R.N.I. NO.HIN/2002/8718 www.akshnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष 19, अंक-17
1 से 15 जून 2021
पृष्ठ-48
मूल्य 25 रूपये

- उमा भारती की राह आसान नहीं!
- मध्यप्रदेश में 2-2 मोर्चों पर जंग

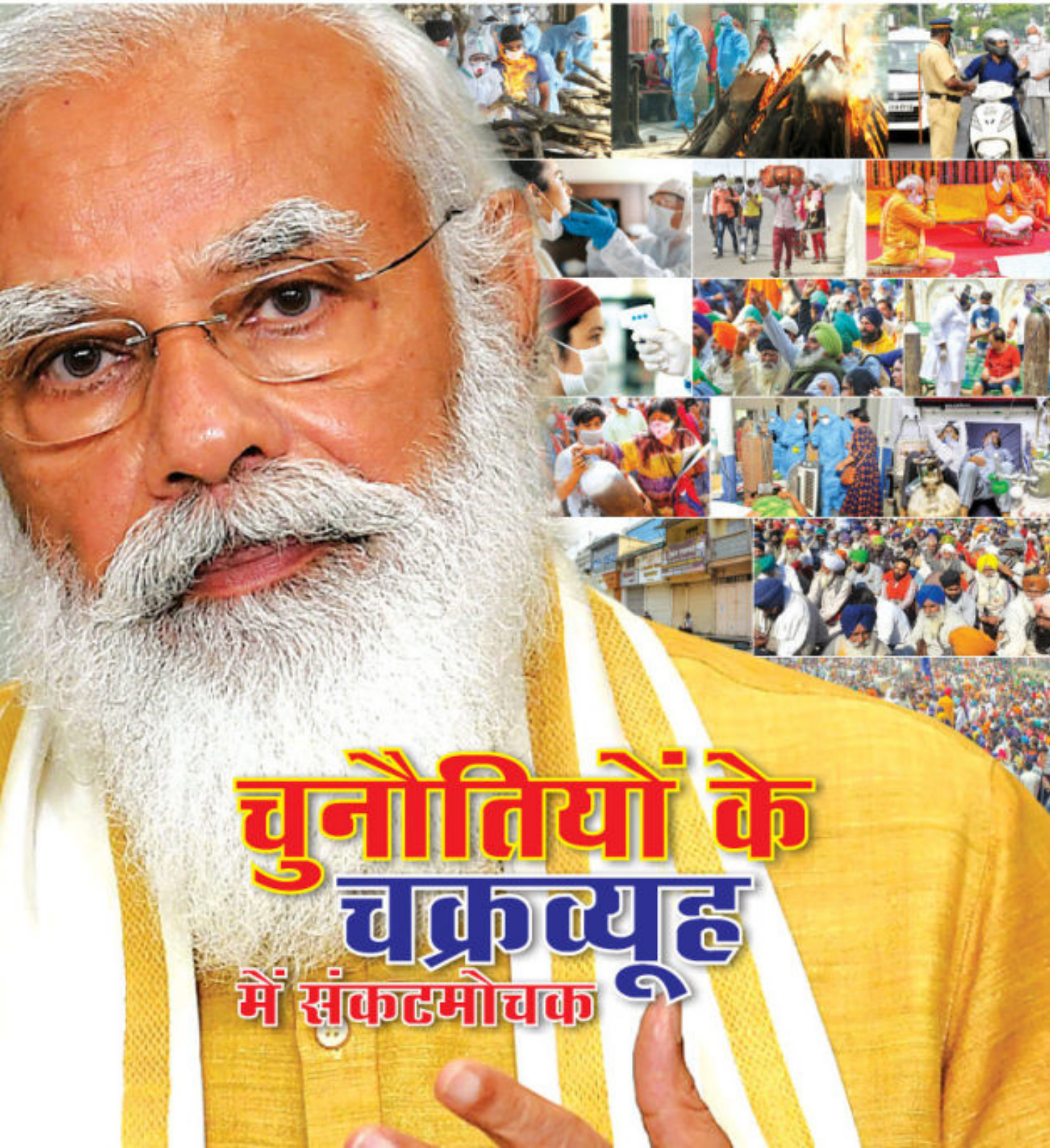

चुनौतियों के चक्रव्यूह में संकटमोचक

मध्यप्रदेश शासन

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

आत्मनिर्भर भारत के लिये आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

आत्मनिर्भरता के स्तंभ

भौतिक अधोसंरचना

- अटल प्रोग्रेस-वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र का विकास।
- सभी ग्रामीण घरों में 1.03 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन की परियोजना।
- 60 सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, इससे 60 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का विस्तार प्रस्तावित।
- 24 प्रमुख सड़कों का नवीनीकरण।
- 378 शहरों में 3 लाख आवासों का निर्माण।
- टोल प्लाज़ाओं का ऑटोमेशन।
- 2642 कि.मी. की ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
- मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना।
- रुपये 4000 करोड़ से 105 रेलवे ओव्हरब्रिज का निर्माण।
- 750 मेगावॉट की देश की सबसे बड़ी रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना शुरू।

सुशासन

- नागरिकों के लिये 'Ease of Living' के तहत प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
- नागरिकों के लिये एकल डेटाबेस के माध्यम से सेवा प्रदाय।
- सार्वजनिक सेवा के लिये मोबाइल आधारित सुविधा प्रदाय।
- ग्रामों की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे तथा अभिलेख प्रदाय।
- कृषि भूमि के सटीक सर्वेक्षण हेतु नई तकनीक का उपयोग।
- डीम्ड अप्रूवल की सुविधा। समय-सीमा में सेवा प्राप्त नहीं होने पर स्वतः कम्प्यूटर से सेवा प्रदाय।

24x7

स्वास्थ्य एवं शिक्षा

- सी.एम. राइज़ योजना में 9,200 सर्व सुविधा सम्पन्न शासकीय विद्यालयों की स्थापना।
- सभी इंजीनियरिंग तथा ITIs में कैरियर तथा प्लेसमेंट सेल की स्थापना।
- 16 सौ अत्याधुनिक प्रसव केन्द्रों की स्थापना।
- 5100 स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।
- प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना में 40 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 101 करोड़ रुपये की सहायता।
- कोविड के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं एवं जाँच केन्द्रों का विस्तारीकरण।

अर्थव्यवस्था एवं रोजगार

- 'एक जिला-एक उत्पाद' के तहत खेती क्षेत्र के पास ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना।
- प्रदेश में 200 क्षमता के नये उद्यमियों के लिए कार्यस्थल की इंदौर तथा भोपाल में स्थापना।
- 800 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन।
- 'नॉलेज पोर्टल' और 'युवा संवाद' के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करना।
- औद्योगिक विकास हेतु भूमि बैंक नीति।
- भोपाल में 320 करोड़ रुपये लागत के 'ग्लोबल स्किल पार्क' की स्थापना।
- राष्ट्रीय उद्यानों में 'सफर में सफर' योजना के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोज़गार।
- 3 लाख पथ विक्रेताओं को स्वयं के रोज़गार हेतु रुपये 300 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण।
- युवाओं एवं महिलाओं को पर्यटन संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण एवं रोज़गार।

शिवराज सरकार – भरोसा बरकरार

D19065/21

इस अंक में

आर्थिकी

9 | **निवेशकों को भाया मप्र**

कोरोना संक्रमण और आर्थिक मंदी के माहौल के बीच मप्र में निवेशकों ने पहले की तुलना में न सिर्फ ज्यादा निवेश किया, बल्कि रोजगार के मौके भी अधिक बने। पिछले 1 साल में रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या देश...

अवैध खनन

15 | **पोर्टल बंद...अवैध खनन चालू**

प्रदेश में नर्मदा सहित अन्य नदियों से रेत निकलने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। खनिज निगम ने पोर्टल को बंद कर दिया है। इसके बावजूद भी नर्मदा नदी सहित अन्य नदियों में मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। खनिज निगम से मिली जानकारी...

राजरंग

16–17 | **हनी ट्रैप की राजनीति**

सत्ता से लेकर विपक्ष और नौकरशाही तक को झकझोर देने वाला हनीट्रैप मामला एक बार फिर मप्र की सियासत के केंद्र में है। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसकी पेनड्राइव का जिक्र कर भाजपा को संकेत दिए...

बुंदेलखंड

23 | **हीरे के लिए पेड़ों की बलि**

छतरपुर में बकस्वाहा हीरा खदान के लिए काटे जाने वाले 2.15 लाख पेड़ों को बचाने के लिए मप्र समेत देशभर के 1 लाख 12 हजार लोग सामने आ गए हैं। कोरोना को देखते हुए इन सभी ने फिलहाल सोशल मीडिया पर 'सेव बकस्वाहा फॉरेस्ट' कैंपेन चलाया है, लेकिन जैसे ही कोरोना संक्रमण...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

नरेंद्र मोदी की सर्व-शक्तिमान प्रधानमंत्री की जो छवि बड़े जतन से गढ़ी गई थी उसका भेद अब राजनीति के मैदान में भी खुलता जा रहा है। किसान आंदोलन और सीएए-विरोधी प्रदर्शनों से ये साबित हुआ कि कोई समूह चाहे छोटा मगर दृढ़ संकल्प वाला हो तो वो भी इस सरकार के खिलाफ मैदान में डटा रह सकता है। वहीं कोरोना संक्रमण ने संकटमोचक को चुनौतियों के चक्रव्यूह में फंसा दिया है, जिससे पूरी भाजपा अस्त-व्यस्त हो गई है।

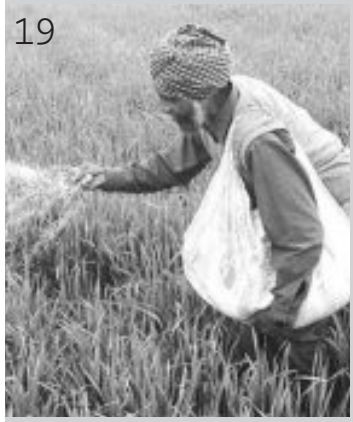
19

20

35

45

राजनीति

30–31 | **झगड़ा नहीं, ये तो रगड़ा है!**

कोई मुकाम हासिल करने से मुश्किल उसे कायम रखना होता है। एक मुकाम हासिल होने के बाद दूसरे की चिंता भी खाए जाती है और अगले मुकाम तक पहुंचने से पहले ही उसे लेकर मन में उमड़ते-घुमड़ते ख्वाब फिक्र बढ़ा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री...

महाराष्ट्र

36 | **रईसी की रेस**

एक जमाना था जब हिंदुस्तान में रईसों की चर्चा होती तो टाटा-बिड़ला का नाम लिया जाता था, वक्त बदला तो रईसों के नाम बदल गए। एक समय ऐसा भी आया, जब रईसों की लिस्ट में अंबानी का नाम ध्रुवतारे की तरह अलग से चमकने लगा। लेकिन साल 2014 में केंद्र की सरकार...

उप्र

37 | **साख का सवाल**

उप्र में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संघ फिक्रमंद है। इसी को लेकर संघ ने गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। बैठक में उप्र में कोरोना के प्रभाव और...

6-7 अंदर की बात
40 विदेश
41 महिला जगत
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

रामदेव और विज्ञानविरोधी राष्ट्रवाद की कॉकटेल

किसी ने ठीक ही कहा है...

हाल यूं है राष्ट्र प्रेम का रंग घोल भी नहीं सकते, आस्तीन के सांपों की पोल खोल भी नहीं सकते।
हां यही है एकतरफा तुष्टिकरण का मतलब, वो गलत कर सकते हैं हम बोल भी नहीं सकते।

कुछ ऐसा ही हाल है योग गुरु रामदेव का। योग और आयुर्वेद के नाम पर उन्होंने अपनी दुकान इस कदर सजा ली है कि वे अपने आप को राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक मान बैठे हैं। राष्ट्रवाद के अतिवाद में वे विज्ञान को भी नकार रहे हैं। इस कारण इन दिनों रामदेव और विज्ञान विरोधी राष्ट्रवाद की कॉकटेल से देश कोरोना महामारी के बीच भूलभुलैया में पड़ा हुआ है। दरअसल, मार्केटिंग का पुराना सूत्र है, प्रचार कैसा भी हो, प्रचार अच्छा है। क्या इसीलिए रामदेव ने, अपने आस्था चैनल पर कोविड-19 के पीड़ितों के ऑक्सीजन के लिए तड़पने का मजाक उड़ाने के जरिए, विवाद को न्यौता दिया है? क्या इसीलिए, उन्होंने स्टुपिड साइंस या बुद्धिहीन विज्ञान कहकर एलोपैथिक चिकित्सा पर हमला किया है और यह झूठा दावा किया है कि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी 10 हजार डॉक्टरों की मौत हो गई है? रामदेव विवाद इसलिए खड़े करते हैं कि इससे खुद उन्हें और वह जो कुछ भी बेच रहे हैं, उसे मुफ्त का प्रचार मिलता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति तथा चिकित्सकीय ज्ञान के क्षेत्र में हो रही प्रगति पर रामदेव का हमला, सिर्फ उनके अपने उत्पाद बेचने का ही मामला नहीं है। यह अपने आप में खतरनाक है क्योंकि यह लोगों को टीकों के और उन दवाओं के खिलाफ करता है, जो उनकी मदद कर सकती हैं। 'प्राचीन ज्ञान' के नाम पर इस अगड़म-बगड़म के प्रचार और भोंडे हिंदू राष्ट्रवाद की दुहाई का योग ही है, जो रामदेव के कारोबारी साम्राज्य को, मिसाल के तौर पर रंग गोरा करने की क्रीम जैसे झूठे उत्पाद बेचने वाले अन्य कारोबारियों से, अलग करता है। एलोपैथी बनाम होम्योपैथी की संज्ञा को पहले-पहले होम्योपैथी के संस्थापक, हहनेमान ने ही गढ़ा था। अब रामदेव एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की लड़ाई को हवा दे रहे हैं। रामदेव की तथाकथित राष्ट्रवादी दुहाई का अर्थ यही है कि आधुनिक दवाओं के मलाईदार बाजार को बड़ी बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के हवाले कर दिया जाए और घरेलू दवाओं के बाजार पर वह अपना इजारा कायम कर ले। भारतीयों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन की क्या जरूरत है, रामदेव से अनुलोम-विलोम सीखना ही काफी है। कोविड-19 का उपचार चाहिए? पतंजलि के बनाई कुछ जड़ी-बूटियों की गोलियों तथा तेलों के भरोसे रहो, जो उसी तरह से इस रोग से आप का उपचार करेंगे, जैसे अपनी क्रीम से लोगों को गोरा बनाते हैं या गर्भ के बच्चों का सुपर सुंदर, सुपुत्र होना सुनिश्चित करते हैं! एलोपैथिक दवाओं या आधुनिक चिकित्सा पर रामदेव का हमला, उन डाक्टरों तथा स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला है, जिन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और लंबे अर्से से यह लड़ाई लड़ रहे हैं। वे इन स्वास्थ्यकर्मियों और उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ाते हैं। इससे भी बुरा यह कि फेफड़ों के गंभीर से प्रभावित होने के चलते, हांफ-हांफ कर सांस लेने की कोशिश करते मरीजों की वह जिस तरह से नकल उतारते हैं, उसके मरीजों की पीड़ा को महसूस करने में भी असमर्थ होने को ही दिखाता है। अगर लोग वाकई रामदेव की इस बात पर विश्वास करेंगे कि कोविड-19 कोई खतरनाक चीज नहीं है और यह बीमारी तो सिर्फ इसलिए हो रही है कि हम सही तरीके से सांस लेना ही नहीं जानते हैं, तब तो इसके गंभीर रूप से संक्रमित रोगी तो मर ही जाएंगे। उन्हें ऑक्सीजन और अन्य जरूरी दवाओं की मदद हासिल होगी, तभी तो उनका शरीर इस बीमारी का मुकाबला कर पाएगा। इसीलिए, रामदेव जो कर रहे हैं वह खतरनाक है।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 17, पृष्ठ-48, 1 से 15 जून, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

प्रकृति के महत्व को समझें

जीवन में प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रबंधन होता है वह प्रकृति को समझकर ही तय किया जा सकता है और जो पारस्परिक संबंध होते हैं गांव, जंगल, नदी, खेत, धारें, कुएं इनकी महत्ता को भी समझना चाहिए। मनुष्यों ने आज तक प्रकृति को समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब समझना होगा।

● **मीनाक्षी मकोडिया,** ग्वालियर (म.प्र.)

माफिया पर शिकंजा

प्रदेश सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर हुए हमलों से सरकार चिंतित है। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। और माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, ताकि आगे से इस प्रकार की घटना न हो सके।

● **पवन सेन,** जबलपुर (म.प्र.)

किसान की परेशानी

पिछले साल के आखिरी समय में बारिश के कारण सोयाबीन की फसल दागी हो गई थी, इसलिए अच्छे बीज किसानों के पास बेहद कम या नहीं के बराबर हैं। जिन 5 से 10 फीसदी किसानों के पास सोयाबीन के बीज हैं वह अभी सोयाबीन बेचना ही नहीं चाहते।

● **राहुल कुमार,** शिवपुरी (म.प्र.)

कोरोना ने बदल दी जिंदगी

कोरोना के इस संक्रमणकाल में सरकार और जनता दोनों के लिए चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन हजारों जानें भी जा रही हैं। इस संकट से निपटने के लिए कड़े अनुशासन, आत्म संयम और संकल्प की बहुत जरूरत है। इस दौर में भी देश–दुनिया में सामाजिक जीवन काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। हमारे खानपान और तौर–तरीकों से लेकर हमारी कार्यशैली बदल रही है। आने वाले समय में इन बदलावों का बड़ा असर पड़ने वाला है। हो सकता है कि इस दौरान हमारी बदली आदतें हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाएं। अब घर से बाहर बगैर मास्क पहने निकलना खुदकुशी करना ही कहलाएगा।

● **प्रवेश जैन,** भोपाल (म.प्र.)

ममता की तारीफ

एक तरफ देशभर में कोरोना की मार झेल रहे लोग पहले से ही परेशान हैं। दूसरी तरफ इस संक्रमणकाल में हुए चुनावों की चर्चा है। देशभर में 5 राज्यों में चुनाव हुए लेकिन सबका ध्यान पश्चिम बंगाल पर ही था, क्योंकि इससे भाजपा और मजबूत होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस चुनाव में किसने किसको वोट दिया–नहीं दिया, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की तारीफ करना होगी कि एक अकेली महिला भले खुद हार गई, लेकिन अपने 213 साथियों को जिता दिया।

● **गौरव राजपूत,** रायसेन (म.प्र.)

उपचुनाव की तैयारी

दमोह उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था। लेकिन भाजपा की रणनीति और दमखम पर अपनों का भितरघात भारी पड़ा। हालांकि दमोह उपचुनाव में हार के बाद अब भाजपा ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भाजपा दमोह उपचुनाव में हुई हार से बेहद चिंतित है। इसलिए अब भाजपा ने आने वाले एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है।

● **दीपक गौतम,** इंदौर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन–1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ–02, 03, एमपी नगर, भोपाल

जगन पर कसता शिकंजा

आंध्र प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। राज्य के युवा मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी इसके लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले जगन ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश एनवी रमन्ना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के कुछ न्यायधीशों पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक पत्र तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बोबड़े को लिखा था। इस पत्र को मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वारा सार्वजनिक भी कराया गया था। अब एनवी रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ बन चुके हैं तो कयासबाजी का दौर चरम पर है कि जगन पर कुछ बड़ी कार्यवाही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गत सप्ताह जगन की पुरजोर खिलाफत कर रहे उनकी पार्टी के बागी सांसद के राजू को जमानत देकर इन कयासबाजियों को गर्मा डाला है। राजू के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर आंध्र पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। के राजू ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि उन्हें न केवल फर्जी मामले गढ़कर फंसाया गया है, पुलिस कस्टडी में उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। कोर्ट ने राजू की बात मान उन्हें जमानत देकर जगन रेड्डी को तगड़ा झटका दे डाला है। दूसरी तरफ गत माह राज्य में हुए पंचायत चुनावों को राज्य उच्च न्यायालय ने रद्द कर डाला है।

स्वामी के निशाने पर मोदी

वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की पहचान एक बेबाक और निडर नेता की है। मोदी-शाह काल में अकेले स्वामी ऐसे सांसद हैं जो खुलकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि भाजपा आलाकमान स्वामी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से लगातार बचता आ रहा है। इस बार स्वामी ने मोदी सरकार से तीन सवालों का जवाब तलाशने को कहा है। बकौल स्वामी सरकार को कोरोना को हराने, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने और लद्दाख से चीन को भगाने की योजना तैयार करनी चाहिए। स्वामी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से इन तीन समस्याओं पर फोकस करने को कहा है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि वर्तमान में इन तीनों सवालों पर सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। गौरतलब है कि स्वामी लंबे अरसे से बागी तेवर अपना चुके हैं। वे लगातार किसान आंदोलन, चीन की घुसपैठ और बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते आ रहे हैं लेकिन भाजपा आलाकमान उनसे न उलझने में ही अपनी भलाई समझ उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही से परहेज करता आ रहा है।

संघ की बढ़ती चिंता

अगले वर्ष चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन चार राज्यों में उप्र, उत्तराखंड, पंजाब, और गोवा में से तीन में भाजपा सत्तारूढ़ है। केवल पंजाब ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। भाजपा के लिए इन तीन राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण उप्र है जहां से लोकसभा के 80 सांसद आते हैं। कोरोना संकटकाल में केंद्र सरकार के साथ-साथ उप्र सरकार की लचर कार्यशैली चलते जनता का आक्रोश इन दिनों चरम पर है। उप्र में योगी आदित्यनाथ के प्रति जनाक्रोश के साथ-साथ भाजपा नेताओं और कार्यकत्ताओं में भी भारी नाराजगी पसर चुकी है। ऐसा ही हाल उत्तराखंड का भी है, जहां चार बरस तक भाजपा आलाकमान ने सत्ता त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथों बनाए रखी। त्रिवेंद्र रावत बेहद खराब मुख्यमंत्री साबित हुए। सत्ता के आखिरी बरस में उन्हें प्रधानमंत्री पद से भाजपा ने हटाकर डैमेज कंट्रोल का प्रयास तो किया है लेकिन हालात उसके प्रतिकूल ही हैं। ऐसे में चिंतित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे आता नजर आ रहा है। गत सप्ताह संघ प्रमुख ने कोरोनाकाल के दौरान सकारात्मक सोच बनाए रखने की बात इसी उद्देश्य के चलते कही। संघ प्रमुख ने सकारात्मकता पर बोलते हुए इशारों-इशारों में केंद्र सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कठघरे में खड़ा कर डाला।

प्रियंका का उप्र से मोहभंग

खबर गर्म है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का अब उप्र की राजनीति से मोहभंग हो चला है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि पंचायत चुनावों के नतीजों के बाद प्रियंका गांधी एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में अपना फोकस बनाने पर विचार कर रही हैं। उप्र में कांग्रेस एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की 'बी' टीम बनने पर विचार कर रही है। दरअसल, लंबे अरसे से कांग्रेस को उप्र में मजबूत करने का प्रयास कर रही प्रियंका गांधी को अब समझ में आ गया है कि प्रदेश में पार्टी संगठन लगभग समाप्त हो चला है और पार्टी का कोर वोट बैंक रहे अल्पसंख्यक और दलित वोटर अब सपा-बसपा में बने रहना चाह रहे हैं। भाजपा से खासा नाराज उच्च वर्ग का वोटर भी कांग्रेस के बनिस्पत समाजवादी पार्टी को जानदार विकल्प मान रहा है। ऐसे में इतना तय है कि 2022 के विधानसभा चुनाव मुख्य रूप से भाजपा बनाम सपा रहने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि वह भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा न होने दे। इसके लिए सपा को महत्व दिया जाएगा।

सुपर सीएम के सहारे

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों मिली करारी हार से तिलमिलाई भाजपा ने अब राजभवन को अपनी शरणस्थली बना डाला है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी सरकार के मध्य रिश्ते पहले से ही खासे तनावपूर्ण थे। राज्यपाल धनखड़ का तृणमूल के विधायकों के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य में राजनीतिक शिष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो चला है। सीबीआई द्वारा दो मंत्रियों समेत चार विधायकों को गिरफ्तार किए जाने से आक्रोशित तृणमूल ने राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ राज्यपाल भी अपनी संवैधानिक मर्यादाओं का स्पष्ट उल्लंघन कर समानांतर सरकार चलाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। राज्य में तेजी से बिगड़ रहे राजनीतिक हालातों के लिए ममता बनर्जी सरकार से कहीं अधिक जिम्मेदार स्वयं राज्यपाल धनखड़ हैं जिन्होंने खुलकर भाजपा के एजेंडे पर काम करना शुरू कर डाला है।

बड़े साहब की आंखों का तारा

मप्र की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों बड़े साहब और उनके एक दोस्त की चर्चा खूब हो रही है। इसकी वजह यह है कि मिलने-मिलाने से परहेज करने के लिए ख्यात बड़े साहब की इन दिनों एक व्यवसायी से खूब पट रही है। आलम यह है कि प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में उक्त व्यवसायी को साहब की आंखों का तारा माना जाने लगा है। मंत्रालय की चौथी मंजिल पर आसीन रहने वाले बड़े साहब अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों से मिलने में भी परहेज करते हैं, लेकिन एक व्यवसायी से उनकी घनिष्टता किसी की समझ में नहीं आ रही है। यहां बता दें कि उक्त व्यवसायी शराब का धंधा करते हैं। साहब पूर्व में शराब की निगरानी करने वाले विभाग में कमिश्नर भी रह चुके हैं। साहब को विभाग और शराब के गठजोड़ की सारी हकीकत मालूम है। लेकिन वर्षों बाद साहब के इस बदले रूप को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है। लोग अपने अंदाज से आंकलन भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो यह कहने से भी नहीं चूक रहे हैं कि बड़े साहब यह बात भलीभांति जानते हैं कि शराब से दोस्ती भले ही कर लो, लेकिन शराब व्यवसायी से दोस्ती हानिकारक होती है। ऐसे में अधिकारियों के लिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार एक शराब व्यवसायी हमारे बड़े साहब की आंख का तारा कैसे बन गया है। लोग इसकी पड़ताल में जुट गए हैं।

सरकारी सुख... निरोगी काया

सरकारी सुख-सुविधाओं के आदी हो चुके कई अफसर रिटायर होने के बाद भी इसी कोशिश में रहते हैं कि उन्हें यह सब बराबर मिलता रहे। प्रदेश में ऐसे कई अफसर हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी सुख-सुविधाओं का भरपूर लाभ प्राप्त किया है। ऐसे ही एक रिटायर अधिकारी दिल्ली में मप्र सरकार के ओंकारेश्वर भवन में अपना बोरिया-बिस्तर डालकर पड़े हुए हैं। कुछ साल पहले प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया के पद से रिटायर हुए ये साहब इलाज के नाम पर सरकारी भवन के एक कक्ष में कब्जा जमाए हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस भवन में पहले एक पूर्व मुख्यमंत्री का कब्जा रहता था। उक्त मुख्यमंत्री जब तक जीवित रहे तब तक भवन उनके हवाले रहा। ऐसा ही कुछ अब रिटायर हो चुके ये साहब कर रहे हैं। यही नहीं दिल्ली स्थिति ग्रीन पार्क में बिजली विभाग का गेस्ट हाउस भी कई सालों तक एक अधिकारी के परिजनों के कब्जे में रहा। बिजली विभाग के प्रमुख सचिव रहे ये साहब जब रिटायर हुए तब भी बिजली विभाग का गेस्ट हाउस का सुख उनके परिजनों ने भोगा। यह गेस्ट हाउस अफसरों की आरामगाह के रूप में ख्यात है। मप्र में सरकारी सुख-सुविधाओं का रिटायरमेंट के बाद भोग करने वाले अफसरों की कमी नहीं है।

दोस्ती का गुणा-भाग

बुंदेलखंड के एक जिले में निर्मित 100 बेड का एक निजी अस्पताल इन दिनों राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, यह अस्पताल भोपाल और होशंगाबाद में स्थित एक अस्पताल की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। लेकिन चर्चा इस बात की है कि एक आईएएस अधिकारी की कृपा से यह अस्पताल आकार ले पाया है। बुंदेलखंड क्षेत्र के एक जिले में बने इस अस्पताल के संचालक जहां होशंगाबाद के रईसों में गिने जाते हैं, वहीं उनके सहयोगी आईएएस होशंगाबाद के कलेक्टर भी रह चुके हैं। इस क्षेत्र में अस्पताल की परिकल्पना के पीछे उक्त आईएएस अधिकारी का सबसे अधिक योगदान है। राजधानी स्थित एक अस्पताल में जब इनकम टैक्स का छापा पड़ा था तो उस छापे में उक्त आईएएस अधिकारी की पत्नी का भी नाम सुर्खियों में आया था। दरअसल, अस्पताल प्रबंधन द्वारा उक्त आईएएस अधिकारी की पत्नी को मोटी तनख्वाह पर रखा गया था। उसके बाद यह तथ्य सामने आया कि अस्पताल प्रबंधन और आईएएस अधिकारी में व्यावसायिक रिश्ते भी हो सकते हैं। लेकिन बुंदेलखंड के एक जिले में निर्मित 100 बेड के अस्पताल को लेकर यह चर्चा जोरों पर है कि इसमें उक्त आईएएस अधिकारी का भी बड़ा योगदान है। जिनकी पत्नी इस अस्पताल की श्रृंखला वाले एक अस्पताल में बिना नौकरी के मोटी तनख्वाह ले रही हैं। अस्पताल पर आईटी के छापे के दौरान लाखों की टैक्स चोरी का मामला सामने आया था।

सत्ता का रसूख

सत्ता का रसूख क्या होता है यह मंत्रियों के साथ ही उनका पूरा परिवार भलीभांति जानता है। यही कारण है कि वर्तमान सरकार में मंत्रियों के नाते-रिश्तेदार सत्ता के रसूख का फायदा उठाकर अपनी झोली भर रहे हैं। चर्चा के अनुसार सरकार के मुखिया से लेकर एक अदने से मंत्री के परिजन भी जमकर कमाई कर रहे हैं। एनबीडीए के एक टेंडर के मामले में साउथ की कंपनियों को टेंडर दिलाने के लिए सरकार के मुखिया के सुपुत्र की सिफारिश का भी सहारा लिया गया है। इसमें हाशिए पर चल रहे एक नेता ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं गेहूं खरीदी के एक बड़े टेंडर को निरस्त कराने के लिए एक मंत्री के बेटे ने कई व्यवसायियों से लाखों रुपए लिए हैं। हालांकि वे टेंडर निरस्त नहीं करा पाए हैं। उधर, कृषि से ही संबंधित एक विभाग में पौधे उत्पादित करने के लिए खरीदे जाने वाले कैरेट का काम मंत्री ने नीलकमल नामक कंपनी को दिलवाने जा रहे हैं। जबकि पात्र अन्य कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वर्तमान समय में प्रदेश में कुछ इसी ढर्रे पर काम चल रहा है, जिससे माननीय और उनके परिजन मालामाल हो रहे हैं।

अफसरों की लीला

आईएएस और आईपीएस अफसरों की लीलाएं अक्सर चर्चा में रहती हैं। इस समय दो आईपीएस अफसरों की चर्चा खूब हो रही है। इनमें से एक अफसर मिनी मुंबई तो दूसरे निमाड़ के एक जिले के एसपी हैं। मालवा क्षेत्र में आने वाले जिले की कमान संभालने वाले आईपीएस अधिकारी बड़े लीलाधारी हैं। इनकी अपनी एक कनिष्ठ महिला अधिकारी के साथ नजदीकी काफी चर्चा में रही है। साहब की लीलाओं की चर्चा पीएचक्यू से लेकर मंत्रालय तक चटखारे लेकर सुनी-सुनाई जाती है। ऐसे में अब साहब ने दिखावे के लिए ऐसी सतर्कता बरतनी शुरू की है, जो इन दिनों चर्चा में है। साहब से मिलने कोई भी महिला आती है तो वह दरवाजा खोलकर उनसे चर्चा करते हैं। यही नहीं वे संत्री को भी वहीं पर रहने का निर्देश दे चुके हैं। लेकिन साहब बूढ़ा बंदर गुलाटी मारना नहीं भूलता कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। इसी तरह निमाड़ क्षेत्र के एक आदिवासी जिले के युवा एसपी पर ऐसा शौक चढ़ा है कि वे वन क्षेत्रों में रहने वाली नई नवेली लड़कियों से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। साहब के इस रूप को देखकर हर कोई दंग है।

आईएमए ने बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग प्रधानमंत्री से की है। लेकिन अरेस्ट तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। सच कहा आपने रामकृष्ण यादव को। भाई और बाप तो विपक्ष को अरेस्ट करने में बिजी हैं।

● **महुआ मोइत्रा**

सागर में लक्षद्वीप भारत का आभूषण है। सत्ता में बैठे अज्ञानी कट्टरपंथी इसे नष्ट कर रहे हैं। मैं लक्षद्वीप के लोगों के साथ खड़ा हूं। प्रफुल्ल पटेल जनविरोधी नियमों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को लोगों की पुकार सुननी चाहिए। और एक नए प्रशासक को वहां भेजना चाहिए। वरना लक्षद्वीप जल उठेगा।

● **अधीर रंजन**

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के विजेता का फैसला एक टेस्ट के बजाय तीन टेस्ट के आधार पर होना चाहिए था। एक टेस्ट के आधार पर विजेता का फैसला सही नहीं होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में भारत की बेहतर बल्लेबाजी ही उसे विजेता बना सकती है। इसलिए टीम को अभी से रणनीति बनाकर काम करना होगा।

● **कपिल देव**

कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत और अमेरिका के बीच मजबूत साझेदारी की बहुत जरूरत है। दोनों देशों ने मिलकर कोविड से निपटने के लिए सबसे ज्यादा फोकस सप्लाई चेन पर किया है। हम चाहते हैं कि वैक्सीन प्रोडक्शन पर भी सहमति जल्द ही बने।

● **एस जयशंकर**

वेबसीरीज महारानी को खूब पसंद किया जा रहा है। मुझे इस वेबसीरीज में काम करने में भी खूब मजा आया। शूटिंग के दौरान जब मैंने मेरे किरदार की फोटो खींचकर मम्मी को भेजी, तब उसे देखकर वे जोर-जोर से हंसने लगीं। दरअसल, मैं अनपढ़ और बिहार के गांव में रहने वाली एक औरत का किरदार निभा रही थी। घर की चार दीवारी में रहकर खाना बनाना, गाय, भैंस, बकरी की देखभाल करना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था। सबको डाउट था कि मैं इस कैरेक्टर में ठीक लग पाऊंगी कि नहीं। लेकिन लोग मुझे मांग में सिंदूर, बिंदी, बिछिया, साड़ी में देखकर खुश हो रहे हैं।

● **हुमा कुरैशी**

वाक्युद्ध

सरकार और प्रधानमंत्री को आज तक कोरोना समझ में नहीं आया है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक बदलती हुई बीमारी है। आप इसको जितना समय और जगह देंगे, ये उतना खतरनाक बनता जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है।

● **राहुल गांधी**

प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे हैं, तब राहुल गांधी ऐसे प्रयासों के लिए नौटंकी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये देश और जनता का अपमान है। राहुल गांधी 2024 तक टीका लगने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन्हें कहना चाहता हूं कि सरकार इसी साल दिसंबर के पहले तक टीकाकरण अभियान पूरा कर लेगी।

● **प्रकाश जावड़ेकर**

निवेशकों को भाया मप्र

कोरोना संक्रमण और आर्थिक मंदी के माहौल के बीच मप्र में निवेशकों ने पहले की तुलना में न सिर्फ ज्यादा निवेश किया, बल्कि रोजगार के मौके भी अधिक बने। पिछले 1 साल में रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या देश में तेजी से बढ़ी है। देश में जहां 1 साल में 37.3 प्रतिशत निवेशक बढ़े, वहीं मप्र में 62 फीसदी से अधिक निवेशक बढ़े हैं। दरअसल, मप्र सरकार ने कोरोना संक्रमणकाल में अधिक से अधिक निवेश करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नीतिगत फैसले लिए हैं। इस कारण निवेशकों के लिए मप्र आकर्षण का केंद्र बना है।

देशभर के साथ मप्र में भी बीते एक साल में निवेशकों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। विशेषज्ञों की मानें तो अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच मप्र में 9.58 निवेशक बढ़े हैं। नए निवेशकों में युवा एवं व्यापारी वर्ग अधिक है। देश में कुल निवेशकों की संख्या अप्रैल 2020 में 4.98 करोड़ थी जो अप्रैल 2021 में बढ़कर 6.84 करोड़ हो गई है। यानी 37.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बड़े राज्यों में मप्र, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में निवेशकों की संख्या में ज्यादा बढ़त हुई है। जबकि छोटे राज्यों में पूर्वी भारत टॉप पर है।

प्रदेश के विभिन्न अंचलों में मांग के अनुरूप 1575 से अधिक हैक्टेयर भूमि पर 20 नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में लगभग 15 हजार करोड़ रुपए के निवेश के साथ 10 हजार व्यक्तियों को रोजगार भी मिल सकेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 1 हजार 325 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का विकास कार्य पूर्ण किया गया। साथ ही 6 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में 1 हजार 323 हैक्टेयर क्षेत्रफल में भी उन्नयन कार्य पूर्ण किया गया है। इससे औद्योगिक इकाइयों को विकसित अधोसंरचना प्राप्त होने के साथ ही प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए इंवेस्टमेंट ड्राइव निर्बाध रूप से चल रही है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रोड-शो, वर्चुअल ईवेंट्स, प्रदर्शनी आदि आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में निवेशकों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश को निवेश के लिए आकर्षक राज्य के रूप में प्रोजेक्ट करने उपलब्ध निवेश की संभावनाओं की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में दो वर्चुअल राउंड टेबल चर्चाएं, दो अंतर्देशीय ईवेंट्स तथा एक अंतर्राष्ट्रीय ईवेंट में भागीदारी और आयोजन किया गया। इस कारण प्रदेश में निवेश बढ़ा है।

देश में निवेशकों की संख्या के लिहाज से दो सबसे बड़े राज्यों की बात करें तो अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र में कुल 1.47 करोड़ निवेशक थे, जो अप्रैल 2020 में 1.08 करोड़ थे। यानी इसमें 36 प्रतिशत की बढ़त हुई है। गुजरात में निवेशकों की संख्या में 1 साल में 22.6 प्रतिशत की बढ़त दिखी है। यहां अप्रैल 2020 में कुल निवेशकों की संख्या 69.51 लाख थी जो अप्रैल 2021 में बढ़कर 85.19 लाख हो गई है।

प्रतिशत के लिहाज से निवेशकों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़त असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना में रही है। मणिपुर में निवेशकों की संख्या एक साल में डेढ़ गुना के करीब बढ़ी है। यहां अप्रैल 2020 में कुल निवेशकों की संख्या 23,657 थी जो अप्रैल 2021 में 58,787 हो गई है। असम में निवेशकों की संख्या अप्रैल 2021 में 7.08 लाख रही है जो एक साल पहले 3.12 लाख थी। यानी 1.26 गुना की बढ़त इसमें देखी गई है।

बड़े राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में कुल निवेशकों की संख्या अप्रैल 2021 में 41.78 लाख रही है जो अप्रैल 2020 में 33.02 लाख थी। यानी इसमें 26.5 प्रतिशत बढ़त रही है। कर्नाटक में कुल निवेशकों की संख्या अप्रैल 2020 में 30.30 लाख रही है जो अप्रैल 2021 में 41.37 लाख रही है। इसमें 36.5 प्रतिशत की बढ़त दिखी है। पश्चिम बंगाल चर्चा में रहा है। विधानसभा चुनावों में यहां खूब जोर आजमाइश दिखी। यहां कुल निवेशक अप्रैल 2021 में 39.02 लाख रही है जो एक साल पहले 31.77 लाख थी। इसमें 22.8 प्रतिशत की बढ़त रही है।

बता दें कि देश में छोटी बचत स्कीम्स जैसे किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस में सबसे ज्यादा पैसा पश्चिम बंगाल से आता है। इसका हिस्सा 15 प्रतिशत है। दिल्ली में कुल निवेशकों की संख्या 36.75 लाख रही है जो एक साल पहले 29.49 लाख थी। यहां पर 24.6 प्रतिशत निवेशक बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश में 37.7 प्रतिशत निवेशक बढ़े हैं। यहां पर कुल 35.40 लाख निवेशक हैं। एक साल पहले इनकी संख्या 25.71 लाख थी।

● **लोकेंद्र शर्मा**

मप्र में 62 प्रतिशत निवेशक बढ़े

मप्र में निवेशकों की संख्या 62 प्रतिशत बढ़ी जो 24.98 लाख रही है। एक साल पहले इनकी संख्या 15.42 लाख थी। राजस्थान में 33.59 लाख निवेशक रहे हैं। यहां निवेशकों की संख्या में 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़त हुई है। एक साल पहले इनकी संख्या 22.31 लाख थी। हरियाणा की बात करें तो यहां भी निवेशकों की संख्या 39.6 प्रतिशत बढ़ी है और यहां कुल 20.71 लाख निवेशक रहे हैं। एक साल पहले 14.83 लाख निवेशक यहां थे। छोटे राज्य तेलंगाना में निवेशकों की संख्या 92.6 प्रतिशत बढ़ी है। यहां कुल 20.13 लाख निवेशक हैं। केरल में 19.15 लाख निवेशक हैं तो बिहार में 16.04 लाख निवेशक हैं। यहां निवेशकों की संख्या 68.8 प्रतिशत बढ़ी है। एक साल पहले यहां 9.50 लाख निवेशक थे। पंजाब में निवेशकों की संख्या 37 प्रतिशत बढ़ी है। यहां पर कुल 16 लाख निवेशक हैं। छत्तीसगढ़ में निवेशकों की संख्या 5.69 लाख रही है जो एक साल पहले 3.76 लाख थी। यानी 51 प्रतिशत की बढ़त दिखी है। इसी तरह सबसे ज्यादा निवेशकों की संख्या बढ़ने वाले इलाकों में मेघालय में 59 प्रतिशत, दादरा एंड नागर हवेली में 53 प्रतिशत, सिक्किम में 42 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 90 प्रतिशत, मिजोरम में 83 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 62 प्रतिशत निवेशक बढ़े हैं। लक्ष्यद्वीप में केवल 461 निवेशक हैं। एक साल पहले यहां 244 निवेशक थे।

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि जनसहयोग और भागीदारी से बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन जंग जीती जा सकती है। शहरों से लेकर गांवों में फैली कोरोना की जानलेवा दूसरी लहर को मप्र में जिस जनभागीदारी से हराया है उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रशंसा कर चुके हैं। अब पूरे देश में मप्र का कोरोना कंट्रोल मॉडल लागू होगा।

2-2 मोर्चों पर जंग

मप्र सहित देशभर में कोरोना की दूसरी लहर जिस तेजी से फैली उसे देखकर ऐसा लगा कि हालात बदतर हो जाएंगे। लेकिन पहली लहर से प्रदेश को बचाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए शासन-प्रशासन के सहयोग के साथ ही जनभागीदारी की नीति अपनाई। इस कोरोनाकाल में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि परिवार के मुखिया की तरह दिखे। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य शासन द्वारा जनभागीदारी के साथ संचालित अभियानों एवं नवाचारों के सु-परिणामों से एक बार फिर मप्र पूरे देश में मॉडल बनकर उभरा है। कोरोना जैसे अदृश्य शत्रु से लड़ने में जो रणनीति मप्र में अपनाई गई, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है और अन्य राज्यों को इसका अनुसरण करने के लिए भी कहा है।

जनता को जागरूक करने के साथ प्रशासनिक तंत्र को कसने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो तेजी दिखाई उसी का परिणाम है कि मप्र में एक बार फिर सरकार कोरोना के विस्तार को रोकने में सफल हो पाई है। लेकिन सरकार को कोरोना महामारी से लड़ने के साथ-साथ ब्लैक फंगस नामक जानलेवा बीमारी के कहर से निपटने के लिए जंग का एक दूसरा मोर्चा भी खोलना पड़ा है। कोरोना से लड़ रही शिवराज सरकार के सामने अब इस नई बीमारी ब्लैक फंगस ने चुनौती बढ़ा दी है। सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए जिलों के अस्पतालों में अलग-अलग वार्ड बनाए जाने के साथ ही जरूरी इंजेक्शन मुहैया कराने, उसकी कालाबाजारी रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री हर दिन समीक्षा बैठक कर रहे हैं।

मप्र में स्वास्थ्य विभाग ने हर संभाग के लिए प्रोटोकाल जारी कर घर-घर सर्वे, इलाज, दवा, निगरानी से लेकर तमाम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिलों के कलेक्टर भी अपने स्तर पर हिदायतें जारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने भी एक प्रोटोकॉल जारी कर ब्लैक फंगस को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि कोविड रोगी के साथ संदिग्ध और ठीक हो चुके व्यक्तियों में डायबिटीज की प्रतिदिन निगरानी रखी जाए। किसी भी स्थिति में स्टेरॉयड और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बायोटिक्स का अनावश्यक अनुचित सेवन नहीं कराया जाए। ऑक्सीजन सपोर्टेड रोगियों के लिए ह्यूमिडिफायर बॉटल में स्टराइल अथवा डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग किया जाए।

मप्र के लिए यह खुशी का प्रसंग है कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में कोरोना जैसी भयानक विपत्ति के समय प्रदेश की जनता सामूहिक रूप से राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। प्रदेश में मैं भी कोरोना वॉलेंटियर्स अभियान ने जन-आंदोलन का रूप ले लिया। देखते ही देखते एक लाख से अधिक कोरोना वॉलेंटियर्स स्व-प्रेरणा से काम करने आगे आए। इन्होंने शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जिस जिम्मेदारी के साथ अपना दायित्व निभाया है, वह तारीफे काबिल है। गांव-गांव में कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश देना, ग्रामीणों को वैक्सीन का महत्व बताना और उसके लिए प्रेरित करना, जरूरतमंदों को भोजन कराना, मरीजों के उपचार में सहयोग करना और जिला प्रशासन के साथ मिलकर

ट्रेसिंग और टेस्टिंग में जनता का सहयोग

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मप्र सरकार ने जनता को सहभागी बनाकर एक मिसाल पेश की है। ट्रेसिंग और टेस्टिंग में जनता का भरपूर सहयोग मिला है। मप्र ने जिस जनभागीदारी मॉडल से कोरोना संक्रमण को कम करने में सफलता पाई है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार सहित कई राज्यों की सरकारों ने सराहा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना प्रबंधन में मप्र द्वारा अपनाए गए जनभागीदारी मॉडल की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई गई हैं। इनमें पक्ष-विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों के लोगों को जोड़ा गया है। यह जनता से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। जनप्रतिनिधियों को जोड़कर हम उनकी ऊर्जा का उपयोग कोरोना के विरूद्ध लड़ाई में कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण गांवों में फैल रहा है। वहां इसका सामना बिना जनशक्ति और जनसहयोग के नहीं किया जा सकता।

कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जो अभी भी जारी हैं। प्रदेश की अधिकांश ग्राम पंचायतों ने स्व-प्रेरणा से निर्णय लेकर सभी गांवों में जनता कर्फ्यू लगाया। ग्रामीणों द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण संकल्प से अनेक गांव ऐसे हैं, जिनमें कोरोना प्रवेश ही नहीं कर पाया।

उपचार की व्यवस्थाओं के साथ राज्य सरकार ने दिन-प्रतिदिन कोरोना टेस्टिंग के प्रतिशत को भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री का कहना है कि कोरोना टेस्ट हर नागरिक का अधिकार है। जो भी चाहेगा उसका निशुल्क टेस्ट कराया जाएगा। एग्रेसिव टेस्टिंग के लिए शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेस्टिंग यूनिट भी कार्य कर रही है। साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे किल कोरोना अभियान-3 में घर-घर जाकर सर्वे का कार्य किया जा रहा है।

कोरोना ने अनेक परिवारों को कभी न भूलने वाला दर्द दिया है। इसने कई परिवारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है तो हजारों परिवार ऐसे भी हैं जिनके सिर से मुखिया का साया उठ गया है। छोटे बच्चों को छोड़कर माता-पिता दोनों चले गए तो कई जगह मासूम बच्चों के साथ मां अकेले बच गई है। भरण-पोषण का पूरा दारोमदार उसके कंधे पर आ गया है। चाहे सरकारी कर्मचारी हों या आम आदमी, सब पर यह विपदा समान रूप से कहर बरपा रही है। सहानुभूति के शब्द जितने कहे जाएं लेकिन यह सच है कि इससे दुखों पर पहाड़ खत्म नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि संबल और सहयोग के लिए सरकार और समाज दोनों खड़े हों। हमारी सामाजिक संरचना में यह कोई रस्म नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अच्छी बात यह है कि मप्र सरकार ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। पहली बार कोरोना योद्धा का दायरा बढ़ाकर उन छोटे सरकारी या अर्द्धसरकारी या सहकारी कर्मचारियों को भी जोड़ा गया है जो किसी भी रूप में इसकी परिभाषा में नहीं आते थे।

यह एक तथ्य है कि कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए दिन-रात मैदानी मोर्चा संभाल रहे कर्मचारी भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। शिक्षक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी,

पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सहकारी संस्थाओं के साथ कई अन्य विभागों के अनेक कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के प्रयास में जिंदगी की जंग हार गए। उनके न रहने पर परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है लेकिन इनमें से अधिकतर संवर्गों की मदद का कोई इंतजाम नहीं था। उन्हें न कोरोना योद्धा की सुविधाएं मिल पा रही थीं और न कोई अन्य सहायता। चौतरफा संकट से घिरे इन परिवारों की सुध अब राज्य सरकार ने ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर इन परिवारों के लिए पहली बार सरकार ने नीतिगत व्यवस्था करके अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण पेश किया है।

प्रदेश की लगभग 8 करोड़ जनता के लिए सदैव अभिभावक की भूमिका में रहने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकटकाल में गरीब एवं जरूरतमंदों के लिए प्रदेश का खजाना खोल दिया। मुख्यमंत्री चौहान ने कोरोना संक्रमण से प्रभावित ऐसे परिवारों के प्रति पूरी संवेदनशीलता अपनाई, जिनके परिवार में कमाने वाला और पालन-पोषण करने वाला सदस्य जीवित नहीं बचा। ऐसे परिवारों के लिए अभिभावक की भूमिका निभाते हुए मुख्यमंत्री ने 5 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का निर्णय लिया। प्रदेश में गरीब परिवारों को तीन माह का निशुल्क राशन दिया जा रहा है। प्रदेश के 6 लाख 10 हजार शहरी पथ विक्रेताओं के खाते में 61 करोड़ की राशि अंतरित की गई। संबल योजना के 16 हजार 844 हितग्राहियों के खातों में 379 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का अंतरण किया गया। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 75 लाख किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए अंतरित किए। प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया तथा सहरिया वर्ग की 2 लाख 18 हजार 593 महिलाओं को 21 करोड़ 85 लाख 93 हजार रुपए की पोषण आहार अनुदान राशि अंतरित की गई। प्रदेश के 27 लाख 35 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को 191 करोड़ 44 लाख रुपए की पारिश्रमिक राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री चौहान ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को संबल योजना में शामिल करने की घोषणा भी की है।

मप्र के कोरोना मॉडल को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आइडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है। इस मॉडल से मप्र में पॉजिटिविटी रेट में तेजी से कमी आई है और रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ा रहा है।

● **कुमार राजेन्द्र**

मप्र में कर्मचारियों के लिए खोला खजाना

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकटकाल में कर्मचारियों के हित में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना भी लागू की है। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना समस्त नियमित स्थाईकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स के रूप में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए लागू की गई है। योजना के अंतर्गत इन सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना में राज्य में कार्यरत समस्त, नियमित, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स, अन्य शासकीय सेवक, सेवायुक्तों की कोविड-19 के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना महामारी के काल में जन-जागृति का धर्म निभा रहे प्रदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सभी अधिमान्य या गैर-अधिमान्य मीडियाकर्मी और संपादकीय विभाग के कर्मचारियों तथा इनके परिवार के सदस्यों के कोरोना से प्रभावित होने पर उनका निशुल्क उपचार करवाने का निर्णय भी लिया है।

मप्र में आगामी समय में एक लोकसभा सीट के साथ ही तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा की कोशिश है कि संगठन में खाली पड़े पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए।

खाली पद जल्द भरेंगे

भाजपा में एक बार फिर संगठन में रिक्त पदों पर नियुक्तियों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जून में संगठन में प्रमुख पदों पर नियुक्तियों का दौर शुरू हो सकता है। इन नियुक्तियों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। बताया जाता है कि आलाकमान ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा को इसके लिए फ्री हैंड दे दिया है। दरअसल प्रदेश की कमान संभालने के बाद शर्मा करीब एक साल बाद किश्तों में अपनी आधी-अधूरी टीम गठित कर सके हैं। अभी उनकी टीम में कार्यसमिति सदस्यों के अलावा प्रवक्ताओं और मीडिया पैनालिस्टों की नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। इन पदों पर होने वाली नियुक्तियों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। कार्यसमिति सदस्यों को लेकर खासतौर पर इंतजार है। इसकी वजह है ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को लेकर लगने वाले कयास। माना जा रहा है कि इन सदस्यों की नियुक्तियों में सबसे बड़ी दिक्तत नामों को लेकर आ रही है।

प्रदेश में भाजपा की सरकार बने हुए एक साल से अधिक हो गया है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का भी संगठन व सत्ता में भागीदारी को लेकर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। माना जा रहा है कि इस सूची को अंतिम रूप देने में दूसरी बड़ी दिक्कत उन नामों को लेकर हो रही है, जिनके नाम पहले मंत्री पद के मजबूत दावेदारों में थे और उसके बाद अब निगम मंडल के लिए भी लिए जा रहे हैं। दरअसल सरकार अब तक राजनीतिक नियुक्तियां नहीं कर सकी है। इसकी वजह से यह मामला टलता ही जा रहा था। हालांकि बताया जा रहा है कि अब भी प्रदेश प्रवक्ताओं के नामों को लेकर फंसा पेंच पूरी तरह से नहीं सुलझ पाया है।

दरअसल प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्तियों के बाद जिस तरह से प्रदेश में उपचुनाव और देश के पांच राज्यों में हुए आम चुनावों में प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं की तैनाती कर दी गई थी, उसकी वजह से भी इसमें देरी हुई है। पहले प्रदेश की 29 सीटों पर उपचुनाव और फिर दमोह सीट पर हुए उपचुनाव की वजह से भी देरी हुई है। इसके अलावा पांच राज्यों के आम चुनाव में भी प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण संगठन नेताओं को भेजे जाने की वजह से इस पर काम नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि चुनावों से लौटने के बाद इन नियुक्तियों को लेकर प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा की प्रदेश संगठन महामंत्री, सह संगठन मंत्री और मुख्यमंत्री से भी बात हो चुकी है।

भले ही संगठन द्वारा भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष की कमान चार माह पहले वैभव पंवार को दी जा चुकी है, लेकिन वे भी अब तक अपनी टीम की घोषणा नहीं कर सके हैं, जबकि यह सहयोगी संगठन भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वजह है प्रदेश में इस संगठन की कोई भी गतिविधि नजर नहीं आ रही है। खास बात यह है कि इस सहयोगी संगठन की भूमिका आंदोलन से लेकर सामाजिक गतिविधियों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर इसका गठन कर लिया गया होता तो यह संगठन कोरोना जैसी महामारी में लोगों की मदद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। सत्ता में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले सिंधिया के अन्य समर्थकों को भी संगठन के रिक्त पदों व निगम मंडलों में नियुक्तियों का बेसब्री से इंतजार बना हुआ है। टीम वीडी में शामिल मुकेश चौधरी को छोड़ दिया जाए तो एकमात्र सिंधिया समर्थक मदन कुशवाहा को ही शामिल किया गया है। उन्हें प्रदेश मंत्री बनाया गया है। इसी तरह से सिंधिया समर्थक कोई भी नेता संगठन में जिला व मंडल स्तर तक के किसी पद पर नियुक्त नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि कुछ सिंधिया समर्थकों को प्रदेश कार्यसमिति सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है।

● **अरविंद नारद**

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा सरकारी लाभ

मप्र से कोरोना महामारी का खात्मा करने के लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने संगठन में नया सिस्टम बनाया है। दरअसल अब सरकार के काम में संगठन मजबूती से जुटेगा। इसमें गांवों में फैल रहे संक्रमण को लेकर खास रणनीति बनाई गई है। इसके तहत जहां अब सांसदों को सीधे सरपंचों से जोड़ने का काम किया गया है, वहीं भाजपा कार्यकर्ता गांवों में घर-घर जाकर मरीजों की पहचान करने के लिए सर्वे करेंगे। यह सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के सभी गांवों के सरपंचों से लगातार चर्चा करेंगे और कोरोना संक्रमण को गांव के बाहर ही खत्म करने के लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। सर्वे के लिए घर-घर जाने वाली टीम को यदि कोई संक्रमित मिलता है तो उसे क्वारैंटाइन सेंटर पहुंचाने में मदद करेगा। साथ ही उसे आवश्यक दवाइयां, किट दिलवाने में भी मदद करेगा। प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पदाधिकारियों से कहा कि चूंकि भाजपा का नेटवर्क गांव-गांव तक है। करीब एक करोड़ सदस्य हैं। इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर संक्रमण का फैलाव रोकने और हर मरीज को समुचित इलाज दिलाने में होना चाहिए। वहीं इस बात की निगरानी हमारे कार्यकर्ता करें कि आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं की टीम हर घर तक पहुंचे और परिवार के सभी सदस्यों की जांच हो। यह जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ताओं को ही निभाना है।

उमा भारती की राह आसान नहीं!

गंगा के बहाव में किस तट पर मिलेगा किनारा

भाजपा की राजनीति में उमा भारती के संरक्षक के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी बड़ी भूमिका में रहे हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के मामले में जो प्रमुख आरोपी रहे हैं, उनमें उमा भारती भी हैं। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी भाजपा नीत सरकार में उमा भारती प्रमुख भूमिका में रहीं। उन्हें गंगा नदी के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे जल संसाधन विभाग की मंत्री बनाई गईं। उमा भारती ने अपनी भावी भूमिका को लेकर एकसाथ 30 ट्वीट किए। इनमें अधिकांश ट्वीट में गंगा नदी का जिक्र है। उमा भारती ने एक ट्वीट में लिखा, 'प्रधानमंत्री ने बनारस में कहा था कि मुझे गंगा ने बुलाया है तथा केदारनाथ में कहा था कि मुझे हिमालय ने भेजा है।' साध्वी भारती ने अपने ट्वीट में कुछ पुराने घटनाक्रमों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि गंगा की पदयात्रा करने के लिए वर्ष 2019 का चुनाव न लड़ने का फैसला किया। एक ट्वीट में उन्होंने पार्टी को चुनाव जिताने के लिए दिए गए योगदान का भी जिक्र किया। चुनावी राजनीति की मुख्यधारा में आने के लिए उमा भारती ने गंगा की धारा का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि वे वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। चुनाव से पहले पार्टी संगठन में अपना योगदान देना चाहती हैं।

हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा माने जाने वाली साध्वी उमा भारती चुनावी राजनीति में वापस लौटना चाहती हैं। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली 10 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने से उनका चुनावी सफर शुरू हुआ था। उमा भारती लगभग आठ माह ही मप्र की मुख्यमंत्री रह पाईं। वे राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। उनके नेतृत्व में ही वर्ष 2003 में भाजपा की मप्र की सत्ता में वापसी हुई थी। पार्टी ने राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम सामने रखकर चुनाव लड़ा था। पार्टी के कई दिग्गज इससे हाशिए पर चले गए थे। उमा भारती के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा की रिकार्ड सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कर्नाटक के हुबली की एक अदालत द्वारा 10 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के कारण अगस्त 2004 में उमा भारती ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हुबली का मामला तिरंगा फहराने से जुड़ा था। उमा भारती मुख्यमंत्री का पद छोड़कर देश व्यापी तिरंगा यात्रा पर निकल पड़ी थीं। पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी बाबूलाल गौर को सौंप दी थी। पार्टी में विरोधियों के हावी होने के कारण उमा भारती मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कभी वापसी नहीं कर सकी थीं। गौर के स्थान पर शिवराज सिंह चौहान को राज्य का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी के नाम से अलग पार्टी बना ली थी। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कोई चमत्कार नहीं कर सकी।

पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की आलोचना के कारण उन्हें दूसरी बार कार्यवाही का सामना करना पड़ा था। पार्टी में उनकी वापसी इस शर्त पर हुई थी कि वे मप्र की राजनीति में वापसी नहीं करेंगी। उमा भारती ने इस शर्त को स्वीकार किया था। वे महोबा जिले की चरखारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ीं और विधायक बनीं। 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी उमा भारती के जरिए उप्र की सत्ता में आने की उम्मीद लगाए हुए थी लेकिन सफलता नहीं मिली। उमा भारती लंबे समय से मप्र की राजनीति में वापसी की कोशिश कर रही हैं। माना यह भी जाता है कि मप्र की राजनीति में वापसी के लिए ही उन्होंने वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव न लड़ने का दांव खेला था। इससे उप्र से पीछा छूट गया?

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर हजारों लोगों की जान ले चुकी है। सैकड़ों शव गंगा की धारा के साथ बहते दिखाई दे रहे हैं। आरोप यह लग रहा है कि यह शव उप्र से बहकर बिहार पहुंचे हैं। उमा भारती ने कोरोना से हो रहीं मौतों का कोई जिक्र अपने ट्वीट में नहीं किया। लेकिन एक ट्वीट बेहद दिलचस्प है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गंगा एवं हिमालय के संबंध में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं कर रही किंतु इस विषय पर ठीक से एवं विस्तार से मैंने मोदी, अमित शाह और हमारे वर्तमान संगठन मंत्री बीएल संतोष को प्रमाण सहित समझाया है। उमा भारती के लिए उप्र की राजनीति में वापस जाना आसान नजर नहीं आता है। मप्र कांग्रेस कमेटी के विचार विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता कहते हैं कि भाजपा के लिए उमा भारती की अब कोई उपयोगिता नहीं बची है। उमा भारती का भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख पर निर्भर करेगा। उमा भारती ट्वीट से भी यही संकेत मिलते हैं। उन्होंने लिखा कि मेरा आज भी प्रधानमंत्री पर भरोसा है। उन्होंने यह भरोसा गंगा नदी के संदर्भ में व्यक्त किया है लेकिन इसके कई राजनीतिक अर्थ हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही उमा भारती मप्र की राजनीति में वापस अपने पैर जमाना चाहती हैं। 28 सीटों के विधानसभा उपचुनाव के अलावा दमोह उपचुनाव में प्रचार में भी साध्वी सक्रिय दिखाई दी। राज्य में जहरीली शराब से जब लोगों की जान गई तो साध्वी ने शराबबंदी के लिए आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। यद्यपि बाद में वे इस दिशा में सक्रिय दिखाई नहीं दी हैं। भाजपा प्रवक्ता आशीष अग्रवाल कहते हैं कि उमाजी का गंगा और हिमालय प्रेम किसी से छुपा नहीं है। उमा भारती लोधी समुदाय से हैं। इस समुदाय के प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री हैं। मप्र और उप्र के बुंदेलखंड इलाके में लोधी वोटर काफी निर्णायक हैं। राज्य भाजपा में इन दिनों दमोह उपचुनाव में मिली हार पर बवाल मचा हुआ है। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया सहित कई भाजपा पदाधिकारियों पर चुनाव हराने के आरोप लग रहे हैं। पार्टी में चल रही उठापटक के बीच उमा भारती के ट्वीट से हलचल तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

● **प्रवीण कुमार**

मप्र में इस साल रिकार्डतोड़ धान की खरीदी हुई है। लेकिन मिलर्स और सरकार के बीच चल रही खींचतान के कारण धान की मिलिंग नहीं हो पा रही है। इस कारण प्रदेश के कई जिलों में धान खुले कैंप में रखे हुए हैं। कई जगह बारिश के कारण धान भीग गए हैं, जो सड़ने की कगार पर आ गए हैं।

धान की मिलिंग ठप

खून-पसीना बहाकर देशवासियों का पेट भरने के लिए अन्नदाता उपज तैयार करता है, लेकिन उसकी सुरक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है और ना ही समय पर मिलिंग। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि धान की अब तक 80 फीसदी मिलिंग हो जानी थी, लेकिन महज 14 प्रतिशत हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि बारिश आदि के कारण ओपन कैंपों में रखी लाखों क्विंटल धान सड़ रही है। जिम्मेदार विभाग नागरिक आपूर्ति निगम जिसके जिम्मे मिलिंग की जवाबदारी है उसका तर्क है कि चावल रखने जगह नहीं है इसलिए मिलिंग नहीं हो रही।

जून माह तक हर हाल में मिलिंग हो जानी चाहिए। जनवरी, फरवरी व मार्च में 80 फीसदी मिलिंग हो जानी थी, लेकिन नहीं की गई। अभी भी केंद्रों व गोदामों में लाखों मीट्रिक टन धान की मिलिंग बाकी है। बता दें कि 2019-20 के धान की भी अभी तक पूरी मिलिंग नहीं हुई है, जबकि 31 मार्च को समय सीमा खत्म हो गई है। फिर से टेंडर हुआ है, लेकिन कई माह बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। टेंडर में दूसरे राज्यों को भी बुलाया गया था, लेकिन गुणवत्ता में कमी के कारण बाहरी राज्यों के मिलर्स ने रूचि नहीं दिखाई। वहीं प्रदेश के मिलर्स का कहना है कि 10 रुपए प्रति क्विंटल मिलिंग चार्ज केंद्र सरकार देती है, 25 रुपए राज्य सरकार प्रोत्साहन के रूप में मिलिंग देती है। 35 रुपए क्विंटल मिलता है, जिससे मिलर्स काम नहीं कर रहे हैं। मिलर्स के हाथ खड़ा करने पर भी विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। मप्र में धान की मिलिंग को लेकर अन्य राज्यों ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। प्रदेश के मिलर्स द्वारा आनाकानी करने के बाद सरकार को उम्मीद थी कि उप्र, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मिलर मिलिंग के लिए आगे आएंगे। इसके लिए निविदा भी निकाली पर अब तक कोई मिलर आगे नहीं आया है। दरअसल, झगड़ा एक क्विंटल धान से चावल बनाकर देने की मात्रा को लेकर है। मिलर एक क्विंटल धान से 67 किलोग्राम चावल बनाकर देने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी मांग है कि इसे 12 किलो घटाकर 55 किलोग्राम किया जाए पर यह राज्य सरकार के स्तर पर तय नहीं हो सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति लगेगी, जो संभव नहीं है क्योंकि मप्र को छूट देने से अन्य राज्यों में भी यह मांग उठ सकती है। यही वजह है कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने प्रदेश के ही मिल संचालकों से दोबारा मिलिंग के लिए दरें बुलाई हैं। अब मिलर 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि मांग रहे हैं।

प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पिछले साल रिकॉर्ड 39 लाख टन धान की खरीद की थी। 6 लाख टन धान और पहले की रखी हुई है। इसकी मिलिंग कराने के लिए निगम ने निविदा निकालकर मिल संचालकों से दरें बुलाई थीं पर मिलर सरकार के प्रावधान पर मिलिंग के लिए तैयार नहीं हुए। मप्र मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल का कहना है कि इस बार धान में टूटन अधिक है। एक क्विंटल धान से 67 किलोग्राम चावल बनाकर देना संभव नहीं है। प्रोत्साहन राशि भी कम है। ऐसे में मिलिंग करना घाटे का सौदा है। यही वजह है कि चावल की मात्रा 55 किलोग्राम करने और प्रोत्साहन राशि 100 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग रखी थी पर सरकार तैयार नहीं हुई।

इसे सुलझाने के लिए मंत्रियों की समिति भी बनाई पर बात नहीं बनी और उप्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के मिल संचालकों से मिलिंग कराने के लिए निविदा बुलाने का निर्णय लिया गया। निगम ने निविदा निकाली पर पड़ोसी राज्यों के मिलर भी मौजूदा प्रावधानों के तहत मिलिंग करने के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने भी मिलिंग करने में कोई रूचि नहीं दिखाई। वहीं, धान की टेस्ट मिलिंग के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। निगम के प्रबंध संचालक अभिजीत अग्रवाल का कहना है कि अभी 33 लाख टन धान की मिलिंग होना बाकी है। इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। शासन के निर्णय अनुसार निविदा निकालकर अन्य राज्यों के मिल संचालकों को आमंत्रित किया था पर उन्होंने रूचि नहीं दिखाई है। प्रदेश के मिल संचालकों से फिर से मिलिंग के लिए दरें बुलाई हैं। इनका परीक्षण करने के बाद शासन स्तर पर मिलिंग को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

● **विकास दुबे**

25 रुपए बढ़ाई जा चुकी है प्रोत्साहन राशि

सरकार इस बार मिलिंग के लिए प्रोत्साहन राशि में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कर चुकी है। अब मिलर को 50 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस राशि में कुछ और वृद्धि की जा सकती है क्योंकि मिलिंग कराने के लिए यही एकमात्र विकल्प है। प्रदेश में नवंबर से पंद्रह सौ से ज्यादा खरीदी केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (1,868 रुपए प्रति क्विंटल) पर धान की खरीदी शुरू हुई थी, जो 15 जनवरी को समाप्त हो गई। इस दौरान 37 लाख टन धान खरीदी गई। यह प्रदेश में हुई अब तक की धान खरीदी का रिकॉर्ड है। यह खरीदी भी तब हुई जब देश में यह माहौल बनाया जा रहा है कि नए कृषि कानूनों के आने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद हो जाएगी। जबकि, केंद्र से लेकर राज्य सरकार साफ कर चुकी है कि न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद होगी और न ही मंडियां। इसके प्रमाण भी मप्र में किसानों को मिल चुके हैं। पिछले दिनों ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने नरसिंहपुर जिले के साईंखेड़ा में उप मंडी की शुरुआत की है। हालांकि, सरकार को धान की मिलिंग में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिलर्स एक क्विंटल धान से 67 किलोग्राम की जगह 55-57 किलोग्राम चावल देने की बात कर रहे हैं।

पोर्टल बंद...अवैध खनन चालू

प्रदेश में नर्मदा सहित अन्य नदियों से रेत निकलने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। खनिज निगम ने पोर्टल को बंद कर दिया है। इसके बावजूद भी नर्मदा नदी सहित अन्य नदियों में मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है।

खनिज निगम से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 19 जिलों का पोर्टल बंद किया गया है। जिसमें बताया गया है कि जिलों की कंपनियों ने नियम अनुसार रॉयल्टी जमा नहीं की है। आरकेटीसी कंपनी के द्वारा तवा और नर्मदा में खनन का काम किया जा रहा है, जबकि खनिज निगम के द्वारा सभी रेत खदानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अवैध रेत खनन को लेकर गत दिनों रेत माफिया के गुर्गों और रेत खनन कंपनी के कर्मचारियों में जमकर बवाल हुआ। माफिया के गुर्गों ने कर्मचारियों को लाठियों से पीट-पीट कर लहुलुहान कर दिया। इतना ही नहीं फायरिंग भी की। माफिया के गुर्गों पर दो कर्मचारियों को अगवा करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। लेकिन क्षेत्र में तनाव कायम है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दूधी नदी किनारे स्थित रेत खदान पर अवैध कब्जे और खनन को लेकर लंबे समय से होशंगाबाद जिले में सक्रिय आरकेटीसी कंपनी के लोग सक्रिय हैं। वे सालीचौका क्षेत्र के कुछ पुराने खननकर्ताओं को प्रश्रय देकर जिले की शांति में खलल पैदा करने में जुटे हैं। पहले भी बेदर खदान से अवैध रास्ते को लेकर विवाद हो चुका है। उस वक्त भी पुलिसबल की तैनाती तक करनी पड़ी थी। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों मालहन बाड़ा की रॉयल्टी पर्ची पर होशंगाबाद की रेत सप्लाई का मामला सुर्खियों में आया तभी से होशंगाबाद के माफिया को लेकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही थी। क्षेत्रीय पुलिस भी इससे अनजान न थी। बावजूद इसके पुलिस ने कोई एहतियाती कदम नहीं उठाया। नतीजतन बीती रात दूधी नदी खदान में हुई फायरिंग और अपहरण की घटना है। बताया जा रहा है कि केकरा गांव में धनलक्ष्मी के कर्मचारियों को जानकारी लगी कि कुछ लोग दूधी खदान से रेत चोरी कर रहे हैं तो कंपनी के कर्मचारी इसकी पड़ताल करने पहुंचे। कर्मचारियों को देख माफिया के गुर्गों ने फायरिंग कर दी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नर्मदा नदी की ज्यादातर रेत खदान चोरी छुपे संचालित की जा रही हैं जिसमें बुल्डोजर और पोकलेन मशीन से अवैध उत्खनन दिन-रात किया जा रहा है। वहीं टेंडर प्रक्रिया के अनुसार रेत नीति के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कंपनी के द्वारा डंपर और हाईवा में ओवरलोड रेत भरी जा रही है। होशंगाबाद और सीहोर से लगी कुछ रेत खदानों की जानकारी ली गई तो बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों से लगी रेत खदानों में चोरी-छुपे नर्मदा में खनन किया जा रहा है। तवा पुल, होरियापीपर, जलालपुर, रजौन के कुछ ग्रामीणों का कहना है कि नदी और नर्मदा में अवैध उत्खनन बुल्डोजर और पोकलेन मशीनें द्वारा की जाती है। जिसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी जाती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अवैध उत्खनन के मामलों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि रेत का अवैध करोबार नहीं रोका गया तो जल्द ही सभी ग्रामीण एकत्रित होकर मशीनों की धरपकड़ करेंगे व कलेक्टर को सौंपने का काम करेंगे। कागजों में भले ही रेत खदानें बंद हैं। लेकिन खदानों की हकीकत कुछ और ही है। कंपनी की ज्यादातर रेत खदानों में दिन-रात खनन का काम चल रहा है। जिससे सरकार की आय को नुकसान पहुंच रहा है। रेत के घाटों पर प्रतिदिन सैकड़ों डंपर हाइवा से रेत परिवहन किया जा रहा है और स्टॉक की वैद्य रॉयल्टी दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि यह खेल कंपनी तक ही सीमित है इस खेल की जानकारी प्रशासन को है लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालातों की वजह से रायसेन, मंदसौर, आलीराजपुर, उज्जैन, आगर-मालवा जिलों की रेत खदानों की नीलामी अटक गई है। अब ये खदानें बारिश बाद नीलाम होंगी। खनिज निगम इसकी तैयारी में जुटा है। इनमें से रायसेन, मंदसौर और आलीराजपुर की खदानों के ठेके रॉयल्टी की दूसरी किश्त जमा न करने के कारण दो महीने पहले निरस्त किए गए हैं। जबकि उज्जैन और आगर-मालवा की खदानों को नीलामी के पांचवें प्रयास में भी ठेकेदार नहीं मिले हैं। अब इन खदानों में रेत के भंडारण का फिर से आंकलन कराया जा रहा है। कमलनाथ सरकार ने जिलों की रेत खदानों का समूह बनाकर दिसंबर 2019 में नीलामी की थी। इससे सरकार को करीब 1400 करोड़ रुपए राजस्व मिलना था, पर काफी महंगी खदानें लेने के कारण ठेकेदार चला नहीं पा रहे हैं। पहले प्रदेश की सबसे महंगी नर्मदापुरम (होशंगाबाद) जिले की रेत खदान ठेकेदार ने छोड़ी और इस साल रायसेन, मंदसौर और आलीराजपुर के ठेकेदार रॉयल्टी राशि जमा नहीं कर पाए। इसलिए तीनों जिलों के ठेके निरस्त करने पड़े। खनिज निगम अप्रैल-मई में नीलामी प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में था, पर इन महीनों में कोरोना की वजह से सभी गतिविधि ठप रहीं। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश प्रक्रिया में आड़े आ जाएंगे। 30 जून से तीन महीने के लिए नदियों से रेत निकालना प्रतिबंधित रहेगा। इसलिए नीलामी चार महीने के लिए टल गई है।

● **बृजेश साहू**

रेत के भंडार का अध्ययन करेंगे कलेक्टर

दो साल में पांच बार नीलामी करने के बाद भी आगर-मालवा और उज्जैन की खदानें नीलाम नहीं हुईं। ठेकेदारों का कहना है कि सरकार ने खदानों का जो मूल्य तय किया है, उतनी भी रेत नहीं है। इसलिए छठवीं बार नीलामी प्रक्रिया शुरू करने से पहले दोनों जिलों के कलेक्टरों से रेत भंडारण का आंकलन करने को कहा है। प्री-मानसून बारिश शुरू होने से पहले ठेकेदार रेत का भंडारण करना चाहते हैं। प्रदेशभर में ज्यादातर ठेकेदारों ने भंडारण की अनुमति के लिए आवेदन लगा दिए हैं। दरअसल, बारिश शुरू होते ही नदी तट से रेत भरना मुश्किल हो जाएगा और 30 जून से तीन महीने के लिए घाट बंद हो जाएंगे। ऐसे में ठेकेदार भंडारण करके रखेंगे, तभी काम चल पाएगा।

हनी ट्रैप की राजनीति

राजनीति में शह-मात का खेल चलता रहता है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की प्रेमिका द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। भाजपा को जहां कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया, वहीं कांग्रेस इस मामले में अपने विधायक को बचाने की कवायद में जुट गई। इसी कवायद में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा और सरकार पर दबाव बनाने के लिए कह दिया कि हनीट्रैप कांड की पेनड्राइव मेरे पास भी है। उनका यह कहना राजनीति में एक और बड़ा बवाल खड़ा कर गया है। कमलनाथ ने ऐसा क्यों कहा, अब इसको लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

सत्ता से लेकर विपक्ष और नौकरशाही तक को झकझोर देने वाला हनीट्रैप मामला एक बार फिर मप्र की सियासत के केंद्र में है। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसकी पेनड्राइव का जिक्र कर भाजपा को संकेत दिए थे कि वह उमंग सिंघार के मामले में नर्म रुख अपनाए, लेकिन कोरोना पर दिए विवादित बयान से खुद घिर गए। उन्होंने इसे इंडियन वैरिएंट कहा तो भाजपा ने थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। हालांकि नाथ के बचाव में आई कांग्रेस ने कोरोना के आंकड़ों में हेरफेर के आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ एफआईआर के आवेदन थानों में सौंप दिए हैं।

दरअसल, मामले की शुरुआत हुई थी कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के आवास पर महिला की आत्महत्या की घटना से, लेकिन दबाव की राजनीति के फेर में तब हनीट्रैप तक पहुंच गई, जब कमलनाथ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इसकी पेनड्राइव उनके पास है। उनके बयान से सियासी गलियारे में सन्नाटा सा खिंच गया, जिसने उन अनुमानों को ही बल दिया कि हनीट्रैप की आंच सियासत से लेकर कई आला अफसरों तक पहुंचती है, जिसमें से कई प्रशासनिक तो कई पुलिस सेवा में हैं तो कुछ सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नाथ का ये दांव सरकार को सिंघार के प्रति नर्म रुख रखने का संकेत माना गया, लेकिन खुद नाथ ही भाजपा को इससे उबरने का मौका दे बैठे, जब उन्होंने कोरोना को इंडियन वैरियंट बता दिया। भाजपा ने इस अवसर को लपक लिया और उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन की रणनीति पर काम शुरू कर दिया।

सबसे पहले भोपाल में ही उनके खिलाफ झूठी खबर फैलाने के तहत एफआईआर करा दी। हालांकि संवैधानिक बाध्यताओं के चलते कांग्रेस भी हनीट्रैप की पेनड्राइव को लेकर सीधा मोर्चा लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वह भी कोरोना पर ही बचाव और आक्रमण की रणनीति अपनाए हुए है। राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा सहित सभी कांग्रेसी कानूनी कार्रवाई कर कमलनाथ पर एफआईआर को चुनौती देने के लिए विमर्श में जुटे हैं।

खास बात ये है कि हनीट्रैप मामले के शोर में सिंघार के आवास पर आत्महत्या का मामला दब गया, जबकि दोनों ही मामलों में जांच कहां तक पहुंची, कार्रवाई की स्थिति क्या है, दोषी कौन है, जैसे कई सवालों के जवाब आज तक सामने नहीं आ सके हैं। हनीट्रैप मामला कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में सामने आया था, जिसकी जांच जोर-शोर से शुरू हुई, आरोपित महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती दौर में जो तेजी दिखी, बाद में वह

कमलनाथ की सफाई पर उठ रहे सवाल

कमलनाथ ने अपनी सफाई में भले ही जोर देकर यह कहा हो कि वे हनीट्रैप पेनड्राइव का जिक्र करके न तो किसी को धमकी दे रहे हैं और न ही इस मामले में कोई राजनीति करना चाहते हैं लेकिन उनके बयान का अंदाज और टाइमिंग देखकर किसी को भी यह निष्कर्ष निकालने में आसानी होगी कि वे उस 'पेनड्राइव' को 'काउन्टर अटैक' के रूप में इस्तेमाल करने की ही बात कर रहे हैं। और फिर मीडिया से चर्चा में यह कहकर तो कमलनाथ ने खुद को और फंसा लिया कि उन्हें वह पेनड्राइव पुलिस ने दी थी और शायद वह सबसे 'ओरिजनल' है। अब सवाल यह उठ रहा है कि भले ही कोई मुख्यमंत्री हो लेकिन किसी अपराध की जांच कर रही एजेंसी का इस तरह एक महत्वपूर्ण सबूत किसी राजनीतिक व्यक्ति को सौंपना क्या अपने आप में कानून का उल्लंघन नहीं है और उससे भी ज्यादा उस व्यक्ति के द्वारा उस सबूत को अपने पास रख लेना क्या गैरकानूनी नहीं है। अगर 'उच्चस्तरीय राजनीतिक समझौता' नहीं हुआ तो ये दोनों ही बातें आने वाले दिनों में कमलनाथ को कानूनी तौर पर मुश्किल में डाल सकती हैं। जाहिर है तब तक प्रदेश की राजनीति में कोरोना की कम और हनीट्रैप की चर्चा ज्यादा होती रहेगी।

ठंडे बस्ते में जाते दिख रही है। मामले में गठित एसआईटी भी विवादों में ही रही। तेजतर्रार आईपीएस संजीव शमी को जब कमलनाथ सरकार ने एसआईटी से हटाया, तभी तय हो गया था कि अब जांच में सिर्फ लीपापोती ही होनी है। यही वजह है कि कोर्ट ट्रायल शुरू होने के बाद भी दागी रसूखदारों के चेहरे बेनकाब नहीं हुए।

कोरोना महामारी के कारण जिस तरह से लोगों की जान जा रही है और जिस तरह लोग उससे पीड़ित हैं, उसके चलते कायदे से तो इन दिनों सारा ध्यान कोरोना से निपटने के उपायों पर ही होना चाहिए। लेकिन 'अजब-गजब' मप्र में कुछ 'अजब-गजब' न हो तो 'अजब-गजब' का तमगा लटकाने का फायदा ही क्या? सो अपने नाम को सार्थक करते हुए मप्र की राजनीति इन दिनों 'कोरोना ट्रैप' के बजाय 'हनीट्रैप' में उलझी है।

आमतौर पर इन दिनों सरकारों पर यह आरोप लग रहा है कि वे कोरोना से निपटने में अपनी असफलता के चलते लोगों का ध्यान बंटाने के लिए दूसरे मुद्दे उछाल रही हैं, लेकिन मप्र में मुद्दा उछालने का यह काम विपक्ष ने किया है और वह भी पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता कमलनाथ ने। इसने सत्तापक्ष को कोरोना के कारण हो रही आलोचना से बचने का अच्छा मौका दे दिया और उसने भी मुद्दे तो तत्काल लपकने में कोई कोताही नहीं बरती।

हुआ यह कि 16 मई को प्रदेश के पूर्व मंत्री और धार जिले के गंधवानी से कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार के भोपाल स्थित मकान पर अंबाला की एक महिला ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद खबरें आईं कि उमंग सिंघार कई दिनों से उस महिला के संपर्क में थे और उससे शादी करना चाहते थे। महिला ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें सीधे तौर पर अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया था। लेकिन उसकी ओर से दिए गए कुछ अन्य संकेतों के आधार पर पुलिस ने उमंग सिंघार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया। और यहीं से मामले में सियासत की घुसपैठ हो गई। भाजपा ने सिंघार के बहाने कांग्रेस को घेरने का अवसर पाया और इसे भुनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। यहां तक कि इसे मप्र का 'भंवरी कांड' तक करार दे दिया गया। 20 मई को कमलनाथ ने कोरोना और अन्य विषयों पर पार्टी विधायक दल के सदस्यों से एक वर्चुअल संवाद किया तो उस दौरान कुछ विधायकों ने इस मामले को उठाते हुए शिकायत की कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए उमंग सिंघार को इस मामले में जबरन फंसाना चाहती है। इसी दौरान कमलनाथ की ओर कथित तौर पर यह कहा गया कि 'सिंघार मामले में सरकार ओछी राजनीति न करे वरना परिणाम ठीक नहीं होंगे। हमारे पास भी हनीट्रैप की पेन ड्राइव है।'

कमलनाथ का यह बयान जैसे ही मीडिया में आया, बवाल मच गया। भाजपा ने अवसर का लाभ उठाते हुए तत्काल आरोप जड़ दिया कि कमलनाथ एक आरोपी को बचाने के लिए 'ब्लैकमेल' की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि शाम होते-होते कमलनाथ की ओर से सफाई आई कि 'हनीट्रैप' की सीडी-पेनड्राइव कई लोगों के पास है और उन्होंने उसी बात को बस दोहराया भर है। पर शायद अगले दिन उनसे एक बड़ी रणनीतिक चूक हो गई। इसे 'हनीट्रैप' पेनड्राइव वाले बयान से पैदा हुई उलझन का असर कहें या कुछ और लेकिन अगले दिन कमलनाथ ने मीडिया से वर्चुअल संवाद किया और उसका फोकस कोरोना पर रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि मप्र में कोरोना से एक लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार आंकड़े को छुपा रही है। इसी तरह उन्होंने खेती-किसानी और बेरोजगारी से लेकर अर्थव्यवस्था तक के कई मुद्दे उठाए। लेकिन जब सवाल पूछने की बारी आई तो कुछ पत्रकारों ने उमंग सिंघार केस और 'हनीट्रैप की पेनड्राइव' वाले मामले पर उनसे सवाल कर डाले। और इन सवालों के जवाब में कमलनाथ ऐसी चूक कर बैठे जिसने मामले को ठंडा करने की कोशिशों पर सिर्फ पानी ही नहीं फेरा, बल्कि उसमें और आग लगा दी। मामला इस कदर विवादों में हो गया है कि भाजपा ने कमलनाथ को चारों तरफ से घेर लिया है।

● **सुनील सिंह**

क्या है हनी ट्रैप कांड

दरअसल कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे, उस समय सितंबर 2019 में कुछ ऐसी महिलाएं पुलिस के हत्थे चढ़ी थीं जिन्होंने प्रदेश के राजनेताओं, अफसरों और बिजनेसमैन सहित कई रसूखदारों को कथित जिस्मफरोशी के जरिए ब्लैकमेल किया था। वह कांड सामने आने के बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया था और सरकार ने इसके लिए विशेष जांच दल का गठन किया था। खबरें यह भी थीं कि मामले से जुड़ी सीडी में कथित तौर पर भाजपा व कांग्रेस से जुड़े कई बड़े नेताओं के भी नाम हैं। कारण चाहे जो भी रहा हो लेकिन उस मामले की जांच बाद में ठंडे बस्ते में चली गई। न तो कमलनाथ के समय उस मामले को अंजाम तक पहुंचाया गया और न बाद में शिवराज सिंह की सरकार ने इस मामले में कोई सक्रियता दिखाई। मामले से जुड़ी कई महिलाएं अब भी जेल में हैं। लोग भी एक तरह से उस मामले को या तो भूल चुके थे या उन्होंने मान लिया था कि 'राजनीतिक मिलीभगत' के चलते इस मामले में कुछ होना जाना नहीं है। उमंग सिंघार पर शिकंजा कसता देख कमलनाथ ने 'हनीट्रैप' पेनड्राइव का उल्लेख कर, एक तरह से गड़े मुर्दे को फिर उखाड़ दिया है। इस पेनड्राइव का जिक्र करने के बाद भाजपा ने जिस तरह मामले को लपका उससे कमलनाथ को भी संभवतः यह अहसास तो हो गया होगा कि उनसे तीर गलत दिशा में चल गया है। और शायद इसीलिए मामला दूसरी तरफ मोड़ने के लिहाज से उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर कोरोना से निपटने में असफल होने के आरोपों की बौछार कर दी थी। पर दुर्भाग्य से उनकी वह कोशिश भी बेकार सी गई और मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी हनीट्रैप का मुद्दा ही सबसे ज्यादा उभरकर प्रकाशित और प्रसारित हुआ।

मप्र के हरे सोने पर नक्सलियों की नजर

प्रदेश में हरे सोने यानी तेंदूपत्ता की तुड़ाई शुरू हो गई है। अनुमानतः इस बार सरकार को करीब 15 अरब रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। उधर, हरे सोने की चमक को देखते हुए समितियों, ठेकेदारों और व्यापारियों से लेवी वसूलने के लिए नक्सलियों और डकैतों ने भी वन क्षेत्रों में डेरा डाल दिया है। बालाघाट में वसूली के लिए ठेकेदारों पर दबाव बनाने के लिए नक्सलियों ने मलाजखंड थाना क्षेत्र की पाथरी चौकी अंतर्गत किनारदा के भद्रीटोला के खेतों में सूख रहे तेंदूपत्ता फड़ों में आग लगा दी है। इस आगजनी की घटना में करीब डेढ़ लाख पत्ते जलने का अनुमान जताया जा रहा है। यहां मौके से पुलिस ने नक्सली पर्चे भी बरामद किए हैं। घटना स्थल पर मलाजखंड एरिया कमेटी के नाम के पर्चे मिले हैं। वहीं, वन क्षेत्रों में नक्सलियों और डकैतों की हलचल बढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। वन क्षेत्रों में लगातार पुलिस की गश्त हो रही है।

प्रदेश में हर साल तेंदूपत्ते की तुड़ाई शुरू होते ही नक्सली और डकैत सक्रिय हो जाते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार नक्सली और डकैत समितियों, ठेकेदारों और व्यापारियों से हर साल लेवी वसूलते हैं। तेंदूपत्ता से एक माह के अंदर डकैतों और नक्सलियों की इतनी कमाई हो जाती है कि वे सालभर उससे अपना खर्चा चलाते हैं। इस साल भी इन्होंने वन क्षेत्रों में डेरा डाल दिया है और ठेकेदारों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।

खुफिया विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, माओवादी संगठनों ने प्रत्येक एरिया कमांडर और सब एरिया कमांडर को 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक की वसूली का लक्ष्य दिया गया है। ऑपरेशन से जुड़े अफसरों ने बताया कि फोर्स के दबाव में पिछले काफी समय से बैकफुट पर चल रहे माओवादी आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। वहीं लॉकडाउन के चलते रही-सही कसर पूरी हो गई है। कोरोना वायरस के चलते उनके पास खाने तक का सामान नहीं है। संसाधनों की कमी को देखते हुए ठेकेदारों के जरिए वसूली करने की योजना बनाई है। बता दें कि हर साल फरवरी से लेकर जून तक वसूली के टारगेट को लेकर माओवादी अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं।

जानकारी के अनुसार, प्रदेश में तेंदूपत्ता उत्पादक सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनुपपुर में नक्सली सक्रिय हैं, वहीं सतना, रीवा, छतरपुर, सीधी, पन्ना, टीकमगढ़ में डकैतों की उपस्थिति देखी जा रही है। सीधी ऐसा जिला है जहां नक्सली और डकैत दोनों सक्रिय हैं। इनके अलावा शिवपुरी, श्योपुर, कटनी, सागर, सोहागपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद, खरगोन, झाबुआ व जबलपुर में भी तेंदूपत्ता बहुतायत में होता है। उपरोक्त सभी जिलों में माफिया सबसे अधिक कमाई करते हैं। ऐसे में अगले दो महीने तक प्रदेश के वन क्षेत्र काली कमाई वालों के कब्जे में रहेंगे।

मलाजखंड एरिया कमेटी ने धमकी भरे पर्चे छोड़कर तेंदूपत्ता संग्रहण की मजदूरी बढ़ाने की मांग पर जोर दिया है। उसमें नक्सलियों द्वारा लिखा गया है कि बाजार में हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन तेंदूपत्ता रेट में एक नए पैसे की वृद्धि नहीं हुई है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र में 750 रुपए और छत्तीसगढ़ में 450 रुपए प्रति सैकड़ा गड्डी का दिया जाता है। मप्र में तेंदूपत्ता रेट पूछे जाने पर ठेकेदार और मैनेजर द्वारा पुलिस की धमकी दी जाती है।

नक्सलियों की कोरोना संक्रमण के दौर में सक्रियता को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों मे तैनात बल को अलर्ट करते हुए सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है। बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी ने भी इस मामले में पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है और शिकायत के बाद नक्सलियों के खिलाफ संबंधित पुलिस चौकी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मप्र का तेंदूपत्ता सबसे अच्छा होता है। इसलिए नक्सली और डकैत यह बात भलीभांति जानते हैं कि देश के बड़े-बड़े व्यापारी यहां तेंदूपत्ता खरीदने आते हैं। इसलिए वे तेंदूपत्ता तुड़ाई के सीजन में लेवी वसूलने के लिए दबाव बनाने लगते हैं।

● राकेश ग्रोवर

नक्सली सहानुभूति के सहारे वनवासियों में बढ़ा रहे पैठ

दरअसल, नक्सली इस कोशिश में हैं कि वे तेंदूपत्ता तोड़ रहे वनवासियों की मजदूरी बढ़ाने की मांग करके उनमें पैठ बढ़ा सकते हैं। इसलिए बालाघाट में पर्चे के माध्यम से उन्होंने ठेकेदारों के लिए फरमान जारी किया है। पर्चे में मांग की गई है कि तेंदूपत्ता मजदूरों को प्रति सैकड़ा गड्डी 600 रुपए दिए जाए। स्थानीय लोगों को फड़ी चेकर का काम देने की बात पर जोर दिया गया। हर फड़ पर मुंशी के साथ चपरासी रखने को कहा गया है। चेकर को 25 हजार और मुंशी व चपरासी को 20-20 हजार रुपए देने की मांग भी की गई है। तेंदूपत्ता की उल्टाई-पल्टाई 75 रुपए प्रति हजार गड्डी देने पर जोर भी जोर दिया गया है। फड़ की जगह पर 25 हजार कुएं, बोर तालाब के लिए देने की बात लिखी है। दरअसल, वनवासियों के सहयोग के बिना नक्सली वन क्षेत्रों में असुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि वे वनवासियों को अपने पक्ष में बनाए रखें। सूत्र बताते हैं कि जंगल क्षेत्रों में स्थित गांव नक्सलियों की शरणस्थली भी बने रहते हैं। नक्सली ठेकेदारों से मिली लेवी का कुछ हिस्सा गांव में भी वितरित कर देते हैं। बालाघाट में पर्चा मिलने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी का कहना है कि मलाजखंड की पाथरी चौकी अंतर्गत किनारदा के भद्रीटोला में नक्सलियों द्वारा खेतों में सूख रहे तेंदूपत्ता फड़ों में आगजनी की गई है। करीब डेढ़ लाख पत्ते जलने की बात कही जा रही है। मौके से कुछ नक्सली पर्चे भी मिले हैं। पुलिस पर्चों की तस्दीक कर रही है। साथ ही मामले की जांच भी कर रही है।

मप्र में हो सकता है खाद का संकट!

मप्र में इस बार सरकार ने करीब 149.57 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोवनी और 272 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। उधर मौसम की आहट के साथ ही किसानों ने बोवनी के लिए खेत तैयार कर लिया है, लेकिन न तो उनके पास बीज और न ही खाद का इंतजाम है। ऐसे में किसान परेशान हैं। दरअसल इस वर्ष कोरोना कर्फ्यू खरीफ की बोवनी को भी प्रभावित कर रहा है। मानसून की आहट के बाद किसानों ने सोयाबीन की बोवनी के लिए खेत तैयार कर लिए हैं। अब खाद और बीज का इंतजार है, जो कि सरकार के आदेश अनुसार 1 जून के बाद मिलेगा। हालांकि जिला प्रशासन ने सहकारी सोसायटियों पर खाद उपलब्ध कराने की बात कही है लेकिन अधिकांश सोसायटियों के पास खाद उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किसान बारिश के पूर्व खेतों में खाद नहीं डाल पाएगा।

मप्र में किसानों के सामने खाद का संकट आने के आसार हैं। फिलहाल रीवा, मंदसौर, रायसेन, शिवपुरी समेत कई जिलों में 1200 की डीएपी खाद की बोरी 1900 रुपए में मिल रही है, जबकि बोरियों पर पैकिंग दिसंबर 2020 अंकित है। तब खाद की कीमत 1200 रुपए थी। स्पष्ट है, कंपनियां पुराना माल बढ़े हुए दाम पर बेच रही हैं। मप्र सहकारी विपणन संघ पर एमआरपी बदलकर बेचने के आरोप लग रहे हैं। मप्र में फरवरी 2021 में खाद की एक बोरी 1200 रुपए में बिक रही थी। इसकी कीमत मई माह में अचानक 1900 रुपए हो गई है। कई कंपनियों ने इस कीमत पर भी खाद की आपूर्ति से हाथ खड़े कर दिए हैं। हालांकि कंपनियों से सरकार ने कम कीमत के दौरान ही एक लाख टन डीएपी और 10 हजार टन एनपीके खरीद लिया था, लेकिन जरूरत 10 लाख टन से ज्यादा की है।

इस वर्ष प्रदेश में 149.57 हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल की बोवनी होना है। इसके लिए किसानों ने मैदानी क्षेत्र में तो तैयारी कर ली है। खेतों को साफ कर जुताई कर ली गई है, अब बोवनी के पहले डीएपी फास्फेट व एनपीके 12:32:16 की दरकार है। किसान इसे लेने के लिए भटक रहा है क्योंकि जनता कर्फ्यू के चलते प्रदेश में खाद बीज की दुकानें बंद है व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सहकारी सोसायटियों के पास पर्याप्त खाद उपलब्ध नही हैं। ऐसे में किसानों का बोवनी का समय निकल जाएगा। अब 1 जून से ही किसानों को खाद बीज उपलब्ध हो पाएगा। जानकारी के अनुसार अभी निजी दुकानों के पर एपीके 12:32:16 व डीएपी सुपर फास्फेट रखा है। वहीं, सहकारी सस्थानों में से मात्र 25 फीसदी सस्थानों पर ही खाद उपलब्ध बताया जा रहा है। ऐसे में किसान खरीफ की तैयारी कैसे करें।

खाद की मांग, बिक्री और भंडारण पर नजर

प्रदेश में डीएपी, यूरिया सहित अन्य खाद की मांग, बिक्री और भंडारण की स्थिति पर सरकार की नजर रहेगी। प्रत्येक सहकारी समिति को न सिर्फ भंडारण की स्थिति प्रतिदिन बतानी होगी बल्कि बिक्री का हिसाब-किताब भी देना होगा। इसके आधार पर जहां जरूरत होगी, वहां सरकार अपनी कार्ययोजना में सुधार करती जाएगी। इसके लिए कृषि और सहकारिता विभाग ने राज्य सहकारी विपणन संघ और अपेक्स बैंक के स्तर से मांग और आपूर्ति की निगरानी करने की व्यवस्था बनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खाद की उपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि किसानों के पास आगामी फसल के लिए अपने खेतों को तैयार करने और खाद बीज आदि की व्यवस्था करने के लिए सिर्फ एक महीना बचा है। ऐसे में रासायनिक उर्वरक को सहकारी समितियों के माध्यम से सीधे किसानों के घर तक पंहुचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सरकार का कहना है कि किसानों को यूरिया की उपलब्धता 31 मई तक 5.50 लाख मीट्रिक टन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह डीएपी की उपलब्धता 4.50 लाख मीट्रिक टन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा डीएपी का प्रदेश के लिए आवंटन बढ़ाने एवं प्रदाय के लिए भारत सरकार से कहा गया है।

मंत्रालय सूत्रों का कहना है, खाद की कीमत 700 रुपए बढ़ने उनकी फसल की लागत बढ़ेगी। अभी किसान फसल के लिए खेतों में तैयारी कर रहे हैं। उन्हें खाद की जरूरत 25 मई के बाद से हो रही है। खाद की मांग जून से तेजी पकड़ सकती है। तब खाद के लिए संकट की स्थिति निर्मित होने की आशंका है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए खाद पर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि जारी वित्तीय वर्ष के लिए सब्सिडी की दरों में बदलाव न कर यथावत रखा गया है। कमलनाथ सरकार जब सत्ता से बाहर हुई थी, तब डीएपी की एक बोरी की कीमत 900 रुपए थी। इसे दिसंबर 2020 में शिवराज सरकार ने 1200 रुपए कर दिया था। अब इसे बढ़ाकर 1900 रुपए कर दिया गया है। जानकारों का कहना है, प्रदेश में अगले माह करीब साढ़े 9 लाख टन खाद की जरूरत पड़ेगी। चूंकि कीमतों में इजाफा हुआ है। खुले बाजार की हालत ठीक नहीं है, तो खाद को लेकर संकट की स्थिति बन सकती है। पिछले साल प्रदेश में सरकारी और खुले बाजार से 10 लाख टन खाद की आपूर्ति हुई थी। इस साल सरकार ने 1 लाख 18 हजार टन डीएपी खाद की व्यवस्था कर ली है। इसके बाद 6 से साढ़े 6 लाख टन खाद की जरूरत होगी। खुले बाजार में भी 3 लाख टन की आपूर्ति अलग से होगी।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम बढ़ने से खाद कंपनियों ने 1900 रुपए में भी आपूर्ति से इंकार कर दिया है। कंपनियों को बंदरगाहों पर खाद की बोरी 2100 रुपए में मिल रही है। उनकी मांग 2100 रुपए प्रति बोरी की है। कंपनियों से कई दौर की बातचीत के बाद सरकार ने 1700 रुपए की दर से 18 हजार टन डीएपी खाद खरीदी। इसके बाद कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए तो 12 में से ञ कंपनियां 1900 रुपए की दर से आपूर्ति को तैयार हुईं।

● **जितेंद्र तिवारी**

महिलाओं पर नसबंदी का दारोमदार!

मप्र की बढ़ती जनसंख्या सरकार के लिए नई चुनौती के रूप में सामने आ रही है। प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर देश ही नहीं पूरी दुनिया के औसत से ज्यादा है। प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर यानी टीएफआर 2.3 है, जबकि देश का 2.2 और दुनिया का टीएफआर 2.4 है। देश के अन्य राज्यों से तुलना करें तो जनसंख्या वृद्धि में मप्र पांचवें नंबर पर आता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का टीएफआर मप्र से कम है।

भारत में जनसंख्या की गणना हर 10 साल में होती है। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इस बार अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है। फिर भी जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम पर काम करने वाले सेंटर फॉर एडवोकेसी एवं सृजन फाउंडेशन का अनुमान है कि 2021 में मप्र की जनसंख्या 8,50,02,417 हो गई है। जिसमें पुरुषों की अनुमानित संख्या 4,40,19,895 और महिलाओं की अनुमानित संख्या 4,09,82,522 है। भारत की जनगणना पिछली बार 2011 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मप्र की कुल जनसंख्या 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार 809 थी। जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 6.00 प्रतिशत है। जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या 3 करोड़ 76 लाख 10 हजार 983 थी, जबकि महिलाओं की जनसंख्या 3 करोड़ 50 लाख 15 हजार 826 थी। इस तरह 10 साल में मप्र की जनसंख्या में करीब 1,23,75,680 लोगों की बढ़ोत्तरी हुई है। जिसमें पुरुषों की संख्या 94,08,912 और महिलाओं की संख्या 59,66,696 है।

जनसंख्या नियंत्रण देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि की दर ज्यादा है। इन राज्यों में मप्र भी शुमार है। प्रदेश की कुल प्रजनन दर भले ही कम होकर राष्ट्रीय स्तर से अधिक पहुंच गई हो, वहीं प्रदेश के 25 जिले ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर प्रदेश से दोगुनी तक है। इन 25 जिलों में पन्ना और शिवपुरी सबसे आगे हैं। इन जिलों को केंद्र सरकार ने अपनी मिशन परिवार विकास में भी शामिल किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट हैरान करने वाली है। परिवार नियोजन में प्रदेश के सिर्फ पांच फीसदी पुरुषों की रुचि है। चौंकाने वाली बात ये भी है कि सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी प्रदेश के सिर्फ आधा फीसदी पुरुष ही नसबंदी ऑपरेशन करवाते हैं। जबकि सरकार पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए कई जतन कर रही है। प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर तीन हजार कर दी गई है। महिलाओं को दो हजार रुपए मिलते हैं। प्रसव के तुरंत बाद यदि महिला नसबंदी ऑपरेशन करवा लें तो उसे भी प्रोत्साहन राशि स्वरूप तीन हजार रुपए दिए जाते हैं। इसमें महिला को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि सहित डॉक्टर फीस, आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता का इनसेंटिव, नाश्ते का पैसा सहित अन्य खर्च शामिल है। पुरुष नसबंदी पर ज्यादा पैसा दिया जाता है। सबसे ज्यादा नसबंदी करने वाले डॉ. ललित मोहन पंत बताते हैं कि देश के 29 में से 19 राज्यों ने यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। वहां का टीएफआर 2.1 प्रतिशत से नीचे आ गया है। मप्र को यह लक्ष्य हासिल करना है।

हालांकि विडंबना यह है कि जो पुरुष और महिला नसबंदी ऑपरेशन करवा रहे हैं उन्हें वर्तमान में प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। इस संबंध में जिम्मेदारों का कहना है कि पिछले लगभग 1 साल से प्रदेश सरकार की तरफ से इस मद में राशि ही प्राप्त नहीं हुई है। महिला डॉक्टरों के अनुसार नसबंदी का लक्ष्य निजी अस्पतालों को भी दिया जाता है। आमतौर पर ऑपरेशन के जरिए होने वाले प्रसव के दौरान महिला से नसबंदी के लिए सहमति ली जाती है और सहमति मिलने पर नसबंदी कर दी जाती है। यही वजह है महिलाओं की नसबंदी का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अधिकारियों के अनुसार प्रजनन दर में प्रदेश के आगे रहने की सबसे बड़ी वजह है पुरुषों का असहयोगी रवैया। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग साढ़े तीन लाख नसबंदी ऑपरेशन होते हैं लेकिन इसमें पुरुष नसबंदी की संख्या 5 प्रतिशत से भी कम है।

जनसंख्या नियंत्रण सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटना इस समय सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रदेश का पूरा अर्थशास्त्र जनसंख्या के आधार पर ही तय होता है। विकास की गति, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय और संपन्नता का सीधा संबंध प्रदेश की जनसंख्या से ही है। प्रदेश की प्रजनन दर 2.3 है यानी एक परिवार में औसतन दो से ज्यादा बच्चे होते हैं। गांव में प्रति परिवार 3 बच्चे और शहर में 2.1 बच्चे होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में मप्र की कुल आबादी 7,26,26,809 दर्ज की गई थी। परंतु जनगणना के 10 साल बाद सर्वे और आंकड़ों की मानें तो 2021 में प्रदेश की जनसंख्या 8,50,02,417 हो गई है। चूंकि यह आंकड़े पूर्ण रूप से आंकी गई जनसंख्या के नहीं हैं, परंतु अनुमानित जनसंख्या इतनी ही है। अगर इस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो हम पाएंगे कि वह 24.34 प्रतिशत है। जो जनसंख्या के विस्फोट को दर्शाता है। प्रदेश में शहरों की अपेक्षा गांवों में जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है।

● श्याम सिंह सिकरवार

प्राथमिकता में जनसंख्या नियंत्रण नहीं

सेंटर फॉर एडवोकेसी एवं सृजन फाउंडेशन मझगवां (कटनी) की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मप्र में सरकार की प्राथमिकता में जनसंख्या नियंत्रण कभी नहीं रहा है। यही वजह है कि प्रदेश में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। अब हालात यह है कि मप्र की फर्टिलिटी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक हो चुकी है। यही वजह है कि मप्र को उन राज्यों में शामिल कर लिया गया है, जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक बनी हुई है। इसे जनसंख्या नियंत्रण के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। इसमें प्रमुख भूमिका उन दो दर्जन जिलों की है जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर प्रदेश से दोगुनी है। प्रदेश में जिन दो जिलों में सबसे कम वृद्धि दर है उनमें मुरैना व खंडवा जिले हैं। इसके उलट पन्ना व शिवपुरी जिले ऐसे हैं जो प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे आगे हैं।

सूबे में अपराधियों ने अपना ट्रेंड बदल लिया। कल तक आपराधिक घटना को अंजाम देने वालों ने नए रास्ते को अपनाना ही बेहतर समझा। हथियार का सहारा अब इस धंधे में खलल डालने वालों पर बनाया जाने लगा। इसके साथ ही जिले में शराब माफियाओं ने एक समानांतर व्यवस्था खड़ी कर ली। अपराध जगत के बड़े माफियाओं से लेकर छुटभैया तक शराब तस्करी के धंधे में लिप्त हो गए।

जंगल में अब शराब तस्करों का कब्जा

ग्वालियर और उसके आसपास के जंगलों में जहां कभी डकैतों की दहाड़ गूंजती थी वहां अब शराब माफियाओं की हलचल दिखाई देती है। जंगलों में जमीन के नीचे, टैंकों के अंदर पानी के बीच छुपाकर रखी गई लाखों की कच्ची शराब, गुड़ लहान व अन्य सामग्री आबकारी विभाग के अमले ने जप्त की है। ग्वालियर-चंबल संभाग में हर दिन पुलिस और आबकारी विभाग अवैध शराब के धंधे को उजागर कर रहे हैं। विगत दिनों जिले के घाटीगांव, नयागांव, बेला का बावड़ी के जंगल में छापा मारा गया था। काफी मात्रा में महिलाएं शराब बना रही थीं, पर आबकारी अमले के हाथ मौके से कोई भी आरोपी नहीं लगा है। अमले के वाहनों को देखकर शराब बना रहे लोग भाग गए।

फिलहाल फरार शराब माफियाओं के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम ने अलग-अलग 8 एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। तीन स्थानों पर जंगल में जो शराब बनाई जा रही थी यह शराब कोरोना कर्फ्यू में शहर और देहात इलाके में खपाई जानी थी। यह जहरीली शराब है और इसकी कोई जांच नहीं होती। ऐसी ही शराब से मुरैना में आधा सैकड़ा लोगों की जान चली गई थी।

चंबल के बीहड़ों में कभी बागियों की बंदूकों की आवाज गूंजा करतीं थी। पुलिस के लिए चुनौती बने बागियों (डकैतों) का सफाया हुआ तो अब यहां अवैध शराब और मिलावट के कारोबार ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। माफिया ने इसके लिए बागियों का ही तरीका अपनाया है। बीहड़ दुर्गम क्षेत्रों में अपने कारोबार का ठिकाना बनाया है। जहां इस अवैध कारोबार की भनक आसानी से पुलिस तक पहुंचती नहीं और अगर पहुंचती भी है तो पुलिस को सटीक सूचना के बाद भी मौके तक पहुंचने में दो से तीन घंटे का समय लगता है। बीहड़ में बसे गांवों में जहरीली शराब बनाकर बड़े पैमाने पर बाइकों से चंबल के अलावा राजस्थान और उप्र से सटे इलाकों में सप्लाई की जाती है। स्थिति यह है कि यहां ज्यादातर गांव अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हो चुके हैं। खास बात यह है कि इसके लिए बीहड़ों की दुर्गम जगहों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पुलिस का पहुंचना आसान नहीं है। इसमें सहायक बनती है चंबल नदी की सीमा। यहां से सामान भी आसानी से राजस्थान और उप्र से लाया जा सकता है और यहां से उसी रास्ते से पहुंचाया भी जा सकता है। यही वजह है कि चंबल में यह अवैध शराब कारोबारी व मिलावटखोर अपने पैर पसारते चले गए।

यहां राजस्थान से अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही है, वहीं अवैध शराब की भट्टियां भी बढ़ गईं हैं, जिन्हें बीहड़ों में ही लगाया जाता है। नूराबाद पुलिस ने कुछ दिन पहले नाऊपुरा गांव में एक अवैध शराब बनाने की भट्टी को पकड़ा, जिसमें पुलिस को कार्रवाई के लिए पहुंचने के लिए दो घंटे तक इन बीहड़ इलाकों में पैदल चलना पड़ा। दुर्गम स्थानों तक पहुंचने में पुलिस को समय लगता है, इसी समय में कोई न कोई इन अवैध शराब कारोबारियों तक सूचना पहुंचा देता है। जिससे इनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है।

पुलिस व प्रशासन की निष्क्रियता के साथ-साथ लाइसेंसी ठेकेदारों की मनमानी ने भी अवैध व नकली शराब के कारोबार को फैलने में मदद की है। मुरैना में लाइसेंसी दुकानों पर प्रिंट रेट से 15 से 20 फीसदी महंगी शराब मिल रही है। इसी तरह लोग सस्ती होने के कारण नकली व अवैध शराब के जाल में फंस जाते हैं। 15 लोगों को लीलने वाली शराब का क्वार्टर महज 50 रुपए में मिल गया था। अवैध और नकली शराब के कारोबार करने वाले इतने बेखौफ हैं कि बीहड़ से सटे गांवों में किराना, पानी-बीड़ी की दुकानों पर इसको बिकवा रहे हैं। छैरा मानपुर गांव में जिस शराब से मौतें हुई उसे छोटी-छोटी किराने की दुकानों से बेची गई थी।

मप्र में शराब इतनी महंगी है कि अंग्रेजी शराब की जो बोतल मुरैना में 2400 रुपए की है वह राजस्थान के धौलपुर में 1200 से 1300 रुपए में मिल जाती है। बस यही कारण है कि मुरैना के शराब तस्कर, राजस्थान के शराब माफियाओं के साथ मिलकर अंचल में हर रोज 40 से 45 लाख रुपए की राजस्थान व हरियाणा की शराब अवैध तरीके से खपा रहे हैं।

● **नवीन रघुवंशी**

बीहड़ में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री

टेंटरा, सबलगढ़, चिन्नौनी, देवगढ़, बागचीनी, जौरा थाना पुलिस ने कईयों बार राजस्थान से आई शराब पकड़ी, जिसमें से अधिकांश शराब बीहड़ों के रास्ते से आ रही है। चंबल के बीहड़ों में नकली शराब बनाने की फैक्ट्रियां तक चल रही हैं। नूराबाद पुलिस ने नाऊपुरा गांव के बीहड़ों में सांक नदी के किनारे जहरीले कैमिकल व गुड़ से बनाई जा रही नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी। नूराबाद ही नहीं बागचीनी और सिकरौदा में क्वारी नदी के किनारे बीहड़ों में नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है। पुलिस अफसर ही मानते हैं कि ऐसी कई और अवैध शराब फैक्ट्री बीहड़ों में चल रही हैं।

74 साल बाद रफ्तार भरेंगे चीते

धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले स्तनधारी चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाकर इस साल नवंबर में मप्र के श्योपुर जिले स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाएगा। इससे करीब 74 साल बाद देश में विलुप्त हुए चीते की दहाड़ फिर से सुनाई देगी। इन चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत में लाने के लिए करीब 10 साल से चर्चा चल रही थी। गत दिनों मप्र के वनमंत्री विजय शाह ने इसकी जानकारी दी है।

देश में अंतिम धब्बेदार चीता वर्ष 1947 में अविभाजित मप्र के कोरिया इलाके में देखा गया था, जो अब छत्तीसगढ़ में आता है। बाद में वर्ष 1952 में इस जानवर को देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। वनमंत्री शाह ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से 10 चीतों को मप्र के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा। इनमें 5 नर एवं 5 मादा होंगी। हमने इनके लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बाड़ा बनाने का काम इस महीने से शुरू कर दिया है और अगस्त में बाड़ा बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। चंबल संभाग में आने वाला कूनो राष्ट्रीय उद्यान करीब 750 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और चीते को फिर से बसाने के लिए देश के सबसे बेहतर पर्यावास में से यह एक है। इसमें चीतों के लिए अच्छा शिकार भी मौजूद है, क्योंकि यहां पर चौसिंगा हिरण, चिंकारा, नीलगाय, सांभर एवं चीतल बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। शाह ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हमें चीतों को फिर से बसाने के लिए इस सप्ताह एक संभावित कार्यक्रम भेजा है। इसके अनुसार इस साल मई से अगस्त के बीच मप्र वन विभाग को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनके लिए बाड़ा तैयार करना है और इनको बसाने के लिए इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 14 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट मिलेगा।

उन्होंने कहा कि 14 करोड़ रुपए के इस अनुमानित बजट को भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मप्र एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान को जून में दिया जाएगा। शाह ने बताया कि इसके अलावा इस संभावित कार्यक्रम में कहा गया है कि भारत से मप्र वन विभाग, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान के दलों को जून-जुलाई में इन चीतों के बारे में विस्तृत रूप से जानने एवं प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा और बाद में इन चीतों को पकड़कर पिंजरों में रखकर अक्टूबर-नवंबर में अंतरराष्ट्रीय परिवहन के जरिए भारत भेजा जाएगा तथा ये चीते नवंबर में भारत में पहुंचेंगे।

अफ्रीका के चीतों को भारत में लाए जाने की योजना वर्ष 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान बनाई जा रही थी। तब जयराम रमेश केंद्रीय पर्यावरण एवं वनमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) थे और उन्होंने इसकी पहल की थी लेकिन लगभग 1 दशक बाद यह योजना बन पाई। एक वन अधिकारी ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के चीतों के विशेषज्ञ विन्सेंट वैन डेर मेरवे 26 अप्रैल को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ आए और इस उद्यान का निरीक्षण किया कि वहां पर चीतों को बसाए जाने के लिए कैसा पर्यावास है। बाद में उन्होंने इन चीतों को यहां बसाने की अनुमति दे दी और अब चीतों को यहां लाने की अंतिम प्रक्रिया चल रही है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) जेएस चौहान ने बताया कि चीते को फिर से बसाने के लिए देश के सबसे बेहतर पर्यावास का पता लगाने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के विशेषज्ञों के एक दल ने पिछले साल मप्र के 4 स्थानों का दौरा किया था। इनमें श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा सागर जिले स्थित नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और नीमच एवं मंदसौर जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित गांधी सागर अभयारण्य तथा शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान शामिल थे।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल जनवरी में अफ्रीकी चीते को प्रायोगिक तौर पर भारत में सबसे अधिक उपयुक्त जगह पर लाने की इजाजत दी थी और देश में चीतों को फिर से बसाने की योजना के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को मार्गदर्शन देने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति ने भारतीय वन्यजीव संस्थान को देश में चीतों को फिर से बसाने के लिए सभी संभावित ठिकानों का सर्वेक्षण कर जायजा लेने को कहा था जिसके बाद इस संस्थान के दल ने मप्र के 4 स्थानों का दौरा किया था।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

मप्र में पहले भी रहते थे चीते

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) ने बताया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान के वन्यजीव पारिस्थितिकी एवं संरक्षण जीव विज्ञान विभाग के डीन डॉ. यादवेंद्र झाला एवं 2 अन्य वैज्ञानिकों ने यह देखने के लिए 4 स्थानों का निरीक्षण किया कि ये स्थान चीतों के लिए उपयुक्त हैं या नहीं? उन्होंने कहा कि मप्र में पहले भी चीते रहते थे। राज्य में लंबे समय तक इनके संरक्षण का इतिहास रहा है। हमारे पास इनको बसाने के लिए बेहतर जगह है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) जेएस चौहान ने बताया कि हम मप्र के पन्ना बाघ अभयारण्य में वर्ष 2009 में बाघों को फिर से बसाने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1952 में भारत को चीतों से विलुप्त घोषित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) के रेड डाटा की सूची के अनुसार चीते को लुप्तप्राय प्रजातियों में माना जाता है, क्योंकि अब इनकी आबादी 7,000 से कम हो गई है और इनमें से भी अधिकतर अफ्रीका में ही हैं।

हीरे के लिए पेड़ों की बलि

छतरपुर में बकस्वाहा हीरा खदान के लिए काटे जाने वाले 2.15 लाख पेड़ों को बचाने के लिए मप्र समेत देशभर के 1 लाख 12 हजार लोग सामने आ गए हैं। कोरोना को देखते हुए इन सभी ने फिलहाल सोशल मीडिया पर 'सेव बकस्वाहा फॉरेस्ट' कैंपेन चलाया है, लेकिन जैसे ही कोरोना संक्रमण थमेगा, ये सभी बकस्वाहा पहुंच जाएंगे। जरूरत पड़ी तो पेड़ों से चिपकेंगे। गत 9 मई को देशभर की 50 संस्थाओं ने इसके लिए वेबीनार किया और रणनीति बना ली है। इस बीच दिल्ली की नेहा सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है, जिसे सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। बिहार में पीपल, तुलसी और नीम लगाने के देशव्यापी अभियान से जुड़े डॉ. धर्मेंद्र कुमार कहते हैं कि कोरोना ने ऑक्सीजन की अहमियत बता दी है। राष्ट्रीय जंगल बचाओ अभियान से जुड़ी भोपाल की करुणा रघुवंशी ने बताया कि कई राज्यों के लोग जुड़े हैं। डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना के खत्म होते ही कैंपेन को एक्शन में लिया जाएगा।

हीरा खदान के लिए 62.64 हैक्टेयर जंगल चिन्हित है। नियम है कि 40 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के खनन का प्रोजेक्ट है तो उसे केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मंजूरी देता है। वन विभाग में लैंड मैनेजमेंट के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील अग्रवाल का कहना है कि इस प्रपोजल को केंद्र सरकार में भेजा जा चुका है, लेकिन अभी मंजूरी नहीं हुई है। उधर, पेड़ काटने का विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय युवकों ने विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर इसके लिए मुहिम छेड़कर इस प्रोजेक्ट को रोकने की मांग की है। वह इसके लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ई-मेल कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में भी एक पीआईएल दाखिल की गई है।

छतरपुर जिले के बकस्वाहा क्षेत्र में 20 साल पहले हुए सर्वेक्षण के बाद 3.42 करोड़ कैरेट हीरा मिलने का अनुमान जताया गया है। हाल ही में इसे आदित्य बिरला समूह को इसके लिए 382 हैक्टेयर क्षेत्र 50 साल की लीज पर दिया गया है। इसमें 62.64 हैक्टेयर में खनन किया जाना है। बाकी तकरीबन 200 हैक्टेयर क्षेत्र में खनन के दौरान उपयोग किया जाएगा। इस पर तकरीबन 2500 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करेगी। वन विभाग के मुताबिक इतने क्षेत्र में 2,15,875 पेड़ लगे हैं। 40 हजार पेड़ कीमती सागौन के हैं। इन सभी पेड़ों को काटा जाना है।

बड़ामलहरा क्षेत्र के तकरीबन 50-60 युवा सक्रिय रूप से इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं। स्थानीय युवा संकल्प जैन ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के बाद इस पूरे क्षेत्र में पर्यावरण का भारी विनाश होगा। उन्होंने बताया सैकड़ों साल उम्र वाले पेड़ों को काटा नहीं जाना चाहिए। इसके लिए सोशल मीडिया पर हम अभियान चला रहे हैं, इससे पूरे देश से तकरीबन एक हजार लोग जुड़ चुके हैं। तकरीबन 20 हजार से ऊपर ट्वीट किए गए हैं, एक बार फिर कैंपेन चलाया जाएगा। हमारी बातें नहीं मानी गई तो यहां भी चिपको आंदोलन शुरू किया जाएगा।

वन विभाग के सीसीएफ छतरपुर पीपी कटारे का कहना है कि हीरा खदान में जंगल काटने के बदले 382 हैक्टेयर राजस्व भूमि को वन भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है, इस भूमि पर ही जंगल विकसित किया जाएगा, इसका पूरा खर्च खनन करने वाली कंपनी ही उठाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्थानीय विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में एक पेड़ काटने के बदले 15 पेड़ लगाए जाएंगे, सरकार को रायल्टी मिले इसके लिए यह जरूरी हैं। विरोध करने वाले युवा इसे नाकाफी बता रहे हैं, उनका कहना है कि हाल ही में रायसेन जिले में दो पेड़ काटने के बदले एक युवक पर एक करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। जब वन विभाग इन पेड़ों को इतना मूल्यवान मान रहा है तो यहां लाखों पेड़ काटने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। स्थानीय वकील रमन जैन का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण का भारी नुकसान होगा, इसके लिए एनजीटी का निर्णय और गाइडलाइन महत्वपूर्ण होगा, जरूरत इस बात की होगी कि उन शर्तों को जमीनी रूप से पूरा-पूरा पालन करवाया जाए।

हीरे निकालने के लिए पेड़ काटने से पर्यावरण को भारी नुकसान होना तय माना जा रहा है। इसके अलावा वन्यजीवों पर भी संकट आ जाएगा। वन्यजीवों को लेकर मई 2017 में जियोलॉजी एंड माइनिंग मप्र और रियोटिंटो कंपनी ने एक रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में तेंदुआ, बाज, भालू, बारहसिंगा, हिरण, मोर जैसे वन्य जीवों का इस जंगल में होना पाया था लेकिन अब नई रिपोर्ट में इन वन्यजीवों के यहां होना नहीं बताया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह इसका विरोध हो रहा है, उससे शासन-प्रशासन की जमकर किरकिरी हो रही है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

भूमि उपयोग में आए बदलावों से 32 फीसदी जमीन हुई है प्रभावित

दुनिया में कहीं जंगलों को काटकर खेत बनाए जा रहे हैं, कहीं खेतों को हटाकर इमारतें और सड़कें बनाई जा रही हैं। बरसों से दुनिया में हर जगह भूमि में किसी न किसी रूप से बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन यह बदलाव कितनी जमीन को प्रभावित कर रहे हैं इस पर हाल ही में एक शोध किया गया है, जिससे पता चला है कि पिछले 6 दशकों के दौरान भूमि उपयोग में आ रहे बदलावों के चलते दुनिया की 32 फीसदी जमीन प्रभावित हुई है। यह बदलाव पिछले अनुमान की तुलना में चार गुना ज्यादा है। शोध के अनुसार 1960 से 2019 के बीच करीब 4.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बदलाव आया है, जिसका मतलब है कि 1960 से लेकर अब तक हर साल औसतन करीब 7.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बदलाव किया जाता है। यदि इस बदलाव के विस्तार का अनुमान लगाएं तो यह क्षेत्रफल में जर्मनी से करीब दोगुना बड़ा है। इस शोध में भूमि उपयोग में आए बदलावों को समझने के लिए उन्हें 6 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें शहरीकरण, कृषि, चारागाह, वनभूमि, घास से आच्छादित भूमि और भूमि जहां कोई वनस्पति नहीं है, वर्गों में विभाजित किया है।

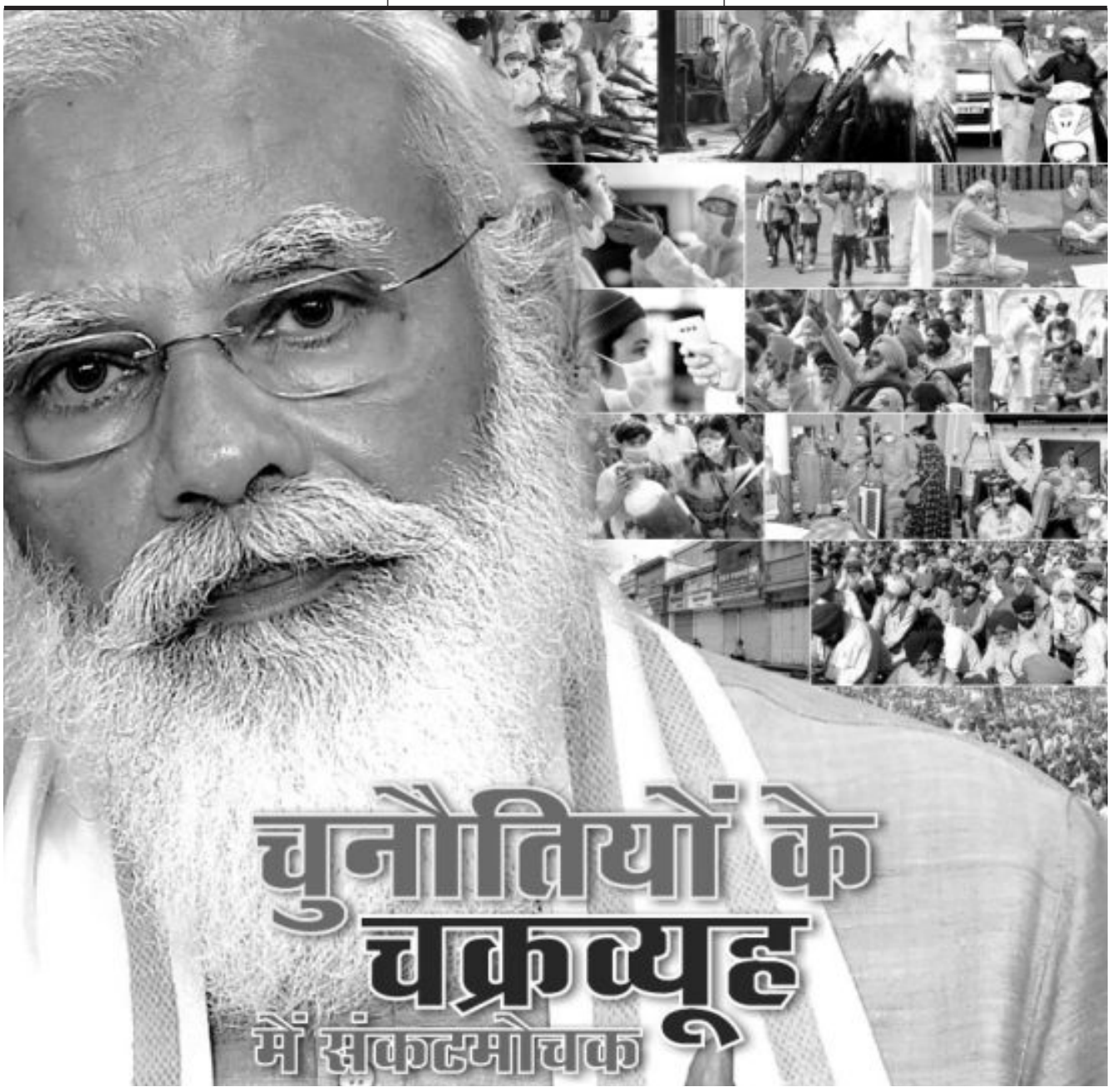

चुनौतियों के चक्रव्यूह में संकटमोचक ?

नरेंद्र मोदी की सर्व-शक्तिमान प्रधानमंत्री की जो छवि बड़े जतन से गढ़ी गई थी उसका भेद अब राजनीति के मैदान में भी खुलता जा रहा है। किसान आंदोलन और सीएए-विरोधी प्रदर्शनों से ये साबित हुआ कि कोई समूह चाहे छोटा मगर दृढ़ संकल्प वाला हो तो वो भी इस सरकार के खिलाफ मैदान में डटा रह सकता है। वहीं कोरोना संक्रमण ने संकटमोचक को चुनौतियों के चक्रव्यूह में फंसा दिया है, जिससे पूरी भाजपा अस्त-व्यस्त हो गई है।

● राजेंद्र आगाल

2014 में अच्छे दिन का सपना दिखाकर सत्ता में आई मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन न तो अच्छे दिन आए और न ही महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार से निजात मिली। उस पर कोरोना वायरस के संक्रमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही उनकी सरकार की साख को गिरा दिया है। भाजपा और मोदी का चमत्कार जितनी चमक के साथ शुरू हुआ था, उसमें उतनी ही तेजी से अंधेरा बढ़ रहा है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। वहीं कोरोना संक्रमण रोकने के मोर्चे पर सरकार पूरी तरह विफल हुई है। सरकार की विफलता का फायदा उठाने के लिए पूरा विपक्ष सरकार पर टूट पड़ा है। बड़ी-बड़ी समस्याओं और चुनौतियों से निपटने वाले संकटमोचक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनौतियों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। देखना यह है कि वे चक्रव्यूह को तोड़ पाते हैं या फंसे रहते हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोदी दूसरे गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने लगातार 7 साल अपनी सरकार के पूरे कर लिए हैं, लेकिन वाजपेयी सरकार के मुकाबले मोदी सरकार ज्यादा स्पष्ट बहुमत वाली मजबूत सरकार है और मोदी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। अपने पहले आम चुनाव साल 2014 में भाजपा को 282 सीटें मिलीं फिर 2019 के चुनावों के वक्त जब बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ अपने-अपने कयास और भाजपा के गिरते ग्राफ की संभावना जता रहे थे तब पिछली बार से भी ज्यादा ताकत 303 सांसदों के साथ मोदी ने वापसी की। कहने भर को यह एनडीए की सरकार है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से यह सिर्फ भाजपा की सरकार है और राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक इसे सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार कहा जाना चाहिए। अब तो भाजपा समेत ज्यादातर लोग मानते हैं कि इस सरकार में सारे निर्णय प्रधानमंत्री करते हैं, यहां तक कि सामूहिक नेतृत्व की औपचारिकता का दिखावा भी नहीं रह गया है।

प्रभामंडल मलिन हुआ

नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण करने के बाद से बीते 7 सालों में उनकी सरकार जितनी अभी कमजोर दिख रही है उतनी पहले कभी नहीं रही। सत्ता का जो प्रभामंडल बना चला आ रहा था वो अब क्षीण और मलिन होने लगा है। मोदी-भंजकों को लग रहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निपटने में भारी लापरवाही बरती गई, मरीजों की टेस्टिंग कम हुई, मौतों की संख्या कम करके बताई गई, तैयारी का अभाव रहा, ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हुई और टीकाकरण का मोर्चा ढीला-ढाला साबित हुआ।

इन बातों के सहारे मोदी-विरोधी मानकर चल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने महामारी की रोकथाम के काम में निर्दयता दिखाई। जो मोदी-भक्त हैं, उन्हें भी लग रहा है कि महामारी के इस भयावह वक्त में सरकार जैसी कोई शय जवाबदेही लेती दिखाई ही नहीं दी और इससे प्रधानमंत्री के सर्व-शक्तिमान होने का जो मिथक खड़ा किया गया था, उसकी चमक धूल-धूसरित हो गई है। मोदी-भक्तों के मन में शक की ये सुई अब चुभने लगी है कि प्रधानमंत्री के हाथ से चीजें महामारी की इस घड़ी में फिसलने लगी हैं और जितना ताकतवर वे जान पड़ते हैं, उतने हैं नहीं। मोदी सरकार की सफलताओं की लिस्ट यूं छोटी नहीं है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्रों में जिन वायदों की बात की, उन्हें पूरा करने की कोशिश सरकार ने की। चाहे वह जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने की बात हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मसला हो। नागरिकता संशोधन कानून को भी सरकार ने पास कराया और किसानों से जुड़े तीन कानून भी। नोटबंदी जैसे अहम फैसले भी मोदी सरकार ने किए तो आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक भी। जन-धन योजना से लेकर उज्ज्वला योजना तक और आप चाहें तो नेशनल हाईवे में तेज रफ्तार से होता काम भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा भी ढेरों योजनाएं और फैसले हैं जिन पर मोदी सरकार ने काम किया।

लगातार गिर रही साख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हुए हाल के सभी सर्वे एक जैसे ही नतीजे पेश कर रहे हैं। एग्जिट पोल की तरह ऐसा नहीं हो रहा है कि एक-दो सर्वे के रिजल्ट बाकियों से मेल नहीं खा रहे हों या उनके उलट हैं। मतलब ये कि मोदी सरकार या राज्यों की भाजपा सरकारों को मिल सकने वाले बेनिफिट ऑफ डाउट के चांस बहुत ही कम हो गए हैं। जनवरी में हुए एक सर्वे में 73 फीसदी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को बेहतर माना था। सर्वे में 23 फीसदी लोगों ने शानदार और 50 फीसदी लोगों ने अच्छा माना था। और ये तभी की बात जिसके कुछ ही दिन बाद मोदी सरकार ने कोरोना वायरस से मुकाबले में जीत का जश्न मनाया था, लेकिन तभी कोरोना की दूसरी लहर आई और सारी वाहवाही मिट्टी में मिल गई। वाजपेयी के दौर के एनडीए शासन की तरह ही मोदी काल में भी फील गुड का माहौल बन गया और इंडिया शाइनिंग की तरह एक बार फिर से सरकार और मोदी का प्रदर्शन शानदार बताया जाने लगा और तभी कोरोना ने ऐसा जोरदार झटका दिया कि सारा फील गुड हवा हवाई हो गया।

महामारी में खुली पोल

पिछले साल जब कोरोना महामारी ने पैर पसारने शुरू किए तब भी काम चल रहा था, लेकिन इस बार जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो सब कुछ साफ हो गया। केंद्र सरकार निशाने पर आ गई। स्वास्थ्य सेवाओं का चरमराता ढांचा और पिछले एक साल में तैयारियों की असलियत भी सामने आ गई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देशभर में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी, दवाओं का संकट, वेंटिलेटर और अस्पतालों में बैड की कमी के साथ डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ कुछ भी पर्याप्त नहीं था। लोग मर रहे थे। लाशों का ढेर दिखने लगा। श्मशानों में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं, तो कब्रिस्तान में दफन करने के लिए जगह नहीं बची। फिर नदियों में बहती लाशों ने तो हाहाकार मचा दिया। कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन अभियान की शुरुआत तो हुई, लेकिन राज्यों के पास वैक्सीन का संकट खड़ा हो गया। बार-बार वैक्सीन नीति को बदला गया। केंद्र में बैठे मंत्री और नेता विदेशी मदद से हवाई जहाजों से आते ऑक्सीजन टैंकरों और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के फोटो ट्वीट कर रहे थे लेकिन मैदान में कोई नहीं था। 'जान है तो जहान है' से 'जान भी जहान भी' का नारा देने वाली सरकार को ना लॉकडाउन खोलकर जहान को चलाने का रास्ता दिख रहा था और ना ही मरते लोगों की जान बचाने में कामयाबी मिल पाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने जब 'पॉजिटिविटी अनलिमेटड' के अपने भाषण में कहा कि पहली लहर के बाद 'गफलत' हो गई तो वो सरकार के लिए भी संदेश था।

आमतौर पर गलतियों की जिम्मेदारी तय करने की बात सरकारों में होती है ताकि लोगों को विश्वास हो सके कि आगे बेहतर होगा। 1962 के युद्ध में हार के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने वीके कृष्णा मेनन को हटा दिया और उनकी जगह वाईबी चव्हाण आए। लाल बहादुर शास्त्री ने तो रेल दुर्घटना के बाद खुद इस्तीफा दे दिया, वाजपेयी सरकार में नीतीश कुमार ने भी बतौर

रेल मंत्री ऐसा किया। मनमोहन सिंह सरकार में साल 2008 में 26/11 की घटना के बाद शिवराज पाटिल का इस्तीफा हो गया और पी चिदंबरम आए। इसका मतलब कोरोना संकट पर किसी मंत्री का इस्तीफा मांगने से नहीं है, लेकिन जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए।

सबकुछ ठीक नहीं

केंद्र सरकार अपनी पहली सालगिरह से अब तक हर साल अपनी वर्षगांठ बड़े जोर-शोर से और जश्न के साथ मनाती रही है, लेकिन इस बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस बार वे 'जश्न नहीं मनाएं' और 'सेवा करें' यानी 'जश्न से सेवा' तक पहुंचने की जरूरत इस बात का इशारा करती है कि अब पार्टी और सरकार को भी महसूस होने लगा है कि सब कुछ ठीक नहीं है।

कुछ सर्वेक्षणों में इस बात का इशारा किया गया है कि मोदी सरकार की लोकप्रियता में कमी आई है लेकिन यह अब भी 38 फीसदी से ज्यादा है यानी कोई दूसरा राजनीतिक दल उसके आसपास नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस अब सिर्फ नामभर के लिए है। संसद में उसकी ताकत कम है लेकिन देशभर में भी उसके कार्यकर्ताओं का जोश या विरोध दिखाई नहीं दे रहा। साल 2014 और 2019 के चुनावों में कांग्रेस को उन 90 फीसदी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा जिसमें उसका मुकाबला सीधे भाजपा से था। साल 2014 में इस मुकाबले में भाजपा ने जहां 88 फीसदी और कांग्रेस ने 12 फीसदी सीटें हासिल कीं, वहीं 2019 में यह 92 फीसदी और 8 फीसदी हो गया। लेकिन अब भी कांग्रेस ही देश में भाजपा के सामने सबसे बड़ी पार्टी है और उसे करीब 20 फीसदी वोट मिले हैं, जबकि भाजपा को 38 फीसदी वोट हासिल हुए। कांग्रेस के अलावा दूसरे कई बड़े विपक्षी दलों का कुल मिलाकर वोट भी 20 प्रतिशत नहीं होता। यानी अब कांग्रेस भाजपा से लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों को एकजुट करके यह लड़ाई जीत सकती है, यह उसे तय करना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के बजाय किसी और को नेतृत्व सौंपा गया तो कांग्रेस बची-खुची हालत को संभालने लायक भी नहीं रहेगी। पश्चिम बंगाल में ममता की जीत ने भाजपा के विजय रथ को ही नहीं रोका बल्कि यह भी बता दिया कि कोई भी ऐसा नहीं, जो अजेय हो।

अगले एक साल तक आर्थिक चुनौतियों से घिरा रहेगा देश?

पिछले दो साल से कोरोना ने न केवल भारत और विश्व की हेल्थ पर असर डाला है, बल्कि विश्व की आर्थिक स्थिति को भी डांवाडोल कर दिया है। भारत की आर्थिक स्थिति की विश्व में अपकमिंग इकोनॉमी या ऐसे राष्ट्रों में गिनती होती है जहां आर्थिक उन्नति की अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन कोरोना ने इस आर्थिक उन्नति पर बड़ा बुरा प्रभाव डाला है। 90 के दशक में जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने भारत में मुक्त इकोनॉमी की स्थापना की थी उसके बाद से भारत लगातार आर्थिक उन्नति करता आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों से जहां भारत आर्थिक उन्नति कर रहा है, वहीं ढेर सारी आर्थिक चुनौतियों की भी कमी नहीं है। पिछले 7 साल से भाजपा सरकार ने राष्ट्र पर अपनी पकड़ बना रखी है और प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक उन्नति को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। नरेंद्र मोदी की राष्ट्र पर पकड़ बहुत अच्छी है और वह युवा शक्ति के बल पर दो बार सत्तासीन हुए। नरेंद्र मोदी के मन में राष्ट्र को लेकर बहुत सारे सपने हैं और वे हर तरीके से नए भारत का निर्माण करना चाह रहे हैं। पुरानी परंपराओं और नीतियों में उनकी कतई आस्था नहीं है और वे अपने सपनों का भारत बना रहे हैं।

धीरे-धीरे गिर रही साख

साल 2024 के आम चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन इससे पहले 16 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें अगले साल 7 राज्यों में वोट पड़ेंगे, उनमें सबसे अहम और सबसे बड़ा राज्य उप्र है। उप्र के अलावा अगले साल फरवरी में उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में, फिर साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। गुजरात में पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से भाजपा सरकार बना पाई थी। उत्तराखंड में हाल में मुख्यमंत्री को बदला गया है, पंजाब में कोई संभावना फिलहाल नहीं दिखती। साल 2023 में 9 राज्यों- मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में फरवरी में, मई में कर्नाटक में और दिसंबर में राजस्थान, मप्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों में पिछले चुनावों से भाजपा को बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि साल 2024 में मोदी को 'हैट-ट्रिक' लगाने से रोका जा सकता है, फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। भाजपा को हराने के लिए ज्यादातर लोग एक संयुक्त विपक्ष की पैरवी करते हैं, लेकिन भारत में संयुक्त विपक्ष के प्रयोग बहुत सफल नहीं रहे हैं, चाहे वो 1967 में संयुक्त विपक्षी दल हों, 1977 में जनता पार्टी का प्रयोग हो, या फिर 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल और फिर 1996 में तीसरा मोर्चा या बाद में संयुक्त मोर्चा। सच यह भी है कि इन प्रयोगों की असफलता के बावजूद इस तरह के गठजोड़ ने ही केंद्र में एक पार्टी के शासन को खत्म किया है, इसमें 400 से ज्यादा सीटों वाली राजीव गांधी सरकार भी शामिल है।

विपक्ष को मोदी की ताकत को समझना होगा, वो हिंदुस्तान की राजनीति के 'फीनिक्स' हैं, उन पर निजी हमले, मोदी को ताकतवर बनाते हैं। चाहे वो 2007 के गुजरात चुनावों में सोनिया गांधी का 'मौत का सौदागर' का बयान, 2014 में मणिशंकर अय्यर का 'चायवाला' और फिर 2019 से पहले राहुल गांधी का 'चौकीदार चोर है', का अभियान। अब फिर कांग्रेस ने मोदी के एक कार्यक्रम में 'आंसुओं' का मजाक बनाया है। राहुल गांधी के 'मगरमच्छ निर्दोष है', का हमला मोदी को ताकत देगा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पर निजी हमले किए गए। अभी ममता बनर्जी के खिलाफ जैसा अभियान भाजपा ने चलाया, उसका नतीजा भी सामने है। इस वक्त सरकार पहली बार अपने कामकाज को लेकर कटघरे में हो तो उसकी नीतियों पर हमला करने के बजाय मोदी पर व्यक्तिगत हमले राजनीतिक तौर पर

नुकसान करेंगे। बहुत से लोग अभी मोदी सरकार के कामकाज से नाराज है, लेकिन मोदी पर व्यक्तिगत हमला उन्हें 'चक्रव्यूह का अभिमन्यु' बनाते हैं और समर्थक ज्यादा ताकत से उनके साथ खड़े हो जाते हैं।

योग्य टीम नहीं

पिछले कार्यकाल की तरह मोदी के पास अरुण जेटली जैसा 'राजनीतिक सलाहकार' नहीं है, अनुभवी नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह पर भरोसा शायद नहीं किया जाता, लेकिन अमित शाह एक 'मजबूत दीवार' की तरह उनके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के पास ना एकजुटता है, ना विश्वसनीय नेतृत्व और ना ही कोई उम्मीद भरा कार्यक्रम। विपक्ष के पास संघ जैसा मजबूत संगठन भी नहीं है और जयप्रकाश नारायण जैसा ईमानदार नेता या फिर हरकिशन सिंह सुरजीत जैसा राजनीतिक शतरंज का खिलाड़ी। आज 'मोदी है तो मुमकिन है' के नारे की चमक भले ही कम हुई हो, लेकिन 'आएगा तो मोदी ही' की गूंज अभी बाकी है। मगर इतना तय है कि जब जनता तय कर लेती है कि 'सिंहासन खाली करो' तो फिर कोई नहीं टिक पाता।

साल 2019 के चुनावों में एनडीए के 44 फीसदी वोटों के मुकाबले यूपीए को 26 फीसदी वोट मिले थे। क्या विपक्षी पार्टियां इस फैसले को कम करने के लिए तैयार दिखती हैं? मोदी सरकार की 'हैट-ट्रिक' में मुश्किलें फिलहाल नहीं लगतीं बशर्ते वो 'डिनायल मोड' में नहीं रहे। सत्ता को अक्सर आलोचना पसंद नहीं होती, लेकिन ना जाने क्यों मुझे सआदत हसन मंटो की कही वो बात याद आ रही है कि – 'मेरे अफसाने नहीं, जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है।'

महंगाई अनकंट्रोल

70 साल पहले जब देश सैंकड़ो वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। उस समय तो फ्री या अतिरिक्त लाभ देने की योजनाएं जो गरीब तबके को थी वो एकदम जायज थीं क्योंकि इतने वर्षों की गुलामी के बाद सबसे ज्यादा पीड़ित और दबा हुआ जो समाज था वो गरीब या साधनहीन समाज ही था। इतने वर्षों में कई पार्टियों की सरकारें आईं लेकिन जो लालच देकर वोट लेने की परंपरा है उसमें सभी पार्टियां बराबर की हिस्सेदार हैं। जिस देश की युवा शक्ति 70 प्रतिशत हो वहां पर देश के नेताओं की ऐसी सोच निसंदेह विचारणीय है। वर्तमान में देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी मालूम नहीं पड़ती। रोजगार है नहीं, हमारे लाखों युवा पढ़-लिखकर बेकार बैठे हुए हैं। कोरोना ने आम आदमी की कमर तोड़ दी, खासतौर से पिछले दो साल से। नौकरी का अभाव तो है ही साथ ही जिनकी नौकरियां है उनकी तनख्वाह कट चुकी है।

मंहगाई शेषनाग की तरह फन फैला रही है।

पहली बार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निशाने पर केंद्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की गिरती साख का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाईकोर्ट के निशाने पर केंद्र सरकार रही। कोरोना वायरस के संक्रमण की तेज रफ्तार और महामारी को लेकर मचे कोहराम पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि महामारी से निपटने के लिए आपके पास क्या तैयारी है और क्या योजना है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसका जवाब मांगा। इसी तरह ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, टीकाकरण को लेकर भी अदालतों ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। दरअसल, केंद्र सरकार कई मामलों में मनमानी और पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। इसको लेकर राज्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उधर, केंद्र कोरोना संक्रमण और ऑक्सीजन को लेकर लगातार गलत बयानी कर रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। यही नहीं कोर्ट ने सरकार को यहां तक कह दिया था कि अगर कोरोना मैनेजमेंट नहीं संभल रहा है, तो वह आईआईएम और आईआईटी को सौंप दे। जानकारों का कहना है कि भारतीय इतिहास में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी अन्य सरकार को इस तरह की बात नहीं कही है। पिछले कुछ महीनों से केंद्र सरकार लगातार अदालतों के निशाने पर है। इससे मोदी और सरकार के प्रति लोगों का विश्वास उठता जा रहा है।

देखते ही देखते पेट्रोल 100 पार कर गया। डीजल भी जल्दी ही पेट्रोल के भाव को पकड़ने वाला है। दाल और जरूरत की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। एक जमाना था अक्सर सोने-चांदी के भाव घटते या बढ़ते थे। लोग आपस में इसकी बड़ी चर्चा करते थे कि सोना महंगा हो गया और चांदी सस्ती हो गई। अब बातें होती हैं पैट्रोल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। अब तो सरसों आदि के तेल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। आम आदमी के पास रोजगार नहीं है और खाने के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन स्टाक मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। अगर यही सब चलता रहेगा तो राष्ट्र की उन्नति का तो पता नहीं लेकिन आम आदमी अवश्य ही रसातल में चला जाएगा।

युवा के पास रोजगार नहीं

रोजगार का अकाल पड़ा हुआ है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बाजार आदि पर आप कुछ बुक करके तो देखिए वहां पर भी आपको पुराने दिनों की राशन की दुकान की भीड़ की याद आ जाएगी। छोटे-बड़े शहर की किसी भी रोड पर देखिए आपको कोई युवक अपने कंधे पर किसी कंपनी का बहुत बड़ा बैग लादे हुए अर्जुन के तीर की तरह सीधा सामान की डिलीवरी करने चला जा रहा है। इस तरह का रोजगार बहुत है लेकिन देश की युवा शक्ति का उसके उत्थान के लिए कार्य नहीं हो रहा। कंपनी को प्रमोट करने का माहौल अवश्य बना हुआ है। युवक को कंपनी की तरफ से कोई लाभ नहीं मिलता और अगर सामान की डिलीवरी समय पर नहीं हो तो उसे निकाला भी जा सकता है। निसंदेह कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त कर दी है लेकिन अब संभालने का कार्य भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है।

जिस देश के पास 70 प्रतिशत से अधिक युवा हों और पूरी दुनिया इस देश की और टकटकी लगाए देख रही हो। अगर विश्व में कोई कमाल करेगा तो वो भारत का युवा ही होगा। हमारे देश के प्रत्येक युवा के मन में अपार उत्साह है और वो कुछ भी करने को तैयार है। भारत की आजादी से पहले चंद युवाओं- भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू आदि ने एक क्रांति का जो बीज बोया था वो देश की आजादी में बहुत सहायक सिद्ध हुआ था। देश स्वतंत्र है, युवा स्वतंत्र है और आसमान छूने को लालायित है। यदि वर्तमान सरकार या सरकारें प्रत्येक युवक को कोई सकारात्मक कार्य दे तो भारत की आर्थिक स्थिति बदलते देर नहीं लगेगी।

कौन कराएगा रास्ता पार

विपक्षी एकता की कोशिश में अब तक जो सबसे बड़ा अवरोध रहा है, वह ये कि इसे अंजाम तक कौन ले जाएगा? कई विपक्षी नेताओं का मानना है कि इस कोशिश को वही सर्वमान्य चेहरा आगे बढ़ा सकता है, जिसकी देश के तमाम क्षेत्रीय विपक्षी दलों के नेताओं से अच्छी बनती हो, साथ ही कांग्रेस के अंदर भी नेताओं के साथ उसके बेहतर संबंध हों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम इसके लिए सबसे आगे बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि वह भी इसके लिए एक मजबूत धुरी बन सकते हैं। ममता बनर्जी के अलावा अभी संपन्न हुए चुनाव में तमिलनाडु में वह स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके की भी रणनीति बना रहे थे। इससे पहले वह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के साथ चुनावी रणनीति पर काम कर चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की सेवा लेने का ऐलान किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सहित उनके लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं से भी करीबी संबंध रहे हैं। 2015 में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को एक साथ लाने का श्रेय भी प्रशांत किशोर को ही गया था। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव में एसपी-कांग्रेस गठबंधन की बुरी तरह हार हुई थी, फिर भी वह अखिलेश यादव और राहुल गांधी को एक मंच पर लाने में सफल रहे थे। कांग्रेस के कई नेताओं के साथ भी उनके करीबी संबंध हैं।

गुजरात कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया था कि 2022 के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी सेवा लें। एक सीनियर कांग्रेसी नेता ने बताया कि अगर प्रशांत किशोर का सही ढंग से उपयोग किया गया तो 2024 से पहले वह विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। हालांकि बंगाल चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीति का काम छोड़ देने का ऐलान किया है, ऐसे में वह इस काम को किस तरह करेंगे, अभी इस बारे में सीन साफ नहीं है। लेकिन सूत्रों के अनुसार विपक्ष के कई नेता उनसे लगातार संपर्क में हैं। प्रशांत किशोर के करीबियों के अनुसार अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उनके अनुसार कोरोना संकट झेल रहे देश में अभी इस बारे में बात करना उचित नहीं है। अभी अगले आम चुनाव में वक्त भी है और अगले कुछ महीनों में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम भी आगे की राह तय करेंगे। जानकारों के अनुसार अगले साल के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव का रुख भी बहुत कुछ तय करेगा। अगले साल की शुरुआत में उप्र के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन अभी के संदर्भ में इतना तय माना जा रहा है कि अगर विपक्षी एकता की गंभीर कोशिश हुई, तो इसमें प्रशांत किशोर की अहम भूमिका की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

किसान आंदोलन ने जता दिया है कि इस सरकार को कदम पीछे खींचने की हालत में लाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के नतीजों ने प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी की चुनाव-जिताऊ कौशल की बखिया उधेड़ दी है। 7 सालों तक बेरोक और बेलगाम शक्ति-संसाधन के बाद मोदी सरकार को उस सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है जो हमेशा अधिनायकवादी शासकों को सताते आई है- सत्ता ठहरती नहीं, फिसलती जाती है और परम सत्ता तो चरम गति से फिसलती है। वक्त के इस मुकाम पर मोदी सरकार बहुत कुछ वैसी ही दिख रही है जैसा कि मनमोहन सिंह की सरकार अपनी दूसरी पारी में दिखी थी, इस सरकार के दिन 2012 से लदने शुरू हो गए थे। किसी को लग सकता है कि प्रधानमंत्री अपनी चमक गंवा चुके हैं और कुशासन तथा गड़बड़ियों को ढंकने के लिए झूठ का जो जाल बुना गया है, उसके बोझ तले सरकार भरभरा सकती है।

विपक्ष अभी भी असंगठित और कमजोर

पिछले कुछ सालों से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों की एकता की कई कोशिशें हुईं, जो बयानों तक ही सीमित रहीं। अब, जबकि मोदी सरकार ने 7 साल पूरे कर लिए हैं, और कोरोनाकाल में पहली बार भाजपा को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की पुरानी सियासी हसरत जवान होती दिख रही है। चाहे किसान आंदोलन को समर्थन देने का मसला हो या कोविड मैनेजमेंट पर सरकार से मांग का, पिछले कुछ दिनों में कई मौकों पर विपक्षी दलों ने एक स्वर में संदेश देने की कोशिश की है कि बड़े मसलों और भाजपा की नीतियों के खिलाफ वे एक हैं। अभी पिछले हफ्ते जब किसान आंदोलन को समर्थन देने की बात आई, तो 12 अहम दलों ने एक साथ अपील की। इनमें सोनिया गांधी के अलावा ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एचडी देवेगौड़ा, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी जैसे नेता शामिल रहे। तो क्या इस बार विपक्षी एकता गंभीरता से आगे बढ़ेगी? इस सवाल का जवाब जानने से पहले कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के समीकरण देखने होंगे। यह सियासी तथ्य है कि दक्षिण या उत्तर में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, वे कांग्रेस के पतन की कीमत पर ही उभरे हैं। जिन-जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर होती गई, वहां-वहां क्षेत्रीय दलों का उभार बढ़ता गया।

संजीवनी बनेगा पर्यटन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प और साहसी निर्णयों ने आज मप्र को विकासशील राज्य की अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा किया है। उनके प्रयासों और संकल्प से आज पर्यटन क्षेत्र आत्मनिर्भर मप्र की संजीवनी के रूप में उभरा है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मप्र एक दूसरे के पूरक है। नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य और अद्‌भुत स्थापत्य कला के धनी मप्र का गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति पूरे भारत में अद्वितीय है। जिस तरह हीरे की असली परख जौहरी को ही होती है उसी तरह मप्र में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार और विकास की असीम संभावनाओं को तलाशने का हुनर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में ही है। उन्होंने न सिर्फ प्रदेश के नैसर्गिक और लुभावने स्थलों को पर्यटन के लिए विकसित किया बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा किए। अब पर्यटन सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा बल्कि रोजगार, स्थानीय संस्कृति और खान-पान, कला और स्थापत्य कला का केंद्र-बिंदु भी बनके उभरा है।

मुख्यमंत्री के निर्देशन में पर्यटन विभाग ने कोविड के बाद की परिस्थितियों के अवसरों को तलशाना जारी रखा। नित नए प्रयासों और नवाचारों से मप्र में पर्यटन की संभावनाओं को ढूंढने के उद्‌देश्य को लेकर सतत प्रयास किया। पर्यटन के प्रमुख क्षेत्र वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, लेइश्यरू टूरिज्म और पिलग्रिमेज टूरिज्म की सभी संभावनाओं को विकसित किया गया। सभी उम्र के व्यक्तियों की रूचियों को ध्यान में रखकर गतिविधियां आयोजित की गई। रूरल टूरिज्म, हेरिटेज वॉक, इंस्टाग्राम मांडू टूर, साइकिल टूर, आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार, म्यूजिकल कंसर्ट और फूड बाजार जैसे नवाचार किए गए।

मप्र एडवेंचर टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनके उभरा है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और मनभावन वातावरण अनायास ही ट्रेकिंग, सफारी और कैंपिंग के शौकीनों को आकर्षित करता है। एडवेंचर टूरिज्म की इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग ने प्रदेशभर में 30 से ज्यादा कैंपिंग साइट विकसित किए हैं। पर्यटकों के हॉलिडे को एक्टिव हॉलिडे में परिवर्तित करते हुए टूर-डे सतपुड़ा, हेरिटेज रन, पचमढ़ी मॉनसून मैराथन जैसे कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बैलून सफारी, टाइग्रेस ऑन ट्रेल और भोपाल में प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा की स्थापना आदि प्रमुख नवाचार रहे हैं। वर्तमान में भी मप्र को 365 डेज का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का संकल्प लेकर सतत प्रयास किए जा रहे हैं। वार्षिक आयोजनों की श्रृंखला में 5 जल महोत्सवों और ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया है। वेब सीरीज पंचायत, गुल्लक और धाकड़ के फिल्मांकन से मप्र में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इसी दिशा में ग्रामीण पर्यटन की संकल्पना पर वैल्यू फॉर मनी डेस्टिनेशन के विकास कार्य में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाया जाएगा। इससे क्षेत्र विशेष की संस्कृति और धरोहर से पर्यटक परिचित हो सकेंगे। मप्र को वैलनेस एंड माइंडफुल टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी निरंतर प्रयास जारी है। इसमें पर्यटकों को पर्यटन के साथ योग, ध्यान और नेचुरोपैथी आदि से जोड़ा जाएगा। साथ ही आस-पास टूरिज्म की अवधारणा पर पड़ोसी राज्य के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए छोटी अवधि के टूर प्लान बनाए गए हैं।

सहकारी साख आंदोलन में अपेक्स बैंक की भूमिका

मप्र के सहकारी साख आंदोलन को सफल बनाने में समन्वयक की भूमिका के रूप में प्रदेश स्तर पर मप्र राज्य सहकारी बैंक अपनी 24 शाखाओं एवं जिला स्तर पर 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों तथा प्राथमिक स्तर पर अपनी 4523 पैक्स (प्राथमिक सहकारी साख समितियों) के माध्यम से कृषि एवं सहकारी

क्षेत्र से जुड़े लोगों के जनकल्याण के लिए सहकारी भावना से समर्पित होकर निरंतर कार्य कर रहा है एवं सहकारी साख के सतत् विस्तार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं मप्र शासन के सहकारिता विभाग के दिशा-निर्देशों से सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ व पारदर्शी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में मप्र शासन के निर्देशों को क्रियान्वित करने की दिशा में सहकारिता विभाग के नोडल एजेंसी बनने पर समन्वयक के रूप में अपेक्स बैंक द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण एवं विभिन्न कृषि आदानों का वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ता सामग्री वितरण यथा केरोसीन, खाद्यान्न का वितरण भी संपूर्ण प्रदेश में किया जाता है। कृषकों की फसल के उचित मूल्य के लिए उपार्जन का कार्य भी संपादित किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के समय प्रदेश में लॉकडाउन होने के बावजूद सहकारी समितियों ने विषम परिस्थितियों में गेहूं का लगभग 4500 उपार्जन केंद्रों पर उपार्जन किया तथा मप्र को पहली बार देश में प्रथम पायदान पर पहुंचा, जबकि गत वर्षों में पंजाब व अन्य राज्य आगे रहा करते थे। मप्र शासन के निर्देशानुसार अपेक्स बैंक द्वारा समन्वयक के रूप में मप्र में सहकारी समितियों के माध्यम से गेहूं, चना, सरसों एवं मसूर की खरीदी का रिकॉर्ड बनाते हुए वर्ष 2020-21 में 1 करोड़ 29 लाख टन गेहूं के साथ 8 लाख 23 हजार टन चना, सरसों और मसूर की भी खरीदी की गई।

कोई मुकाम हासिल करने से मुश्किल उसे कायम रखना होता है। एक मुकाम हासिल होने के बाद दूसरे की चिंता भी खाए जाती है और अगले मुकाम तक पहुंचने से पहले ही उसे लेकर मन में उमड़ते-घुमड़ते ख्वाब फिक्र बढ़ा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों की ही हाल की गतिविधियों पर गौर करें तो ये सब दोनों ही नेताओं में कॉमन लगता है।

झगड़ा नहीं, ये तो रगड़ा है!

पश्चिम बंगाल का चुनाव भी ममता बनर्जी ने वैसे ही केंद्र की मजबूत सरकार को शिकस्त देते हुए जीता, जैसे नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन ताकतवर सरकार के खिलाफ 2014 में चुनावी जीत हासिल की थी। तब देश में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। फिलहाल नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री हैं, और उनके लिए इससे खराब बात क्या होगी कि जिस मनमोहन सरकार को कोसते हुए वो दिल्ली पहुंचे, पहुंचने के बाद उनके सामने भी भविष्य वैसा ही चुनौतीपूर्ण नजर आने लगा हो और आगे ऐसी ही किसी के धाव बोल देने की आशंका हो जो ठीक वैसा ही व्यवहार उनसे करने को पहले से ही आतुर हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सबसे भरोसेमंद कैबिनेट साथी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के लिए पश्चिम बंगाल चुनाव का रिजल्ट बिलकुल 2015 के बिहार चुनाव जैसा रहा, और मुश्किल ये है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास तात्कालिक तौर पर कोई कमजोर कड़ी भी नजर नहीं आ रही है, जैसी तब नीतीश कुमार के केस में तेजस्वी यादव के चलते लालू प्रसाद यादव रहे। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की अरसे से जारी आपसी जंग पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आने के साथ खत्म नहीं भी हुई तो कुछ दिन के लिए नरम पड़ जाएगी, लेकिन ये तो बढ़ती ही चली जा रही है। कहीं इसकी असली वजह दोनों के भीतर बस चुकी कोई गहरी असुरक्षा की भावना तो नहीं है? एक दौर रहा जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हद से ज्यादा आक्रामक देखने को मिलता था, ये तब की बात है जब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को मनोरोगी और कायर बताया करते थे और राहुल गांधी खून की दलाली जैसे इल्जाम लगाया करते थे। ऐसा भी दौर देखने को मिला जब एनडीए से बाहर होते हुए नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हमलावर देखे जाते, लेकिन बाद के दिनों में, खासकर दिल्ली चुनावों के नतीजे आने के बाद अरविंद केजरीवाल हनुमान जी के ऐसे भक्त हुए कि कभी-कभी तो शक होने लगता था कि वो अरविंद केजरीवाल ही हैं या फिर अचानक से चिराग पासवान बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल हाल फिलहाल ऑक्सीजन को लेकर राजनीतिक चालें तो तेज चले हैं, लेकिन उनके मुकाबले ममता बनर्जी के तेवर काफी तेज हो चुके हैं। ये तो पहले से ही लग रहा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे कुछ भी होने की स्थिति में ममता बनर्जी केंद्र की मोदी सरकार के प्रति ज्यादा उग्र रूप धारण कर सकती हैं, लेकिन ऐसा तो कतई नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में हद से ज्यादा दिलचस्पी लेते रहेंगे।

तृणमूल कांग्रेस नेताओं से सीबीआई के पूछताछ और जेल भेजे जाने के बाद तो तस्वीर और भी साफ हो चुकी है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि जिस घोटाले में आरोपियों की सूची में मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी के भी नाम हों, तो सिर्फ टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी क्यों हुई? अपने अफसरों के बिल्लियों की तरह लड़ने के लिए चर्चित रही, सीबीआई लगता है फिर से तोता बनकर पिंजरे में लौट गई है। ममता बनर्जी तो कोविड-19 से पैदा हालात पर प्रधानमंत्री की बुलाई हुई पिछली दो मीटिंग से भी नदारद रहीं, जब खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी देशभर के कुछ जिलाधिकारियों से कोरोनावायरस संकट को लेकर बात करने वाले हैं तो भी तृणमूल कांग्रेस नेता ने विरोध जताया था और विरोध की उसी राह पर चलते हुए वो कोविड पर मुख्यमंत्रियों की लेटेस्ट मीटिंग में पहुंच गईं। दरअसल, ममता बनर्जी को अपने जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री मोदी के साथ

2024 की टेंशन, दो पैरों से दिल्ली कैसे जीतेंगी

बेशक ममता बनर्जी ने एक पैर से बंगाल जीत लिया हो, लेकिन अगर दो पैरों से दिल्ली जीतने की बात कही है तो उसका तनाव भी तो सवार होगा ही। ममता बनर्जी को मालूम होना चाहिए कि अगर देश के लोग कोरोनाकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हो सकते हैं तो पश्चिम बंगाल के लोगों के पास उनसे कहीं ज्यादा ही नाराज होने के चांस हैं, क्योंकि उनके पास भाजपा को सत्ता सौंपने का विकल्प था, फिर भी लोगों ने ममता बनर्जी को ही मौका देने का फैसला किया। अगर ममता बनर्जी ने निराश किया तो उनके मन में बंगाल में डबल इंजिन की सरकार न होने का अफसोस बैठने लगेगा और भाजपा तो घात लगाकर बैठी ही है। कहीं ऐसा न हो दिल्ली दूर ही रहे और बंगाल भी हाथ से फिसल जाए? अब ऐसा ही लगता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों के मन में असुरक्षा की भावना बलवती होने लगी है और दोनों के बीच फिलहाल जो भी राजनीति संघर्ष देखने को मिल रहा है वो तो इनसिक्योर होने का ही नतीजा लगता है।

मीटिंग से रोकना था। अगर वो खुद नहीं जातीं तो भला जिलाधिकारियों को मीटिंग से रोकने के लिए क्या तर्क देतीं। वो भी तब जबकि भाजपा शासित राज्यों के साथ-साथ गैर-भाजपा सरकारों वाले राज्यों के डीएम मीटिंग में हिस्सा ले रहे हों। ममता बनर्जी ने पहले ही ऐसी मीटिंग को राज्यों के अधिकार और संघीय ढांचे में केंद्र के दखल की संज्ञा दे डाली थी और मीटिंग के बाद साफ किया कि जब वो खुद मौजूद थीं तो जिलाधिकारियों के होने की क्या जरूरत थी। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन से परहेज और ऑक्सीजन, अस्पतालों के इंतजाम और जरूरी दवाइयों पर खामोश रवैया अख्तियार किए रहने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी का सीधे जिलाधिकारियों से फीडबैक लेना या मन की बात करना भी कोई ठोस पहल जैसा तो नहीं लगता। अब पटना के डीएम अपवाद हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण की समीक्षा के दौरान पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खास ऐप की जानकारी दी तो वो उनको काफी पसंद आया और वो बोले कि ऐप को अपडेट कर पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

मोदी के साथ मीटिंग के बाद ममता बनर्जी तो आगबबूला नजर आईं ही, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला। रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर अशोभनीय आचरण प्रस्तुत करने का आरोप तो लगाया ही, ये भी कहा कि ममता बनर्जी ने पूरी बैठक को एक तरह से पटरी से उतारने की कोशिश की। ममता बनर्जी का तो रविशंकर प्रसाद के उलट ही इल्जाम रहा, 'अगर राज्यों को बोलने नहीं दिया जाता तो उन्हें बुलाया क्यों जाता है? सभी मुख्यमंत्रियों को विरोध करना चाहिए कि मीटिंग में बोलने की इजाजत नहीं दी गई।' अब एक सहज सा सवाल ये उठता है कि आखिर ये बंगाल की लड़ाई है या दिल्ली की गद्दी को लेकर जंग छिड़ चुकी है? क्या मोदी अब ममता बनर्जी को अपने लिए भी चुनौती मानने लगे हैं?

किसी को भी कोई शक शुबहा नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी 2002 के बाद अपने राजनीतिक कैरियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अब तक तो मोदी सरकार पर सिर्फ राजनीतिक विरोधी ही अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल बना देने के आरोप लगते रहे, लेकिन अब तो धीरे-धीरे आम लोगों के मन भी संकटकाल में बेपरवाह सरकार जैसी भावना घर करने लगी है। जाहिर है सारे फीडबैक मोदी को तो मिलते ही होंगे क्योंकि मोदी सरकार में कभी राजधर्म की याद दिलाने वाले वाजपेयी के दौर जैसे इंडिया शाइनिंग वाले फील गुड फैक्टर तो गायब ही लगते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेतृत्व को मिले जख्म असम की सत्ता में वापसी कर लेने से थोड़े कम जरूर हुए होंगे, लेकिन बड़ी टेंशन

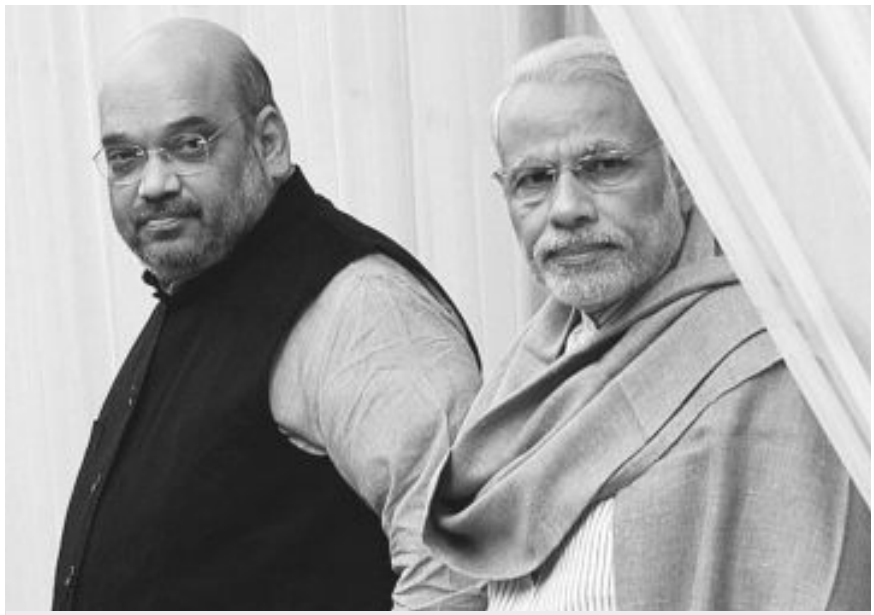

मोदी को छवि की चिंता

ब्रांड मोदी क्या है, नरेंद्र मोदी की छवि ही तो है। हिंदू हृदय सम्राट की छवि। देश के मजबूत नेता की छवि। छवि जिसके साये में बहुसंख्यक हिंदू समाज किसी मुस्लिम आतंक की आशंका से खुद को महफूज महसूस करता है। छवि ऐसी कि आम चुनाव के पहले से ही लोगों के मन में ऐसी भावना जगने लगी थी कि मोदी के सत्ता में वापसी के साथ ही पाकिस्तान का नामोनिशान तक मिट जाएगा। मुश्किल ये है कि बिहार चुनाव के दौरान मूड ऑफ द नेशन सर्वे में अपनी लोकप्रियता के शिखर पर रहे प्रधानमंत्री मोदी, रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एकसाथ दो-दो सर्वे में उनका पॉप्युलरिटी ग्राफ गिरते हुए दर्ज किया गया है। डेटा इंटेलीजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट और भारत के सी-वोटर सर्वे दोनों के हिसाब से नरेंद्र मोदी की छवि बीते सात साल में सबसे ज्यादा धूमिल पाई गई है।

तो मिशन 2022 है। अगले साल की शुरुआत में भाजपा को उप्र, उत्तराखंड और आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सत्ता हाथ से फिसलने से बचाने की चुनौती है। किसान आंदोलन के बीच पंचायत चुनाव के नतीजों ने पंजाब से तो उम्मीदें भी खत्म कर दी होंगी, लेकिन गोवा के ताजा हालात और मणिपुर की अंदरूनी उठापटक की चिंता भी तो खाए ही जा रही होगी।

2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उप्र चुनाव हैं। जहां पंचायत चुनावों में शिक्षकों की मौत पर मुआवजे का विवाद भुला भी दें तो नतीजों जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है और भाजपा अयोध्या, काशी और मथुरा में जूझती नजर आई है। संकेत तो तकरीबन साफ-साफ ही हैं। हालात तो यही कह रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में बेकाबू हो चुके हालात के चलते हर तरफ से फेल साबित हो रहे योगी आदित्यनाथ को भी कुर्सी बचाए रखने के लिए अयोध्या की दिवाली और राम मंदिर निर्माण से कहीं ज्यादा ब्रांड मोदी के आसरे ही उम्मीद बची होगी, लेकिन जब ब्रांड मोदी ही बेअसर होने लगे तो क्या आस लगाई जाए? ये तो पानी की तरह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने 2024 से पहले किसी तरह का खतरा नहीं है। शिवसेना और अकाली दल की तरह बचे हुए सहयोगी एनडीए छोड़ दें तब भी। कांग्रेस और राहुल गांधी को तो भाजपा पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज ही समझने लगी थी, लेकिन ममता बनर्जी के रूप में जो नया खतरा उभर रहा है वो तो दिल की धड़कन बढ़ाने वाला ही है। और वैसे भी अब राम मंदिर जैसा कोई ठोस और वोट दिलाने वाला मुद्दा भी आगे के लिए नहीं है। और सर्जिकल स्ट्राइक का भी बार-बार स्कोप थोड़े ही होता है। कहां लगातार चुनावी हार के चलते सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बोलती बंद हो चुकी थी। कहां कांग्रेस नेतृत्व मोदी-शाह के लिए चुनौती पेश कर पाता कि अंदर ही जी-23 की बगावत शुरू हो गई थी। कहां कोरोना संकट पर विजय प्राप्ति के डंके पीटे जा रहे थे कि कोविड-19 के दूसरे दौर ने अचानक ही धावा बोल दिया और जहां-जहां खामियों पर पर्दा पड़ा हुआ था, एक झटके में सब सामने आ गया।

● **रजनीकांत पारे**

ताकतवर क्षत्रपों की वापसी

4 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय नेता ताकतवर होकर उभरे, जो केंद्र को हर मायने में चुनौती देने को तैयार हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो अभी से केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आग उगलने लगी हैं। वे विपक्ष का बड़ा चेहरा बनकर सामने आ रही हैं। इसी तरह अन्य क्षेत्रीय क्षत्रप भी भाजपा के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं।

हर चुनाव निराले नतीजे लेकर आता है और सियासत का रंग-ढंग बदल जाता है। 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी के विधानसभा चुनावों के 2 मई को आए नतीजों के पहले और बाद की घटनाओं पर जरा नजर डालिए तो उतने से ही साफ हो जाता है कि क्या कुछ बदला है और आगे क्या होने वाला है। असम में दो चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद कांग्रेस की अगुवाई वाले महाजोट ने अपने कुछ जीतने योग्य उम्मीदवारों को भाजपा की कथित खरीद-बिक्री से बचाने के लिए जयपुर में सुरक्षित भेज दिया था। पहली टोली के बाद दूसरी टोली भी आने वाली थी और गुवाहाटी में उन्हें इकट्ठा किया जा रहा था। लेकिन तभी कोरोना की दूसरी लहर का खतरनाक संक्रमण बेपनाह बढ़ने लगा और राहुल गांधी के कहने पर वह प्रक्रिया रोक दी गई। उधर, बंगाल में ममता बनर्जी हर सभा में कहती घूम रही थीं कि तृणमूल कांग्रेस को 200 से ज्यादा सीटों पर जिताइए, वरना गद्दारों की खरीद-बिक्री शुरू हो जाएगी। लेकिन 2 मई के नतीजों के बाद भाजपा बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का मुद्दा उठाने लगी और अपने सभी 77 विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा मुहैया करा दी। एक तो, ऐसी एकतरफा केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराने की नजीर नहीं है, उपद्रवग्रस्त इलाकों में भी ऐसा सभी निर्वाचितों के लिए कभी नहीं हुआ। दूसरा, अटकलें ये भी हैं कि कुछ नवनिर्वाचित भाजपा विधायक और तृणमूल के पुराने नेता घर वापसी की राह तलाश रहे हैं, उसे ही रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी बैठाई जा रही है।

बंगाल में ही नहीं, असम में भी खासकर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को हिमंता बिस्वा सरमा के आगे झुकना पड़ा, जो इन चुनावों में पार्टी की जीत का इकलौता राज्य है। वहां मुख्यमंत्री पद को लेकर चली रस्साकशी का अंदाजा इसी से लग सकता है कि नेता का नाम दिल्ली में तय होने में सात दिन लग गए, जबकि चुनाव वाले सभी राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली थी। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हिमंता बिस्वा सरमा दोनों पहुंचे। हिमंता बिस्वा सरमा से जब पूछा गया कि क्या फैसला हुआ तो बड़ी बेफिक्री से उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में पार्टी विधायक दल की बैठक में सब जाहिर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के तहत भाजपा का शायद ही कोई नेता इतनी बेफिक्री से अपना दावा पेश कर सकता है। यानी जहां भाजपा जीती भी, उसमें भी केंद्रीय नेतृत्व का एकछत्र दबदबा नहीं रहा, जिसकी कोशिश हर चुनाव में करने की कोशिश दिखती है। उस छोटे से पुदुचेरी में भी नहीं, जहां वह दिग्गज नेता तथा मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की पार्टी की छोटी सहयोगी है।

दरअसल इन चुनावों में भाजपा का निशाना देश में विपक्ष की बची रह गई (चुनावों के पहले तक) सबसे मजबूत आवाज ममता बनर्जी को औकात दिखाने की थी। उसे पिछले लोकसभा

विपक्ष को एकजुट करने का अभियान

पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद ममता की कोशिश रहेगी कि वह पूरे विपक्ष को एकजुट करें। असल में ममता ने चुनाव नतीजों के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिर शपथ लेने के बाद साफ संकेत दिया है कि वे विपक्ष को एकजुट करने के अभियान में जुटेंगी। हाल में उन्होंने कहा कि वे देश के 130 करोड़ लोगों को केंद्र की तरफ से मुफ्त कोविड टीकाकरण की मांग करती हैं और उसके लिए सत्याग्रह करेंगी। अगर वे ऐसा करती हैं तो विपक्ष उनके पीछे लामबंद हो सकता है, क्योंकि अभी कोई दूसरा नेता मोदी-शाह जोड़ी को चुनौती देता नहीं लगता और कोई देता भी है तो ताकत के अभाव में अप्रासंगिक हो उठता है। हाल में वैक्सीन का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा तो केंद्र का जवाब था कि अदालत को कार्यपालिका पर भरोसा करना चाहिए। इसी तरह कोरोना दौर में सेंट्रल विस्टा निर्माण पर उठे सवालों पर भी केंद्र ने दिल्ली हाइकोर्ट में अपने हलफनामे में कड़ा रुख अपनाया। दरअसल, केंद्र सरकार के खिलाफ हर स्तर पर आवाज उठने लगी है। ऐसे में विपक्ष भी इस तैयारी में है कि वह केंद्र की घेरेबंदी करे।

चुनावों में अचानक दो से 18 सीटें और 40 फीसदी वोट हासिल होने से यह हौसला मिल गया था कि ममता बनर्जी भी कमजोर कर दी गईं तो देश में कोई भी अगले लोकसभा चुनावों में केंद्र में चुनौती देने वाला नहीं बचेगा। इसी उम्मीद में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री समेत पार्टी के तमाम मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने जैसे डेरा ही डाल दिया था। ऐन चुनाव के पहले ममता की पार्टी से कई दलबदल कराए गए। दावा किया गया कि चुनाव खत्म होते-होते ममता अकेली बच जाएंगी। भाजपा प्रदेश की कुल 294 सीटों में से 200 जीतने का लक्ष्य घोषित कर चुकी थी। लेकिन हुआ उलटा। ममता की पार्टी 213 पर जा पहुंची और भाजपा 77 पर अटक गई।

हां, भाजपा के शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता को बहुत थोड़े अंतर से हराने में कामयाब रहे, मगर तृणमूल कांग्रेस की भारी जीत से उनकी हार भी भाजपा के किसी काम की नहीं है। वे उन तीन सीटों में से किसी से जीतकर आ सकती हैं, जहां उम्मीदवारों के कोविड से निधन के बाद चुनाव होने हैं। तो, सबक यह है कि जिस ममता को कमजोर करने की कोशिश भाजपा आला नेतृत्व कर रहा था, उसमें वह बुरी तरह नाकाम हुआ। शायद अपनी इसी नाकामी को छुपाने के लिए बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा को कुछ ज्यादा तूल दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर में लगभग गैर-हाजिर केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा नेता धरना देने कोलकाता पहुंच गए और हालात की समीक्षा के लिए केंद्र से टीम भेजी गई। भाजपा की रणनीति यह लगती है कि ममता को राज्य में उलझाए रखो, ताकि वे केंद्र की ओर ध्यान न दे सकें।

इसी तरह केरल में भी भाजपा को पिछले विधानसभा चुनावों में एक सीट मिल गई थी तो पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को वहां भी संभावना दिखी। सो, पार्टी ने मेट्रोमैन ई श्रीधरन जैसे सेलिब्रिटी चेहरे को उतारकर राज्य में अपना कुछ आधार बढ़ाना चाहा था। इसके पहले सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे से भी गरमी पैदा करने की कोशिश की गई थी। इन चुनावों में भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के मोटे तौर पर दो लक्ष्य स्पष्ट थे। एक, वाम मोर्चे की अगुवाई वाले एलडीएफ या कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ में से किसी को कमजोर किया जा सका तो केंद्रीय राजनीति में उसकी धमक कमजोर होगी। लेकिन हुआ उलटा। सही साबित हुई मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की वह बात कि '2016 में राज्य में भाजपा का एक सीट से खाता खुला था, हम इस बार वह भी बंद कर देंगे।' भाजपा को वहां एक भी सीट नहीं मिली, बल्कि उसका वोट प्रतिशत भी घट गया।

पिनराई विजयन निर्विवाद नेता बनकर उभरे। विजयन की अपनी पार्टी माकपा में भी अब उन्हें कोई चुनौती देने वाला नहीं है। बंगाल में पार्टी को इन चुनावों में शून्य मिला है। वहां वामपंथी दलों की यह हालत आजादी के बाद के इतिहास में पहली बार हुई है। इसलिए पार्टी में बंगाल के नेताओं का दबदबा घटने से केरल पार्टी इकाई ही मजबूत रह गई है और वहां अब सबसे अधिक जनाधार वाले नेता विजयन ही हैं। इससे विजयन का कद इतना बढ़ गया है कि वे विपक्ष की हर पहल में वजन रखेंगे।

फिर, तमिलनाडु में एमके स्टालिन आखिरकार अपने पिता दिवगंत करुणानिधि के साये से निकलकर राज्य में अपने दम पर चुनाव जिताऊ नेता बन गए हैं। स्टालिन ने यह करिश्मा 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद दूसरी बार विधानसभा चुनावों में भी कर दिखाया। अब इन चुनावों ने उन्हें द्रमुक के एकछत्र नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। भाजपा, या कहिए उसके केंद्रीय नेतृत्व की कोशिश यह लग रही थी कि अगर अन्नाद्रमुक की सरकार बरकरार रहती है तो उसका दबदबा बना रहेगा और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उसका असर देखने को मिले, लेकिन चुनावी नतीजों ने इसकी संभावना खारिज कर दी।

ममता बनर्जी से लेकर पिनराई विजयन और स्टालिन जैसे क्षत्रप इतने मजबूत और ताकत के साथ उभरकर आए हैं कि केंद्र के लिए उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे मुख्यमंत्रियों या फिर अन्य विपक्षी नेताओं की तरह झुकने पर मजबूर कर देना आसान नहीं होगा। एक वजह यह भी है कि उनकी प्रतिबद्धताएं ठोस हैं और लंबे समय से परखी हुई हैं। शायद उनके उभार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ताकत मिले, जो पिछले विधानसभा चुनावों के बाद कुछ शांत हैं और केंद्र उन पर लगातार दबाव बनाए हुए है। केंद्र ने कानून में संशोधन के जरिए दिल्ली सरकार के हाथ से सभी निर्णय-क्षमता वापस लेकर उपराज्यपाल को असली प्रशासक घोषित कर दिया है। इसके अलावा, लगातार केंद्र के वार से घिरे महाराष्ट्र की शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठजोड़ सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी मजबूती मिल सकती है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के तेवर भी कुछ साफ हो सकते हैं। यही नहीं, इससे तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को भी भाजपा के खिलाफ खुलकर खड़े होने की ताकत मिल सकती है। इससे बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद और उप्र में सपा के अखिलेश यादव को भी ताकत मिल सकती है। इन दोनों ने बंगाल चुनावों में ममता की मदद की थी। कांग्रेस हालांकि चुनावी नतीजों से उत्साहित नहीं हो सकती, लेकिन अगर विपक्ष की लामबंदी बड़ी होती है तो उसके लिए उसमें शामिल होना मजबूरी बन जाएगी।

● इन्द्र कुमार

भाजपा के लिए मुश्किल घड़ी

भाजपा के लिए स्थितियां मुश्किल भरी हो सकती हैं। उसको इस बात का अहसास हो सकता है कि इन चुनावों में हर जगह भाजपा के वोट प्रतिशत घट गए हैं। पश्चिम बंगाल में यह 40 से 37 प्रतिशत पर आ गया है तो केरल और तमिलनाडु में भी घट गया है। बंगाल के एक भाजपा नेता के मुताबिक, विधानसभा चुनावों के नतीजों को लोकसभा सीटों पर लगाएं तो भाजपा 9 यानी आधी सीटें हार सकती है। असम में जहां पार्टी जीती है, वहां भी यूपीए का वोट प्रतिशत भाजपा से ऊपर ही है। इसलिए विपक्ष शायद 2024 के आम चुनावों में वैसा ढीलापन न दिखाए, जैसा उसने 2019 के चुनावों में दिखाया था। इसलिए ये चुनावी नतीजे केंद्रीय सत्ता की कमजोरी और मजबूत विपक्षी क्षत्रपों के उभरने का ही संकेत हैं। यह अलग सवाल है कि अगले साल उप्र समेत कई अहम राज्यों के चुनाव हैं, जिनके नतीजे भी 2024 के चुनावों और केंद्रीय सत्ता के दबदबे पर असर डालेंगे।

कर्ज लेकर न्याय

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ के 22 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए की नकद सहायता जारी की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक समारोह में बटन दबाकर इस राशि का वितरण किया। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत 15 मार्च से 15 मई तक पशुपालकों से गोबर खरीदी की राशि 7 करोड़ 17 लाख रुपए और गौठान समितियों व महिला स्व-सहायता समूहों को 3 करोड़ 6 लाख रुपए भी ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। सरकार के इस कदम पर विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में कर्ज लेकर घी पीया जा रहा है। ऐसे समय में जब देश की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी की वजह से धड़ाम हुई पड़ी है, न्याय योजना केवल सरकार पर कर्ज ही बढ़ाएगी। वैसे, कर्ज लेकर घी पीने की बात केवल किताबों में ही अच्छी लगती है।

कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाया हुआ है। कुछ राज्यों में कड़े प्रतिबंधों के साथ आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। इसी के अनुपात में बेरोजगारी का भी आंकड़ा बढ़ गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच कांग्रेस लगातार मोदी सरकार से देश के गरीब लोगों को न्याय देने की मांग कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता कोरोना और लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों को 6000 रुपए प्रतिमाह की मदद के लिए मोदी सरकार से पत्र के जरिए या मौखिक रूप से न्याय योजना की मांग कर चुके हैं। इस स्थिति में सवाल उठना लाजिमी है कि लोगों को न्याय दिलाने की मांग कांग्रेस शासित राज्यों में लागू क्यों नहीं होती है?

बीते साल लगे लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार की 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि ये मदद लोन के जरिये नहीं, सीधे लोगों के खाते में पहुंचनी चाहिए। केरल में भी चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट न्याय योजना को लागू करने की बात की थी। लेकिन, केरल में कांग्रेस के चुनाव हारने से ये हो नहीं सका। वैसे, बीते साल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि यानी 21 मई 2020 को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूआत की थी। यानी सिर्फ किसानों तक सीमित। वैसे ही, जैसे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को छह-छह हजार रुपए दे रही है। यानी, यहां भी राहुल गांधी की मंशा के अनुसार न्याय गरीबों पर तक नहीं पहुंच रहा है, जिन पर कोरोना की दोहरी मार आन पड़ी है।

छत्तीसगढ़ में चल रही न्याय योजना पर जाने से पहले इसका अंकगणित समझ लेते हैं। इस योजना से छत्तीसगढ़ सरकार पर 5700 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त भार पड़ा है। किसानों की कर्जमाफी, समर्थन मूल्य समेत कई योजनाओं के सहारे छत्तीसगढ़ की सत्ता पाने वाली कांग्रेस कर्ज लेने के मामले में भी रिकॉर्ड बना चुकी है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बीते दो सालों में 25,277 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। भूपेश बघेल की सरकार पर 66,968 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। भूपेश बघेल सरकार को इस साल कर्ज के ब्याज का भुगतान करने के लिए 5330 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। जिसके लिए वह फिर से कर्ज ले सकती है। ऐसी योजनाओं से सीधे तौर पर राज्य सरकार पर कर्ज बढ़ता है और इसका असर राज्य की जनता पर नए-पुराने टैक्स के रूप में पड़ता है। कोरोनाकाल में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। तकरीबन हर राज्य कोरोना महामारी की वजह से भारी आर्थिक संकट से गुजरा है। बीते वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसडीपी के मामले में 3.62 लाख करोड़ के साथ छत्तीसगढ़ 19वें स्थान पर था। छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यह अभी तक उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सका है।

कांग्रेस शासित राज्यों में शामिल राजस्थान या पंजाब ने न्याय योजना को लागू करने की बात कभी नहीं की गई है। दरअसल, इन राज्यों का कर्ज पहले से ही लाखों करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इस स्थिति में ये राज्य न्याय योजना के लोक लुभावन वादे से दूरी बनाए हुए हैं। अगर ये योजना इतनी ही कारगर और अच्छी है, तो राजस्थान और पंजाब ने इसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया है। वैसे, अगर छत्तीसगढ़ में शुरू हुई न्याय योजना के सहारे लोगों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव आया होता, तो केंद्र की मोदी सरकार पर यह दबाव बन सकता था कि वह इस योजना को लागू करे। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए जारी की गई न्याय योजना भूपेश बघेल सरकार पर केवल कर्ज बढ़ा रही है। ये योजना सुनने में जरूर अच्छी लग सकती है, लेकिन इसे लागू करने के लिए सरकार के पास फंड भी होना जरूरी है। यहां एक बात और है कि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, तो वहां न्याय योजना चलाई जा सकती है। लेकिन, बड़े राज्यों में ये सरकारों के लिए सिरदर्द बन सकती है। इससे इतर मोदी सरकार की ओर से गरीबों के लिए मुफ्त राशन, गैस जैसे कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान निधि योजना के तहत भी मोदी सरकार किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश करती है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

कांग्रेस की जरूरत है न्याय योजना

2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जिस तुरुप के इक्के के साथ सत्ता में वापसी की उम्मीदें लगाए बैठी थी, उस न्याय योजना पर लोगों का भरोसा कायम नहीं पाया था। दरअसल, कांग्रेस की ओर से लगातार न्याय योजना की मांग करने की वजह ये है कि इस योजना के सहारे कांग्रेस की राजनीति सधती हुई दिखती है। अगर मोदी सरकार न्याय योजना लागू करती है, तो कांग्रेस इसे अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर पेश करने से नहीं चूकेगी। दूसरी ओर उसके लिए यह मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का राजनीतिक हथियार भी है। कांग्रेस की ओर से इस बात को प्रचारित करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी कि मोदी सरकार ने गरीबों से मुंह मोड़ लिया है। इस योजना को लागू करने की मांग कर रही कांग्रेस के दोनों हाथों में लड्डू हैं। 2024 में विपक्ष का नेता बनने से पहले राहुल गांधी को एक ऐसी योजना की अदद जरूरत है, जिससे उन्हें स्थापित नेता के तौर पर पेश किया जा सके।

फिर चढ़ा सियासी पारा

राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद प्रदेश में फिर से सियासी पारा चढ़ने लगा है। सचिन पायलट खेमे के कई विधायक अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ फिर से आवाज बुलंद कर रहे हैं। राजस्थान में एक बार फिर से सिर फुटव्वल की स्थिति बनती नजर आ रही है। बीते साल सचिन पायलट के खेमे वाले विधायकों के बागी हो जाने की वजह से गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल ने उस बगावत को जैसे-तैसे शांत कर दिया था। लेकिन, हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद राजस्थान में माहौल बिगड़ने के संकेत मिलने लगे हैं। शीर्ष नेतृत्व पहले से ही जी-23 नेताओं और पंजाब में चल रही खींचतान में फंसा हुआ है। इस स्थिति में सवाल उठना लाजिमी है कि नए सिरे से बगावत का इशारा सचिन पायलट को भाजपा का संकेत तो नहीं है?

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते साल जिस तरह से कांग्रेस सरकार बचाई थी, कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें तब से ही तवज्जो देना शुरू कर दिया था। विधानसभा में बहुमत साबित करने के दौरान सचिन पायलट को आखिरी लाइन में बैठाना हो या शब्दबाणों से लगातार पायलट खेमे के विधायकों को चुनौती हो, अशोक गहलोत के हर वार पर कांग्रेस आलाकमान ने मौन सहमति दी हुई है। यही वजह है कि एक इंटरव्यू में राजस्थान के प्रभारी और दिग्गज कांग्रेस नेता अजय माकन ने साफ लहजे में कह दिया कि सचिन पायलट पार्टी के लिए एसेट हैं, लेकिन पार्टी किसी की उम्मीद के हिसाब से फैसला नहीं करती है। कांग्रेस आलाकमान का सचिन पायलट को बहुत स्पष्ट संदेश है कि राजस्थान में अशोक गहलोत का कद काफी ऊंचा है।

ये ठीक वैसे ही है जैसा आजकल पंजाब में चल रहा है। कांग्रेस के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने उपमुख्यमंत्री पद पाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सिद्धू को समझाने की नाकाम कोशिश के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को कहना पड़ा कि पंजाब में अमरिंदर सिंह के हिसाब से ही चलना होगा। पंजाब में अमरिंदर सिंह और राजस्थान में अशोक गहलोत काफी दबदबे वाले नेता माने जाते हैं। इन दोनों के बारे में ही कहा जाता है कि पसंद न आने पर ये पार्टी आलाकमान का फैसला भी बदलने की ताकत रखते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से अमरिंदर सिंह पर अकाली दल से सांठगांठ के आरोप लगाते हैं। वैसे ही आरोप अशोक गहलोत पर वसुंधरा राजे को लेकर भी लगाए जाते हैं।

भाजपा की डगर पायलट के लिए कठिन

असम में हिमंता बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष में महत्वाकांक्षाएं रखने वालों को अप्रत्यक्ष रूप से निमंत्रण दे दिया हो। लेकिन, राजस्थान में भाजपा की ये मंशा आसानी से पूरी नहीं होगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने लिए अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स की जौर-आजमाइश में लगी हैं। राज्य के भाजपा नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस बाबत मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन वसुंधरा राजे पर कोई दबाव बनता दिख नहीं रहा है। अमित शाह से उनकी अदावत जगजाहिर है। वैसे, हो सकता है कि कांग्रेस से भाजपा में आए उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझाइश के लिए आगे किया जाए, लेकिन वसुंधरा राजे हैं तो उनकी बुआ ही। 2023 में भाजपा उनके बिना राज्य के विधानसभा चुनाव में जाती है, तो एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का खतरा है। ज्योतिरादित्य राजे के साथ सचिन पायलट की नजदीकियों से भाजपा में जगह बन सकती है, लेकिन यहां भी उन्हें उपमुख्यमंत्री का पद ही मिलेगा।

हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को राजस्थान में सियासी संकट की ठंडी पड़ चुकी राख से निकली चिंगारी कहा जा सकता है। सचिन पायलट के खेमे के तमाम विधायक एक बार फिर से गहलोत सरकार की कार्यप्रणाली पर मुखर हो गए हैं। इन विधायकों का आवाज उठाना समझ में आता है, लेकिन गहलोत खेमे के भी विधायक पार्टी और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पचपदरा विधायक मदन प्रजापति ने हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बहाने बिना नाम लिए गहलोत सरकार के मंत्री हरीश चौधरी पर निशाना साध दिया। मदन प्रजापति कहते नजर आए कि हेमाराम चौधरी एक भावुक और सीनियर नेता हैं। उनके इस्तीफे पर हाईकमान को सोचना होगा। कई विधायक दबी जुबान में पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि गहलोत सरकार के मंत्री विपक्ष के नेताओं के कामों पर अपने विधायकों से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पिछले विधानसभा सत्र में गहलोत और पायलट खेमों के कई विधायक अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते नजर आए थे। हेमाराम चौधरी ने तो सड़क निर्माण के कार्य में घोटाले की बात तक कह दी थी। पचपदरा विधायक मदन प्रजापति ने हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बहाने बिना नाम लिए गहलोत सरकार के मंत्री हरीश चौधरी पर निशाना साध दिया। पचपदरा विधायक मदन प्रजापति ने हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बहाने बिना नाम लिए गहलोत सरकार के मंत्री हरीश चौधरी पर निशाना साध दिया।

राजस्थान में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है और फिलहाल अभी यह होता भी नहीं दिख रहा है। पायलट खेमे के विधायक ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे ने इन विधायकों को अपनी पीड़ा कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचाने का मौका दे दिया है। वैसे, अजय माकन ने कह दिया है कि कांग्रेस सरकार को बनाने में सचिन पायलट का योगदान रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में उन्हें भूमिका सौंपी जाएगी। लेकिन, ऐसा लग रहा है कि यह भूमिका अशोक गहलोत को पसंद नहीं आ रही है। पिछले साल हुई बगावत के बाद से ही अशोक गहलोत ने पायलट खेमे को हाशिए पर रखा हुआ है। प्रदेश संगठन पर भी गोविंद सिंह डोटसारा के रूप में अशोक गहलोत का ही कब्जा है। गहलोत किसी भी हाल में सचिन को दोबारा उपमुख्यमंत्री पद देने के हक में नही हैं।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

कोरोना संक्रमणकाल में देश में लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, वहीं हजारों लोगों का कारोबार बंद हो गया है। लेकिन यह संक्रमणकाल देश के 2 बड़े उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के लिए लाभकारी साबित हुआ। इन दोनों में से भी अडानी को सबसे अधिक फायदा हुआ है। अडानी की संपत्ति और आय इस तेजी से बढ़ी है कि वे एशिया के दूसरे नंबर के रईस बन गए हैं।

रईसी की रेस

एक जमाना था जब हिंदुस्तान में रईसों की चर्चा होती तो टाटा-बिड़ला का नाम लिया जाता था, वक्त बदला तो रईसों के नाम बदल गए। एक समय ऐसा भी आया, जब रईसों की लिस्ट में अंबानी का नाम ध्रुवतारे की तरह अलग से चमकने लगा। लेकिन साल 2014 में केंद्र की सरकार बदलने के कुछ दिन बाद गुजरात के एक बिजनेसमैन का नाम तेजी से सबके सामने आया। इस बिजनेसमैन ने कम समय में जिस गति से अपनी संपत्ति बढ़ाई, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जी हां, हम अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी की बात कर रहे हैं, जो कुल 4.98 लाख करोड़ रुपए संपत्ति के साथ एशिया के दूसरे अमीर बन चुके हैं।

इस वक्त एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी को संपत्ति के मामले में गौतम अडानी पीछे छोड़ने के करीब पहुंच चुके हैं। इस साल गौतम अडानी की संपत्ति में 2.47 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 5.73 लाख करोड़ रुपए है। सुपर स्पीड से बढ़ती गौतम अडानी की संपत्ति रईसी की रेस में मुकेश अंबानी के लिए खतरे का संकेत है। पिछले कई वर्षों से अंबानी का नाम हिंदुस्तान के रईसों में नंबर 1 पर बना हुआ है। लेकिन जिस गति के साथ अडानी की संपत्ति बढ़ रही है, वो बहुत जल्द अंबानी को पछाड़कर नंबर वन की कुर्सी पर विराजमान हो सकते हैं।

कोरोना महामारी में जिस वक्त पूरी दुनिया की कई अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं, कई कारोबारी कंगाल हो चुके हैं। ऐसे वक्त में भारत के कारोबारियों की संपत्ति में इस कदर इजाफा हर किसी के लिए चौंकाने वाला है। कोरोनाकाल में ही करीब 40 बिजनेसमैन अरबपतियों की सूची में शामिल हुए हैं। इन्हें मिलाकर भारत के कुल 177 कारोबारी अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं कई बिजनेसमैन के संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ है। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट की मानें को साल 2014 से अब तक अडानी की संपत्ति करीब 432 फीसदी की दर से बढ़ी है, वहीं अंबानी की 276 फीसदी की दर से बढ़ी है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक दिन में ही मुकेश अंबानी की संपत्ति में 22 करोड़ डॉलर की कमी आई है, जबकि अडानी की संपत्ति में 1.11 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इस तरह दोनों की संपत्ति में अब करीब 8.7 अरब डॉलर का फासला रह गया है। यानि करीब 63,530 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करते ही अडानी भारत ही नहीं एशिया के नंबर वन रईस बन जाएंगे। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर हैं। वहीं, गौतम अडानी 13वें नंबर पर हैं। पिछले कुछ समय से अडानी ग्रुप के शेयर की कीमतों में भी लगातार तेजी देखी जा रही है। इसका फायदा गौतम अडानी को मिल रहा है।

फोर्ब्स के मुताबिक, दुनिया के अमीरों की लिस्ट में ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के ओनर जेफ बेजोस सबसे ऊपर हैं, जिनकी नेटवर्थ 191.5 अरब डॉलर यानी 14 लाख 2 हजार करोड़ रुपए है। फोर्ब्स के रीयल टाइम डेटा के मुताबिक, गौतम अडानी की कुल संपत्ति 61.1 अरब डॉलर यानी 4 लाख 98 हजार करोड़ रुपए है। इस साल अडानी की संपत्ति दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस और एलन मस्क से भी तेज बढ़ी है। पिछले साल उनका नेटवर्थ 432 फीसदी की दर से बढ़ा, नतीजा यह रहा कि उनकी संपत्ति 60 अरब डॉलर के पार पहुंच गई। इस तरह गौतम अडानी रईसी के मामले में अंबानी के साथ ही बेजोस और मस्क को चुनौती देते नजर आ रहे हैं।

● **बिन्दु माथुर**

अडानी के मार्केट कैप में 6 गुना इजाफा

गौतम अडानी की शेयर बाजार में लिस्टेड 6 कंपनियों का मार्केट कैप एक साल में 41.2 गुना बढ़ा है। इसी समय में अंबानी की रिलायंस की कंपनियों का मार्केट कैप 55 फीसदी बढ़ा है। पिछले साल अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़कर अब 8.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस तरह इसमें 6 गुना इजाफा हुआ है। इसी समयावधि में रिलायंस का मार्केट कैप 9.37 से बढ़कर 13.35 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस तरह अंबानी को महज 4 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ, जबकि अडानी को 7 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। इस साल की बात करें तो अंबानी की संपत्ति में 1,312 करोड़ रुपए की कमी भी आई है।

साख का सवाल

उप्र में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संघ फिक्रमंद है। इसी को लेकर संघ ने गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। बैठक में उप्र में कोरोना के प्रभाव और इसके चुनावों पर होने वाले असर को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में हुई इस बैठक के बाद पार्टी और संगठन स्तर पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ताकि, उप्र में होने वाले चुनावों से पहले पार्टी की छवि को पहुंचे नुकसान की भरपाई की जा सके। इस बैठक में संघ के दत्तात्रेय होसबोले, उप्र में संगठन के प्रमुख सुनील बंसल भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक कोरोना के चलते भाजपा की जो छवि लोगों में बनी है, उस पर गंभीर चिंता इस बैठक में जाहिर की गई।

दरअसल, उप्र सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के साथ ही कर्मचारी संगठनों के निशाने पर हैं। उप्र यूं तो वैसे ही अपनी ओछी और जाति-पाति वाली राजनीति की वजह से जाना पहचाना जाता है लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। इस बार की राजनीति में दो सियासी दल आमने-सामने नहीं हैं बल्कि एक तरफ शिक्षक संघ है तो दूसरी तरफ वही सरकार है जिसके हाथों में सिस्टम की बागडोर है। वही सिस्टम जिसको हम सब दिन-रात विकलांग कहते हैं, लूला-लंगड़ा कहते हैं। उप्र के शिक्षक संघ का आरोप है कि उप्र में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने के दौरान उसके करीब 2000 शिक्षक कोरोना की चपेट में आए हैं जिसमें 1600 से भी ज्यादा शिक्षकों की जान चली गई है। इन मौतों का जिम्मेदार राज्य सरकार और चुनाव आयोग है, जान गंवाने वाले शिक्षकों के परिवार को आर्थिक सहायता या फिर मुआवजा दिया जाए ताकि परिवार का बोझ कुछ हल्का हो सके। कोर्ट ने भी सरकार को ये निर्देश दिए थे। अब आगे का फैसला करना राज्य सरकार के पाले में था, राज्य सरकार जो आंकड़ों की बाजीगरी में माहिर हुआ करती है उसने अपने अलग ही तर्क दे डाले।

सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि नियमों के मुताबिक चुनाव में ड्यूटी कर रहे लोगों की मौत पर तब ही मुआवजे का प्रावधान है जब चुनाव ड्यूटी के खत्म होने से पहले ही मृत्यु हो जाए। यानी की चुनाव की ड्यूटी के वक्त ही किसी की मृत्यु होती है तो ही मुआवजा दिया जाएगा। ये सच है कि चुनाव आयोग द्वारा यही नियम बनाए गए हैं लेकिन राज्य सरकार बेचारी इतनी सीधी और भोली बनकर जवाब दे जाएगी इसकी उम्मीद तो कतई नहीं की जा सकती थी।

शिक्षक संघ ने जहां 1600 से अधिक मौतों का दावा किया तो वहीं राज्य सरकार ने अपने आंकड़े देते हुए कहा कि मात्र 3 लोगों की ही जान चुनाव कराते हुए गई है। चुनाव के खत्म हो जाने के बाद के ऐसे कोई आंकड़े उनके पास मौजूद नहीं है। इन आंकड़ों के हेरफेर में पड़ने से पहले आप अपना स्टैंड क्लीयर कर लीजिए। शिक्षक संघ के अनुसार 1621 मौत और राज्य सरकार के अनुसार केवल 3 मौत ये आंकड़ों का खेल है। इस पर राजनीति हो रही है और जमकर हो रही है। मगर अब तक दोनों ही ओर से इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच कराए जाने की बात सामने नहीं आई है जो कि बेहद जरूरी है। पंचायत चुनावों के दौरान जिन लोगों ने भी ड्यूटी की है सभी के रिकार्ड मौजूद हैं। रिकार्ड को खंगाल आसानी से इस बात को जांचा-परखा जा सकता है कि कितने लोग ड्यूटी पर मौजूद थे और किसकी मौत कब हुई है, कितनों की मौत हुई है और किस तरह की मौत हुई है।

जाहिर है 1621 मौतों का अगर दावा किया जा रहा है तो उनमें से सबकी मौत स्वाभाविक मौत नहीं हो सकती है। ये भी सच है कि सबकी मौत कोरोना से ही नहीं हुई होगी। यह सबकुछ जांच से साबित हो जाएगा, फिलहाल इन मौतों के आंकड़ों पर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है वो शर्मसार कर देने वाली हरकत है। जिन परिवार ने अपना मुखिया खो दिया है या फिर जिन परिवारों ने अपने बच्चों को चुनाव ड्यूटी के बाद खो दिया है उनको संवेदनाओं की जरूरत है। उनको सहारे की जरूरत है, उनको जरूरत है बोझ को कुछ हद तक बांटने की। परिवार से जब कोई कमाने वाला ही इंसान दुनिया छोड़ जाता है तो उस परिवार की क्या कंडीशन होती है इसको बताना उचित नहीं समझता इसको आप बेहतर समझ सकते हैं। मगर सवाल यह है कि आखिर इन परिवारजनों के छलनी हुए कलेजे पर मरहम रखेगा कौन, इनको सहारा कौन देगा? तो नजर सिर्फ दो ओर ही जा पड़ती है। पहला तो विभाग की ओर यानी शिक्षक संघ की ओर और दूसरा राज्य सरकार की ओर। मगर अफसोस की अभी तक कोई भी बेहतर तरीके से उन बेबस परिवारों की आवाज नहीं बन पाया है। उप्र सरकार को इस पूरे प्रकरण की सही और सटीक जांच करानी चाहिए और सभी जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

भाजपा की फिक्र- मोदी पर सीधे हमले

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मोदी पर हो रहे सीधे हमलों से भाजपा परेशान है। दूसरी लहर ने देश को झकझोर दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की तैयारियां सबके सामने उजागर हो गई हैं। इसके अलावा वैक्सीन, ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की कमी ने तैयारियों की खामी को उजागर किया है। उप्र कोरोना से बुरी तरह प्रभावित होने वाले राज्यों में शामिल है। गंगा में बहती लाशों ने तो प्रदेश में होने वाली मौतों की सच्चाई को सबके सामने रख दिया। कोरोना की स्थित को संभालने को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर भी प्रश्नचिन्ह है कि क्या उप्र में टेस्ट और केस के आंकड़े वाकई सच्चे हैं?

We Deal in Pathology & Medical Equipment

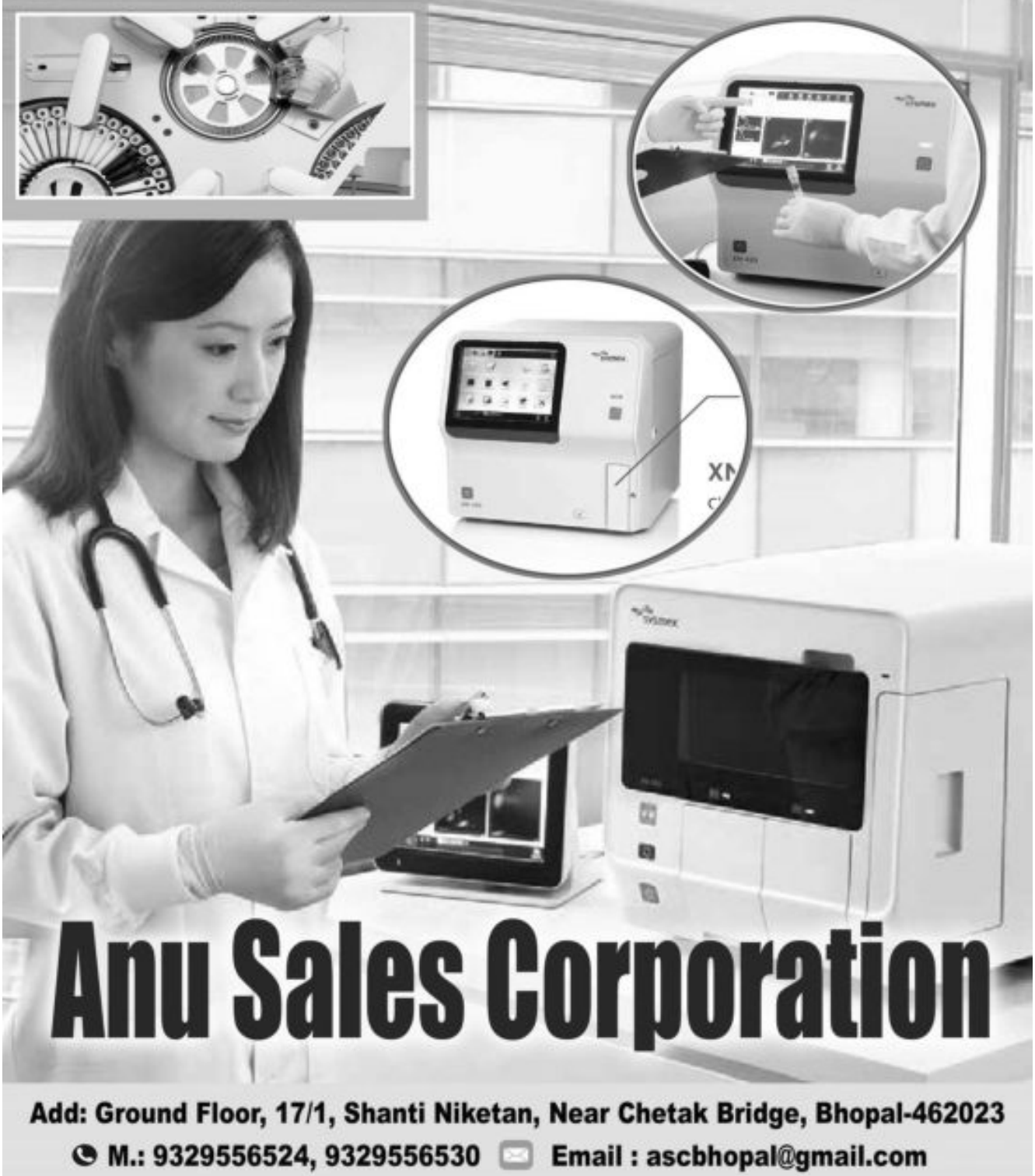

Anu Sales Corporation

Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

M.: 9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

चीन का सबक जरूरी

अमेरिका ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर दी जा रही प्रयोगशाला (लैब) से लीक होने की थ्योरी की जांच नए सिरे से शुरू कर दी है। वह यह आंकने का प्रयास कर रहा है कि क्या कोरोना वायरस चीन की वुहान वायरस लैब से निकला है? कोरोना वायरस कहां से निकला, इस पर बहस जनवरी 2020 में ही छिड़ गई थी, जब चीन ने पहले इनकार किया और फिर कुबूल किया कि यह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। हालांकि चीन सरकार इस पर अड़ी है कि कोरोना वायरस जंगल से निकला है, लेकिन कई जानवरों पर संदेह जताने के बाद भी न तो चीन और न ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) यह बता सका है कि यह वायरस आखिर किस प्रजाति से होता हुआ इंसानों तक पहुंचा? पहले कहा गया कि यह पैंगोलिन से निकला, फिर चमगादड़ और कई दूसरे जानवरों के नाम लिए गए। सच तो यह है कि महामारी के 16-17 महीने बाद भी हम दावे से नहीं कह सकते कि किन प्रजातियों के माध्यम से यह वायरस इंसानों तक फैला? इससे पहले हमने इंसानों को बीमार करने वाले दो अन्य कोरोना वायरस देखे। सार्स-1 (2002) और मर्स (2012), जिनकी प्रजातियों का पता वैज्ञानिकों ने चार और नौ महीने में लगा लिया था।

मौजूदा कोरोना वायरस को लेकर सबसे पहले संदेह गया चीन के वुहान शहर की लैब- इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलाजी पर। वुहान शहर से ही इस वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में हुई। यह लैब कोई आम संस्थान नहीं है। यहां वायरस पर सबसे खतरनाक और जटिल प्रयोग होते हैं। खासतौर पर ऐसे वायरस पर, जो चमगादड़ों में पैदा होते हैं। इस प्रयोगशाला की कमान बैट वायरसों पर विशेषज्ञता रखने वाली शी झेंग-ली संभाल रही हैं, जिन्हें चीन में बैट लेडी भी कहा जाता है। अब तक इस लैब ने दक्षिण चीन की गुफाओं से चमगादड़ों से लगभग सौ किस्म के वायरस इकट्ठा किए हैं, जिनमें आरएटीजी-13 भी शामिल है, जिसे 2013 में चमगादड़ों से आइसोलेट किया गया था। यह वायरस कोरोना वायरस से 96.2 प्रतिशत तक हूबहू मिलता है। वायरस पर अध्ययन के लिए चमगादड़ दो कारणों से काफी महत्वपूर्ण स्तनपायी हैं। पहला, वे उड़ सकते हैं और कम समय में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। दूसरा, स्तनधारियों में उनकी संख्या सबसे अधिक है। धरती पर समस्त स्तनधारियों में एक चौथाई संख्या चमगादड़ों की है। और यहीं से अमेरिका स्थित संस्थानों की भूमिका शुरू हो जाती है।

2015 में वुहान लैब ने अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी कर यह पता लगाने का प्रयास किया कि कैसे जो वायरस चमगादड़ों में पाए जाते हैं, वे इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। इसी साझेदारी में वुहान लैब ने चमगादड़ों में मिले वायरस में बदलाव कर चूहों को संक्रमित करने के विषय में जाना। इसके अतिरिक्त यह भी पता किया कि कैसे उस वायरस में चूहों की सांस की नली में मौजूद एस-2 प्रोटीन पर हमला करने की क्षमता पैदा की जाए। चिंता की बात यह है कि एस-2 प्रोटीन इंसानों में भी पाया जाता है। कोरोना वायरस इंसानों की कोशिकाओं में खुद को इसी एस-2 प्रोटीन के साथ जोड़कर हमारे श्वसन मार्ग में प्रवेश कर जाता है।

अब बात इस विषय पर आती है कि इसमें अमेरिकी सरकार की भूमिका क्या थी, जिसकी जांच अब अमेरिकी सीनेट कर रही है। वुहान लैब को अमेरिका के संक्रामक रोगों के राष्ट्रीय संस्थान से धन मुहैया कराया जा रहा था। इस सरकारी संगठन ने न्यूयॉर्क के एक एनजीओ को पैसे दिए, जिसने वुहान लैब को आगे का काम सौंपा। 2018 और 2019 में इसका अध्ययन करना था कि चमगादड़ों से विभिन्न प्रकार के वायरस दूसरी प्रजातियों में कैसे फैल सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वुहान शहर में पैदा हुआ 2019 का कोरोना वायरस इसी प्रयोग का नतीजा था? चीन इससे इनकार करता है, लेकिन कोई सुबूत नहीं देता। इस जांच की आखिरी महत्वपूर्ण कड़ी एक खास प्रयोग है, जिसे गेन ऑफ फंक्शन कहा जाता है। इस बेहद खतरनाक प्रयोग में वैज्ञानिक एक ऐसे चमगादड़ (या दूसरे जानवर) से वायरस को लेते हैं, जो इंसानों को प्रभावित नहीं करता। फिर वे उसे एक लैब में तेजी से तब तक रूपांतरित (म्यूटेंट) करते हैं जब तक कि वह इंसानों की कोशिकाओं को प्रभावित करना सीख नहीं लेता। यह अध्ययन किसी हानिरहित वायरस के भविष्य को जानने और अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि आगे चलकर कहीं यह इंसानों में बीमारी तो पैदा नहीं करेगा। निश्चित रूप से हम इस गेन ऑफ फंक्शन प्रयोग के खतरों को समझ सकते हैं। अगर इस प्रक्रिया में लैब में सुपर वायरस बन जाए और वह सुपर वायरस लीक हो जाए तो क्या होगा? वुहान लैब चमगादड़ के वायरस पर ऐसे प्रयोग के लिए ही जानी जाती है।

● **राजेश बोरकर**

दुनिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चीन ने साधी चुप्पी

आज जब दुनिया कोरोना संक्रमण की उत्पत्ति को लेकर प्रश्न कर रही है तो चीन की सरकार ने चुप्पी साध ली है। इन मामलों में चीन का अपना पुराना रिकॉर्ड भी दागदार है। 2015 का एक दस्तावेज हाल में सामने आया है, जिसके अनुसार तब चीन के शीर्ष वैज्ञानिक चर्चा कर रहे थे कि वायरस के प्रयोग से कम कीमत पर हथियार कैसे बनाए जा सकते हैं? चीन अपनी लैब में सुरक्षा के खराब मानकों के लिए भी बदनाम है। पहले भी कई बार चीन में वायरस लीक हुए हैं, जिनमें 2004 का सार्स वायरस भी शामिल है। जाहिर है इस बारे में दुनिया की सारी शंकाओं को दूर कर लेना बहुत आवश्यक है कि जिस कोरोना वायरस ने अब तक 35 लाख इंसानों को मार डाला, आखिर उसकी शुरुआत कहां से हुई? यह सवाल जरूरी है, न केवल अतीत के नजरिए से, बल्कि भविष्य के लिहाज से भी, ताकि फिर कभी ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। यदि इस वायरस की उत्पत्ति का पता चल जाए तो हम जल्द और बेहतर इलाज पाने के साथ ही भविष्य के म्यूटेशन का अनुमान भी लगा सकते हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि गलती से या फिर जानबूझकर कोई भी ऐसे वायरस को मानवता के विरूद्ध हथियार न बना सके।

जंग टली है थमी नहीं

इजराइल और फिलिस्तीनी गुट हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई है जिसका आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। इन दोनों के बीच 11 दिनों के भीषण संघर्ष ने कई चीजों को आईने की तरह साफ करके रख दिया है और आगे क्या होगा इसकी भी हल्की सी झलक जरूर दिखला दी है। इस पूरे प्रकरण ने कई देशों के चेहरों पर से नकाब भी उतार दिया है और कुछ देशों की झूठी ताकत और उनकी बहादुरी की पोल पट्टी भी खोलकर रख दी है। इस लंबे संघर्ष से कुछ बातें तो साफ हो गई हैं।

सबसे पहले बात इजराइल की इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा देश है जो बहुत ही छोटा सा है लेकिन बड़े-बड़े ताकतवर देश भी उसका नाम लेने में खौफ खाते हैं। आसपास दुश्मनों से ही घिरे रहने के बावजूद यह देश-दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। साथ ही इजराइल की अर्थव्यवस्था भी इतनी मजबूत है कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां इजराइल में निवेश को लगातार बढ़ावा देती जा रही हैं। मौजूदा संघर्ष में इजराइल की ताकत ने ही उसको सबसे बड़ी मजबूती प्रदान की है, तमाम मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ सख्त तेवर जरूर अपनाए हुए थे लेकिन इजराइल की ताकत और उसकी दिन-बदिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हावी होने के चलते सभी देश धाराशाई हो गए। इजराइल की रणनीति के चलते ही कोई भी देश सामने आकर हमास की ओर से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाया है। इस संघर्ष से एक बात जो इजराइल के लिए साफ हुई है वह यह है कि अब इजराइल के साथ एक बड़ा तबका खड़ा हुआ है, 25 देशों ने उसे खुला समर्थन दिया है वह भी तब जब वह गाजा पट्टी में खुला हवाई हमला कर रहा था। यह समर्थन इजराइल को सुकून देने के लिए काफी है। फिलिस्तीन एक ऐसा देश जिसका हाल अंग्रेजों ने उसी तरह किया जैसा हाल अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान का किया है। एक ऐसा बंटवारा जो हमेशा के लिए नासूर बना हुआ है। फिलिस्तीन जिसे 48 फीसदी जमीन पर शासन करने की अनुमति दी गई थी और 44 फीसदी पर इजराइल देश की बुनियाद रखी गई थी। यह बंटवारा होने के बाद से ही फिलिस्तीन अपना पूरा कब्जा वापिस पाने की चाह में लगा हुआ था तो दूसरी ओर इजराइल भी अपने अस्तित्व की जंग लड़ने को तैयार था। जंग हुई और हर बार फिलिस्तीन को अपनी जमीन खोनी पड़ी। आज फिलिस्तीन 12 प्रतिशत जमीन पर ही शासन कर रहा है।

एक ओर इजराइल दिन दूनी-रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो फिलिस्तीन अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था और ताकत बढ़ाने के बजाय अपना कब्जा वापिस पाने की होड़ में ही लगा हुआ है जो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। ताजा संघर्ष में फिलिस्तीन वजह तो जरूर था लेकिन फिलिस्तीन का इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि फिलिस्तीन का पूरा शासन वेस्ट बैंक तक ही सीमित है जबकि गाजा पट्टी पर कब्जा हमास का है जो कि इस संघर्ष का अहम पहलू था। फिलिस्तीन जब तक अपनी ताकत बढ़ाने पर काम नहीं करेगा तब तक उसे ऐसे ही अपनी जमीन और अपने लोगों का नुकसान उठाना ही पड़ेगा। एक ऐसा गुट जो किसी के लिए सुपरहीरो की जगह रखता है तो किसी के लिए आतंक का गिरोह। फिलिस्तीन की लड़ाई को हमास ने अपने कांधे पर उठाने का कार्य बखूबी कर लिया है। फिलिस्तीन की सरकार और हमास के बीच मनभेद लगातार सामने आते रहते हैं। दोनों की लड़ाई और दुश्मन तो एक ही हैं लेकिन लड़ाई लड़ने का तरीका अलग-अलग है। हमास लगातार अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर देता रहता है वह ताकत हथियारों का जखीरा जमा करने के रूप में हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में। हमास ने ताजा संघर्ष के दौरान जिस तरह से रॉकेट इजराइल पर बरसाए हैं वह हमास को एक नई पहचान देने के लिए काफी है।

खाड़ी और मुस्लिम देशों का रहनुमा सऊदी अरब जो कि आर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोआपरेशन की नुमाइंदगी भी करता है। इस पूरे संघर्ष के दौरान हर किसी की नजर सऊदी अरब पर टिकी हुई थी। सऊदी अरब से लोगों को काफी उम्मीद थी खासतौर पर उन्हें जो फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में थे लेकिन सऊदी अरब ने अपनी आदत के अनुसार इस मुद्दे पर भी महज रस्मअदायगी ही करना बेहतर समझा। ये बात बिल्कुल साफ है कि इजराइल से सऊदी अरब के रिश्ते हमेशा से अंदरूनी तौर पर ही रहे हैं, सऊदी अरब कभी भी खुलकर इजराइल के साथ नहीं होता है लेकिन दोनों के बीच अच्छे संबंध बने रहते हैं। अभी हाल ही में इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सऊदी अरब का गुप्त दौरा किया था जिसे छिपाकर भी रखा गया है लेकिन कुछ अंदरूनी रिपोर्टों ने इस दौरे को सार्वजनिक भी किया है।

● **विनोद बक्सरी**

तुर्की और पाकिस्तान का मौन

तुर्की और पाकिस्तान दोनों देशों का हाल लगभग एक सा है। दोनों ही देशों की दिली तमन्ना है कि वह मुस्लिम देशों की रहनुमाई करें, पाकिस्तान जो कि खुद सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों का कर्जदार है तो वह कभी भी यह गुस्ताखी नहीं करेगा कि वह अमेरिका या सऊदी अरब के खिलाफ खड़ा होगा। हां पाकिस्तान के फिलिस्तीन के पक्ष में बयानबाजी करने से न तो अमेरिका का कोई नुकसान है और न ही सऊदी अरब की मुस्लिम देशों की नुमाइंदगी पर कोई खास फर्क पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान का बोलना या न बोलना यहां पर बराबर था। बात तुर्की की करें तो उसका कोई खास प्रभाव जरूर पड़ सकता था। तुर्की के राष्ट्रपति ने पूरे गुस्से के साथ बयान दिया जो कि महज दिखावा था। तुर्की और इजराइल का संबंध बरसों पुराना है। इजराइल के साथ तुर्की का व्यापारिक रिश्ता है इसलिए तुर्की को इस पूरे मसले पर सिर्फ बयानबाजी कर खानापूर्ति करना था जो कि उसने बेहतरीन ढ़ंग से किया है। तुर्की अगर वाकई फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ा होता तो सीधे तौर पर वह फिलिस्तीन की सीमा को छूने वाले मिस्र, जार्डन, लेबनान जैसे देशों को भरोसे में लेकर सैन्य ताकत पहुंचाता या फिर अमेरिका की तरह खुलकर मैदान में आने का ऐलान कर देता। लेकिन तुर्की ने भी फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का बस ढ़ोंग ही रचा था।

छिपकर अपनों से मिलने की मजबूरी

आज भी कई घरों में लड़कियां अपने फैसले खुद नहीं लेतीं। शादी के बाद भी उनके ससुराल वाले ही उनके बारे में सबकुछ तय करते हैं। कौन से कपड़े पहनने हैं, किससे दोस्ती करनी है, यहां तक की मायके कब जाना है। शादी में कन्यादान करने का मतलब यह नहीं होता कि घरवालों ने अपनी बेटी को पराया कर दिया या दान ही कर दिया। बेटियां भले ससुराल चली जाएं लेकिन उनका एक हिस्सा हमेशा के लिए अपने घर में बस जाता है, जिसे शादी के बाद मायका कहा जाता है। ससुराल के प्रति जिम्मेदारी निभाने का यह मतलब नहीं होता कि कोई लड़की अपने माता-पिता या भाई-बहन को भूल जाए।

बड़े शहरों की बात छोड़ दीजिए, कभी छोटे शहर और गांवों की तरफ नजर घुमाइए तब पता चलेगा कि सारी दुनिया वैसी नहीं है, जैसा हम सोचते हैं। आज ऐसी तीन लड़कियों की कहानी आपको बता रहे हैं। नीरू की शादी हुए एक साल से अधिक हो गए लेकिन वह मायके नहीं आ पा रही थी। उसे अपने घर की याद आ रही थी। ऐसा नहीं है कि उसके ससुराल में कोई कमी थी लेकिन नए रिश्ते मिलने से पुराने रिश्ते, वो भी अपने घरवालों को कोई भूल पाता है क्या। वह मां को फोन पर कहती मम्मी घर आना है, मुझे सबकी याद आती है। मैं सबको बहुत मिस करती हूं, लेकिन नीरू की मम्मी जब भी उसकी सासू मां से उसे घर बुलाने की बात करतीं तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती, क्योंकि वह बहुत ज्यादा पाखंडी विचारधारा वाली हैं। नीरू अब उदास रहने लगी, उसका वहां मन नहीं लगता। एक दिन उसे मौका मिला जब वह अपने मायके के पास वाले शहर में होली की शाम पति के साथ आने वाली थी। वह कुछ देरी के लिए ही सही बिना किसी को बताए घर आ गई। घर आते ही उसका चेहरा खिल गया। वह उसी रात ससुराल भी चली गई क्योंकि उसकी सासू मां को बुरा लगता।

संगीता की शादी को 8 साल हो गए। उसकी शादी दिल्ली के एक पॉश इलाके में हुई है लेकिन ससुराल वाले ना जाने किस जमाने में जीते हैं। उसके ससुराल में हर चीज पर पाबंदी है। वह ससुराल में अपने मनपसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती। मायके भी साल में एक बार जाने को मिल जाए वही बहुत है। पति की पोस्टिंग दूसरे शहर में है। वह बताती है कि एक बार मां बीमार थी, तब बिना ससुराल में बताए मैं मां से मिलने गई थी। अगर बताती तो उनसे मिल नहीं पाती। ऊपर से मायके से ससुराल आने पर सब यही देखते कि मां ने विदाई में क्या-क्या दिया है। कुछ कमी लगने पर फिर वही पुरानी बातें कि ये नहीं दिया, ऐसी साड़ी कौन पहनेगा... इसलिए मैंने नहीं बताया। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार मायके जाने पर मैं विदाई में सामान भरकर ससुराल लेकर जाऊं। वो भी जब वे परेशान हों।

दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली प्रेरणा का मायका मेरठ में है। कई बार वह शनिवार को हाफ-डे लेकर मायके जाती, वहां अपने माता-पिता से मिलती फिर ससुराल के लिए निकलती और रोज की तरह समय घर पहुंच जाती। ससुराल में वह नहीं बताती कि वह मां-पापा के पास गई थीं। इस बारे में उनका कहना है कि लड़की जब मायके की दहलीज पार कर ससुराल में कदम रखती है, तो उस घर को ही अपना मान लेती है। उस घर की हर चीज को अपना मानने के लिए हर प्रयास करती है, लेकिन जब सासू मां बहू को बेटी नहीं मान पातीं और परिवार में बहू को वो स्नेह नहीं मिल पाता। साथ ही उसके मायके में जाने पर पाबंदियां लग जाती हैं। यही वो वजहें हैं जो हम बेटियों को यह राह चुनने पर मजबूर करते हैं। हमें लगता है कि अगर बताकर जाऊंगी तो मुझ पर नजर रखी जाएगी। रोका-टोका जाएगा।

वहीं मायके से हमसे पूछताछ होगी कि क्या दिया तेरी मां ने हमारे लिए। हम बेटियां अपने पेरेंट्स पर हर समय ये बेवजह बोझ नहीं पढ़ने देना चाहतीं। वहीं शादी के बाद पेरेंट्स को किसी भी तरह की मदद पहुंचाना ससुराल वालों को पसंद नही होता, ऐसे में एक लड़की छिपकर अपना फर्ज निभाती है। असल में शादी के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बहू को मायके की जिम्मेदारी निभाने की छूट देते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह वह अपने घर में ही फंसी रहेगी और ससुराल पर ध्यान नहीं दे पाएगी। कई ऐसे भी मजबूर पिता हैं कि वो कैसे अपनी ही बेटी से मिलने उसके ऑफिस आते थे, क्योंकि बेटी के सुसराल वालों को यह पसंद नहीं था। क्या शादी के बाद पिता का अपनी ही बेटी पर कोई हक नहीं होता, फिर एक पिता क्यों बेटी की सुख-शांति के लिए सब जानते हुए चुप रहता है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

एक शहर में रहकर भी मजबूरी

अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा कि भले कुछ घंटों के लिए सही अगर लड़की का मायका एक शहर में हो तो वह छिपकर अपनों से मिलने जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ससुराल वाले बहू की विदाई नहीं करते और उसे अपने मायके गए हुए सालों बीत जाते हैं। ऐसे में दूर रहते हुए जब भी उसे मौका मिलता है तो वह छुपकर घरवालों से मिलने आ जाती है। शायद आपको लगे कि इस जमाने में ऐसा कौन करता है तो यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी ऐसे लोग हैं जो पुराने ख्यालातों वाले होते हैं। जिनके घर की महिलाओं के लिए पाबंदियां होती हैं। जिनके बिना मर्जी और बिना परमिशन के बहुएं मायके नहीं जा सकतीं। कई लोगों के घरों में तो यह भी तय होता है कि एक साल में कितनी दफा बहू मायके जाएगी। एक तरफ समाज महिला अधिकारों की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। आज देश में कई परिवारों के विखंडन की वजह भी ऐसी पाबंदियां होती हैं।

अपेक्स बैंक

अपेक्स बैंक
म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या.

समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी

- वाहन ऋण
- त्यौहार ऋण
- आवास ऋण
- चिकित्सा ऋण
- व्यक्तिगत ऋण
- परियोजना ऋण
- भ्रमण ऋण
- उपभोक्ता ऋण
- उच्च शिक्षा ऋण
- आभूषणों के तारण पर ऋण
- व्यापारियों को साख-सीमा
- अचल सम्पत्ति के बंधक पर ऋण

क्यों देखें महज सपने, आइये करें उन्हें साकार

केन्द्र/राज्य शासन/शासकीय निगम, मण्डल, बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों/संस्थाओं एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के नियमित कर्मचारियों हेतु उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर

मात्र **8 %** पर ऋण सुविधा उपलब्ध

हमारी अन्य बैंकिंग सेवायें

एनईएफटी | आईएमपीएस | मोबाईल बैंकिंग
आरटीजीएस | एटीएम | लॉकर्स सुविधा

वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज

अपेक्स बैंक की समस्त शाखाओं में आपका हार्दिक स्वागत है।

रौशनदान

पिछले दस दिनों से एक अजीब सी बेचैनी में रागिनी जी रही थी। अपनी भाभी की मां से बहुत गहरा मां-बेटी सा रिश्ता वर्षों पहले बन गया था।

रिश्ते में दिनोंदिन मधुरता और खान-पान के साथ-साथ तोहफों का आदान-प्रदान भी निरंतर लंबे समय तक जारी रहा।

जिंदगी और रिश्तों में भी धूप-छांव होती है। यह वक्त की पाठशाला में जरूर पढ़ाई जाती है।

उसके दोनों बेटे से बेहतर भाभी के भाईयों की शिक्षा हुई।

यहीं से रिश्तों में मधुरता धूमिल होने लगी आपके बच्चे से ज्यादा पढ़ा-लिखा और कमाऊ मेरा बच्चा है।

इस बात को कहने का एक भी अवसर भाभी या भाभी की मां नहीं गंवाती थी। धीरे-धीरे रिश्तों की मधुरता खो गई।

रही सही कसर विधाता ने पूरी कर दी। रागनी अपनी मां की मौत पर बिल्कुल टूट गई।

सभी रिश्तेदारों ने सांत्वना और संवेदनशीलता का परिचय दिया। लेकिन भाभी की मां ने उसे एक फोन भी नहीं किया।

एक टीस सी उठने लगी उसके मन में। जब अपने सुदर्शन भाई का रिश्ता करवाने में रागिनी ने अहम भूमिका निभाई थी तो उन लोगों ने भी उसे बेटी समान प्यार दिया था।

बार-बार यही कहते कि बेटी तो दूर चली गई, पर आप हो पास में, तो बेटी की कमी नहीं महसूस होती है।

वही मां ने, खुद उसकी मां के स्वर्गवासी होने पर एक औपचारिक फोन तक नहीं किया।

नियति को शायद उसकी और परीक्षा लेनी थी। दो साल बाद उसकी भी दुनिया उजड़ गई। भाभी के मायके वालों ने दो शब्द भी सहानुभूति वश नहीं कहे।

उफ्फ क्यों मैं बार-बार पिछली कड़वी बातों को याद करती हूं। आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। मुझे भूलना ही होगा, ऐसा सोचते हुए बेमन से टीवी ऑन कर देखने लगी।

बिटिया कब आकर उसके बगल में बैठ गई उसे पता ही नहीं चला।

मां; आप अपने स्वभाव के प्रतिकूल कुछ भी नहीं कर सकती हैं।

मामी जी का भाई जिंदगी और मौत से लड़कर महीनों बाद घर वापस आया है। क्या आप उसे बधाई और स्वास्थ्य लाभ हेतु शुभकामनाएं नहीं देंगी?

हां; शायद तुम ठीक कहती हो, पर रिश्ता मैंने खराब नहीं किया है, उन्होंने खराब किया है।

भूल गई जब तेरी नानी और तेरे पापा स्वर्गवासी हुए तो उन लोगों ने फोन पर भी संवेदना तक प्रकट नहीं की। लगता है मेरा फोन न. भी उन लोगों ने अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट से हटा दिया है।

मां वह सब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना कहूंगी कि रिश्ता रखो या नहीं रखो, पर उम्मीद के सारे दरवाजे बंद मत करो।

बेटी की बातों में इंसानियत महसूस हुई। उसने व्हाट्सएप पर शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ हों एवं स्वस्थ होकर घर वापस आने का बधाई संदेश भेजकर खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगी।

सच में सारे दरवाजे भले ही बंद हो जाएं, पर रिश्तों में एक छोटा सा रौशनदान जरूरी है।

बिटिया के हल्के से प्रयास से रिश्तों का रौशनदान खुल गया।

- आरती रॉय

आभासी रिश्ते

अब रोज दुआ सलाम होती है
मिलता कोई नहीं
फिर भी रोज बात होती है
इबादत और दुआओं के न जाने
न जाने कितने लफ्ज मिलते हैं
दुनियाभर के फूल अब रोज
मेरे फोन में खिलते हैं
सिमट गए रिश्ते इन तक अब
कोई घर नहीं आता है
बस फारवर्ड मैसेजेस के जरिए
अपनी बात कह जाता है
आभासी दुनिया के रिश्ते वैसे
खुशियां भी दे जाते हैं
अब मेरी सालगिरह पर
हजारों संदेसे आते हैं
सुख-दुख चाहे जो हो
अब कोई नहीं आता है
एक मैसेज भेजकर वो
फर्ज से निजात पाता है
अजनबियों से बने ये आभासी
ये रिश्ते भी खास हैं
बिना मिले नजदीकी हो जाते
बड़े मजे की बात है
अकेलेपन की ऊब से
एक राहत सी दिलाते हैं
दूर कहीं सुंदर सपनों सी
एक दुनिया ये बनाते हैं
खो गए इन सबमें इतना
असल संवेदना अब रोती है
पर इन आभासी रिश्तों में
अब रोज दुआ सलाम होती है।

चंद सांसें

भरा-पूरा परिवार। पोता-पोती के साथ पूरे दिन धमाचौकड़ी मचाती दादी नीरा। सभी को मन से स्नेह देने वाली बीमारी की चपेट में आ जाती है। घर के एक कमरे में बंद, लाचार।

'बहू जरा सुनो।'

बार-बार आवाज लगाती पर...! आवाज दरवाजे से टकरा फिर वहीं ठहर जाती।

थोड़ी देर बाद एक आवाज उनके कानों में पड़ी...

'मम्मी जी खाना व दवाईयां बाहर रख दी हैं। मैं यहां से चली जाऊं तभी लीजिएगा।' आवाज बंद!

किसी तरह उठना लकड़ी के सहारे से गेट तक पहुंच, खाना अंदर लेकर मेज पर रख। पूजा कर मुंह बिटार फिर चादर तान लंबी सांस खींच शांत हो जाना। यही रोज का रूटीन नीरा का रह गया था।

भगवान से अनगिनत प्रश्न ही प्रश्न 'क्यों मैं? क्यों यह सब? क्यों नहीं मेरी बाकी जिंदगी एक जरूरतमंद को? मैं भारी सब पर? मेरा जीवन अब व्यर्थ, मैंने अगर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म किए हों तो उनका मूल्य आज हे भगवान मैं आपसे मांगती हूं।'

कह अपनी चंद सांसों को समेटती दूसरी दुनिया में विचरण करती। न जाने कब इस भार वाली जिंदगी से बाहर निकल अपने को खुश देखती आज खुली हवा में सांस ले रही थी!

- नूतन गर्ग

विवादों के अखाड़े का पहलवान

छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुशील कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। सुशील से विवाद की वजह से ही ओलिंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले बजरंग पूनिया और कई रेसलिंग कोच छत्रसाल स्टेडियम छोड़कर चले गए। नरसिंह यादव और सुशील का विवाद भी भारतीय कुश्ती में चर्चित रहा। 2018 में नेशनल ट्रायल्स के दौरान पहलवान प्रवीण राणा और उसके भाई के साथ मारपीट के आरोप में भी सुशील पर केस दर्ज हुआ था।

2016 रियो ओलिंपिक के लिए 74 किलो वेट में नरसिंह यादव और 2 बार के ओलिंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार दावेदार थे। सुशील ओलिंपिक क्वालिफायर्स के ट्रायल में हिस्सा नहीं ले पाए। इसके बाद नरसिंह को ओलिंपिक क्वालिफायर्स इवेंट के लिए भेजा गया। नरसिंह ने अपनी प्रतिभा से कोटा हासिल भी कर लिया। नेशनल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक जो खिलाड़ी जिस वेट में कैटेगरी में कोटा हासिल करता है, वही ओलिंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करता है। सुशील चाहते थे कि वे दो बार के ओलिंपिक मेडलिस्ट हैं, इसलिए उन्हें जाने का मौका दिया जाना चाहिए। वे फिर से ट्रायल कराने को लेकर कोर्ट भी गए, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

इसके बाद नरसिंह ने सोनीपत में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग शुरू कर दी। ओलिंपिक से 10 दिन पहले नरसिंह की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की ओर से डोपिंग के लिए भेजा गया सैंपल पॉजिटिव आया। हालांकि, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, लेकिन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने न सिर्फ ओलिंपिक में उन्हें भाग लेने से रोक दिया, बल्कि 4 साल के लिए बैन भी कर दिया। इस मामले में नरसिंह भी खुलकर सामने आए और उन्होंने सुशील पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सुशील के इशारे पर उन्हें डोपिंग में फंसाया गया। उनका आरोप था कि सोनीपत में ट्रेनिंग के दौरान सुशील के इशारे पर ही उनके खाने में कुछ मिलाया गया। इस मामले में प्रधानमंत्री के पहल पर मामले के लिए जांच कमेटी भी गठित की गई थी। वहीं, नरसिंह को डोप में फंसाने के बाद भी सुशील ओलिंपिक में नहीं जा सके थे। इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन ने नरसिंह की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को कोटा देने से इनकार कर दिया था।

सुशील का नाम साल 2017 में रेसलर प्रवीण राणा के साथ मारपीट के मामले में भी आया था। 2017 में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ट्रायल किया गया था। इस ट्रायल में सुशील का मुकाबला उभरते रेसलर प्रवीण राणा के साथ था। सुशील के समर्थकों ने प्रवीण और उनके भाई के साथ मारपीट की थी। प्रवीण और उनके भाई ने आरोप लगाए थे कि सुशील के इशारे पर ही मारपीट की गई थी। इस मामले में केस भी दर्ज हुआ था।

लंदन ओलिंपिक में सुशील के साथ देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले योगेश्वर के साथ भी उनका विवाद सामने आया। योगेश्वर छत्रसाल स्टेडियम में ही ट्रेनिंग करते थे। सुशील के साथ विवाद होने की वजह से उन्होंने लंदन ओलिंपिक के बाद छत्रसाल स्टेडियम छोड़ दिया था। योगेश्वर के अलावा सुशील के खास रहे पहलवान जीतेंद्र कुमार और प्रवीण ने भी छत्रसाल स्टेडियम छोड़ दिया था। जीतेंद्र और प्रवीण दोनों 74 किलो वेट में ही लड़ते थे और सुशील को आदर्श मानते थे। ये दोनों ही पहलवान सार्वजनिक रूप से सुशील का पैर छूते थे। इनके अलावा वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीत चुके पहलवान बजरंग पूनिया भी विवाद के कारण छत्रसाल स्टेडियम को छोड़कर चले गए थे। पूनिया टोक्यो ओलिंपिक के लिए कोटा हासिल कर चुके हैं।

2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुए ट्रायल में सुशील पर पहलवान जीतेंद्र को जान-बूझकर आंख पर घूंसा मारने का आरोप लगा था। 2019 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए ट्रायल में फाइनल में जीतेंद्र का मुकाबला सुशील से था। सुशील ने कुश्ती के दौरान पहले जीतेंद्र की अंगुली को मरोड़ दिया, फिर उनकी बाई आंख पर घूंसा मारा। जीतेंद्र ने तब न्यूज एजेंसी को बताया था कि इससे उन्हें कुछ देर तक दिखना बंद हो गया था। हालांकि, चोट लगने के बाद भी वे इस मुकाबले में सुशील से अंत तक लड़ते रहे। सुशील का विवाद न केवल खिलाड़ियों के साथ रहा है, बल्कि उनके व्यवहार से तंग आकर कई कोच भी छत्रसाल स्टेडियम को छोड़कर चले गए। लंदन ओलिंपिक के बाद कोच रामफल छत्रसाल स्टेडियम छोड़कर चले गए थे। वहीं, 6 महीने पहले सुशील के खास माने जाने वाले कोच वीरेंद्र सिंह ने भी विवाद की वजह से सुशील से दूरी बना ली। वह दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर से सटे एक गांव में अपनी एकेडमी चला रहे हैं।

सुशील कुमार का नाम उप्र के नामी बदमाश सुंदर भाटी के साथ भी जुड़ा था। सुशील ने दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर टोल टैक्स वसूलने का ठेका दिल्ली नगर निगम से लिया था। सुशील पर आरोप था कि उन्होंने यहां पर टोल वसूलने का जिम्मा गैंगस्टर सुंदर भाटी को सौंपा है।

● **आशीष नेमा**

‘हीरा-मंडी’ में मुजरा करेंगी माधुरी!

बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस और डांसर्स में शुमार माधुरी दीक्षित एक बार फिर संजय लीला भंसाली के प्रोजेक्ट के लिए मुजरा कर सकती हैं। भंसाली नेटफ्लिक्स की वेबसीरीज हीरा मंडी के लिए तवायफों की कहानी पर काम कर रहे हैं। भंसाली को भव्य चीजों के लिए याद किया जाता है। बड़े और महंगे सेट्स के साथ डांस उनके प्रोजेक्ट का सबसे जरुरी हिस्सा होता है।

भंसाली हीरा मंडी को भी भव्य बनाने की कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि माधुरी दीक्षित का भी इसमें एक मुजरा हो। इससे पहले माधुरी, शरत चंद्र की कहानी पर बनी भंसाली की ही देवदास में चंद्रमुखी का किरदार निभा चुकी हैं। चंद्रमुखी एक तवायफ का किरदार है। देवदास में भंसाली ने माधुरी की डांस स्किल का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। मार डाला... और काहे छेड़ मोहे... पर माधुरी का डांस नंबर आजतक लोग नहीं भूले हैं। भंसाली अब देवदास की तरह हीरा मंडी में भी माधुरी के डांस का जादू दिखाना चाहते हैं। यदि सूत्रों पर भरोसा किया जाए तो माधुरी और भंसाली एक बार फिर साथ आ सकते हैं। भंसाली ने हीरा मंडी के लिए माधुरी को लगभग ले लिया है। इसे बहुत भव्य और बड़े बजट में बनाया जा रहा है। वैसे हीरा मंडी के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को लिया गया है। लेकिन भंसाली इसमें माधुरी का एक खूबसूरत मुजरा प्लान कर रहे हैं जिसे बड़े पैमाने पर शूट करने की योजना है। माधुरी भी इच्छुक बताई जा रही हैं। भंसाली पहले हीरा मंडी को फिल्म के रूप में बनाना चाहते थे। लेकिन बाद में उन्होंने इसे वेबसीरीज के रूप में बनाने का फैसला किया। वैसे भंसाली, आलिया भट्ट को लेकर गंगूबाई काठियावाड़ी बना रहे हैं। गंगूबाई मुंबई के रेडलाइट में रहने वाली एक सेक्स वर्कर थीं। उन्होंने सेक्स वर्कर्स के अधिकार की आवाज उठाई। फिल्म लगभग बनकर तैयार है। इसे इसी साल रिलीज करने की तैयारी है।

चर्चाओं में क्यों है रामगोपाल वर्मा की फिल्म डेंजरस?

रामगोपाल वर्मा (रामू) ने तीन दशक के कैरियर में कई फिल्में बनाई हैं। इसमें सिनेमा की प्रतिनिधि फिल्में भी शामिल हैं जिन्होंने बॉलीवुड में नई चीजों की शुरुआत की। रामू इस साल डेंजरस लेकर आ रहे हैं। डेंजरस का ट्रेलर 13 मई को रिलीज हुआ था। इसके सामने आते ही रामू और उनकी फिल्म की चर्चा है।

दरअसल, डेंजरस बहुत बोल्ड टॉपिक पर आधारित है। बिकनी, किसिंग सीन्स की भरमार है। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के बीच प्रेम है। ऐसी लड़कियां जिन्हें पुरुषों से नफरत है। नफरत क्यों है यह फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेस्बियन प्रेम और उसके आसपास के अपराध पर बुनी डेंजरस को रामू देश की पहली लेस्बियन प्रेम कहानी बता रहे हैं। इसे 12 जून को रिलीज किया जाना है। डेंजरस का ट्रेलर देखकर किसी तरह की कहानी तो समझ में नहीं आती। जो एक चीज समझ में आती हैं वो है लेस्बियन लव स्टोरी के नाम पर बिना मतलब के उत्तेजक सीन्स की भरमार। पूल, बीच और बेडरूम के लव मेकिंग सीन्स किसी ब्लू फिल्म का हिस्सा नजर आते हैं। बीच-बीच में खून खराबा भी नजर आता है।

आरआरआर ने बिना रिलीज कमा लिए 300 करोड़ से ज्यादा!

एसएस राजमौली की पीरियड एक्शन ड्रामा आरआरआर रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बनाने लगी है। जूनियर एनटीआर, रामचरन, आलिया भट्ट, ओलिविया मोरिस और अजय देवगन की भूमिकाओं से सजी आरआरआर इस साल रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म है। निर्माण और रिलीज पर कोरोना का बहुत असर पड़ा मगर ये अब तैयार है। सबकुछ ठीकठाक रहा तो अक्टूबर में दर्शक इसे देख सकेंगे। राजमौली के क्लास और सक्सेस रेट की वजह से आरआरआर से कारोबारियों को बिजनेस की बड़ी उम्मीदे हैं। मेकिंग प्रोसेस में ही इसके राइट्स खरीदने की होड़ दिख चुकी है। लेकिन हाल ही में सलमान खान की राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के राइट्स खरीदने वाले जी ग्रुप ने सबको पीछे छोड़ दिया है। पिंकविला ने एक रिपोर्ट में बताया कि जी ग्रुप ने रिलीज से पहले ही 325 करोड़ रुपए में आरआरआर की सभी भाषाओं के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं। कारोबारी जयंतीलाल गढ़ा ने फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स जी को ट्रांसफर कर दिए हैं। किसी फिल्म की रिलीज से पहले ये देश की सबसे बड़ी डील है।

विभीषण की सरकार

मंत्रिमंडल का गठन, समाज के सभी वर्गों को उनका स्थान दिलाना, बेरोजगारी की समस्या को सुलझाना, कानून व्यवस्था को सुधारना, जगह-जगह श्रीराम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान जी की मूर्तियों का अनावरण करना, नगरों एवं विश्वविद्यालयों के नाम बदलना, जनता के मन से कुंभकरण एवं रावण के आतंक को मिटाना आदि कार्य भी विभीषण की प्रमाणित सूची में सबसे आगे थे।

श्रीराम और रावण के बीच कांटे की टक्कर हुई। काफी समय तक यह अनुमान लगाना कठिन था कि इस रण में कौन विजयी होगा। एक बड़े रोमांचक मुकाबले में अंततः विजय श्रीराम की हुई। भारतवर्ष के सभी कवियों और गीतकारों ने युद्ध का अद्भुत वर्णन किया है। विजेता के पक्ष में तथा हारने वाले के विपक्ष में कई समाचार पत्रों में लेख भी छपे। लोगों ने रामचंद्र की विजय को एक ऐसी विजय के रूप में परिभाषित किया जिससे आने वाले समय की गति का निर्धारण होना था। यह अंधकार पर उजाले की विजय थी! यह अधर्म पर धर्म की विजय थी! असुरों पर सुरों की विजय थी! पाकिस्तान पर भारत की विजय टाईप थी।

लंका देश के कोलंबो नामक ग्राम में एक गरीब किसान वास करता था। उसके पास दो बीघा जमीन थी जिसपर वह खेती करता था। सरकार को कर देने के बाद उसके पास इतना बच जाता था कि सालभर उसे भोजन के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इधर इस युद्ध के कारण रावण सरकार ने एक सुरक्षा टैक्स अलग से लगा दिया था जिसकी वजह से किसान की हालत खराब थी। युद्ध समाप्त हुआ, रावण के हाथ से सत्ता छिटक कर विभीषण के हाथों में आ गई। विभीषण ने युद्ध से पहले ही श्रीराम से गठबंधन कर लिया था। यह तय हुआ था कि लंका का राजा विभीषण बनेगा और समुद्र सेतु पर गुजरने वाले वाहनों से जो टैक्स मिलेगा वह अयोध्या भेजा जाएगा। किसान को ऐसा लगता था कि विभीषण के राजा बनते ही सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा।

विभीषण के समर्थक गांव-गांव घूमकर विभीषण के गुणों का गुणगान करते रहते थे। किसान ने ऐसे ही किसी से सुना था कि एक बार विभीषण राजा बन जाए तो उसके गांव में स्कूल, अस्पताल और पक्की सड़क भी बन जाएगी। गांव के बाहर जो शुगर मिल, मिल मालिकों एवं रावण सरकार के बीच गन्ने को समर्थन मूल्य के मुद्दे की वजह से पिछले कई बरसों से बंद चल रही थी, वह चालू हो जाएगी। किसान को लगता था कि एक बार मिल चल पड़े तो शायद उसका आवारा लड़का भी वहां नौकरी पा जाए तथा भले मानुस का जीवन बिताए। मन ही मन वह भी यह चाहने लगा था कि युद्ध में श्रीराम की ही विजय हो।

जब विभीषण ने सत्ता संभाली तो लंका की हालत दयनीय थी। एक तो हनुमान ने नगर भर को अग्नि के सुपुर्द करके बड़े-बड़े भवनों एवं अट्टालिकाओं को ध्वस्त कर दिया था वहीं दूसरी ओर इस असमय लड़ाई से राज्य की अर्थव्यवस्था की कमर भी टूट गई थी। विभीषण के सामने रावण के अनेक वर्षों के शासन में हुई गड़बड़ियों का पता लगाने की चुनौती भी थी। लंका में विभीषण राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह भी आवश्यक था कि राज्य की सेना को मजबूत किया जाए। वानरों के हाथों मिली पराजय से लंका के वीर भीतर तक टूट गए थे। उनके मनोबल को एक बार पुनः ऊंचा उठाने के लिए नए अस्त्रों-शस्त्रों एवं तकनीक का निर्यात भी आवश्यक था।

मंत्रिमंडल का गठन, समाज के सभी वर्गों को उनका स्थान दिलाना, बेरोजगारी की समस्या को सुलझाना, कानून व्यवस्था को सुधारना, जगह-जगह श्रीराम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान जी की मूर्तियों का अनावरण करना, नगरों एवं विश्वविद्यालयों के नाम बदलना, जनता के मन से कुंभकरण एवं रावण के आतंक को मिटाना आदि कार्य भी विभीषण की प्रमाणित सूची में सबसे आगे थे।

इन सभी कार्यों के लिए धन चाहिए था। सुग्रीव पार्टी के वानर तो सब लूटकर ही गए थे, श्री राम भी पुष्पक विमान अपने साथ ले गए नहीं तो उसी को राजा महाराजाओं को किराए पर देकर कुछ कमाई की जा सकती थी। सागर सेतु से एकत्रित होने वाली चुंगी भी अयोध्या भेजनी पड़ती थी। नल और नील युद्ध के बाद यहीं रुककर पुल की व्यवस्था देख रहे थे तथा उनके रहते इस खेल में धांधली संभव नहीं थी। रावण की वजह से जो हफ्ता वसूली होती थी वह भी अब समाप्त हो गई थी। तो कुल मिलाकर माहौल कुछ ऐसा था कि धन की आवश्यकता थी और धनोत्पादन के सभी मार्ग एक-एक करके सिमटते जा रहे थे।

ऐसे में विभीषण के सलाहकारों ने आम जनता पर अतिरिक्त कर लगाकर इस समस्या से निपटने का प्लान बनाया। जनता पर बिजली, पानी, घर, क्रय-विक्रय तथा इनकम टैक्स तो पहले से ही था सुरक्षा टैक्स को भी बरकरार रखा गया तथा अब कुछ नए टैक्स भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। किसान एवं आम जनता सरकार के इस फैसले से खासी क्षुब्ध हुई। किसान को ऐसा लगा मानो उसके साथ विश्वासघात हुआ हो। गांव के जितने लफंगे थे वे अब भी आवारा घूम रहे थे, ना तो मिल खुल रही थी, ना सड़क बन रही थी। इतना जरूर हुआ था कि सरपंच जी का भवन अब दुमंजिला हो रहा था तथा उनका पुत्र मर्सडीज नामक रथ विदेश से ले आया था। किसान के लिए रावण राज और विभीषण की सरकार में कोई फर्क नहीं था।

● **अभिनव शुक्ल**

Science House Medicals Pvt. Ltd.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbpl@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

'वनवासी समुदाय की आर्थिक उन्नति एवं शोषण से मुक्ति हेतु कृत संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार'

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

32 वनोपजों के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जिला यूनियनों द्वारा निर्धारित अपनी दुकानों पर

लघु वनोपज के नाम	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु. प्रति कि.ग्रा.)
अचार गुठली	130
बहेड़ा	25
हर्रा	20
बेलगूदा	30
चकोड़ा बीज	20
शहद	225
करंज बीज	40
लाख कुसमी	275
लाख रंगीनी	200
महुआ फूल	35
महुआ गुल्ली	35
नीम बीज	30
नागरमोथा	35
साल बीज	20
जामुन बीज	42
आंवला गूदा	52

> न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा से हमारे वनवासी समुदाय को उनके अथक परिश्रम से संग्रहित वनोपजों का उचित मूल्य मिलेगा। मध्यप्रदेश सरकार के इस कदम से उनकी आर्थिक उन्नति की राह खुलेगी और वे सबके साथ कदम मिला कर आगे बढ़ सकेंगे।
>
> – शिवराज सिंह चौहान

लघु वनोपज के नाम	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु. प्रति कि.ग्रा.)
मार्किंग नट (भिलावा)	09
अनन्त मूल	35
अमलतास बीज	13
अर्जुन छाल	21
गिलोय	40
कोंच बीज	21
कालमेघ	35
बायबडंग बीज	94
धवई फूल	37
वन तुलसी पतियां	22
कुटज (सूखी छाल)	31
मकोय (सूखे फल)	24
अपंग पौधा	28
इमली बीज सहित	36
सतावरी	107
गुड़मार	41

मध्यप्रदेश वन विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल

D19065/21